3 राजधानी
डीयू के कई कोर्सों की फीस बढ़ी

6 अभिमत
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार

11 विदेश
चीनी विदेश मंत्री से मिले जयशंकर

12 स्पोर्ट्स
तुषारा भारत के खिलाफ टी20 शृंखला से बाहर

RNI NO.DELHIN/2012/48369
वर्ष 12 अंक 257
नई दिल्ली, शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

राष्ट्रपति मुर्मू शिक्षिका की भूमिका में आईं नजर

राष्ट्रीय-10

पीएम का दौरा, जम्मू कश्मीर हाईअलर्ट पर

मोहित कंडारी। जम्मू/नई दिल्ली

द्रास में शुक्रवार को 25वें कारगिल विजय दिवस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट की स्थिति में रखा गया है। हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद इस क्षेत्र में पीएम की यह पहली यात्रा होगी और इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी में कुछ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें भी होंगी, जिनमें से दो की अध्यक्षता खुद पीएम करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, जो बृहस्पतिवार सुबह श्रीनगर पहुंचे, ने घुसपैठ विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल बलों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के साथ आगे के इलाकों का दौरा किया।

चिनार कोर की अग्रिम चौकियों का निरीक्षण करते हुए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान नियंत्रण रेखा पर भी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।

बाद में सेना प्रमुख व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए कारगिल के लिए रवाना हुए। पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट जिले के एक गांव में सात संदिग्ध आतंकवादियों को देखे जाने के बाद जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। एहतियात के तौर पर जम्मू क्षेत्र और राजमार्ग के किनारे स्थित सेना प्रतिष्ठानों के कई स्कूलों को 29 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। संदिग्धों का पता लगाने के लिए कठुआ (जम्मू) और पठानकोट के सीमावर्ती इलाकों में सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया गया। अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान, प्रधानमंत्री वस्तुत: शिंकुन ला सुरंग परियोजना का पहला विस्फोट भी करेंगे। शिंकुन ला सुरंग परियोजना में 4.1 किमी लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निमू - पदुम - दारचा रोड पर लगभग (शेष पेज 9)

ममता के आश्रय देने संबंधी बयान पर बांग्लादेश ने जताई आपत्ति

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बृहस्पतिवार को ढाका से एक नोट प्राप्त होने की पुष्टि की, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस टिप्पणी पर आपत्ति व्यक्त की गई है, जिसमें उस देश में हिंसक झड़पों से प्रभावित लोगों को आश्रय देने की पेशकश की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने इससे पहले देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के लोगों को 'आश्रय' की पेशकश करने की बनर्जी की हालिया टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने बनर्जी की टिप्पणियों को अस्वीकार करते हुए कहा कि जो मामले संघ को किसी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं, वे केंद्र सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार हैं। कोलकाता में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने संबोधन में बनर्जी ने हिंसा प्रभावित बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि वह पड़ोसी देश के संकटग्रस्त लोगों के लिए पश्चिम बंगाल के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें आश्रय प्रदान करेंगी। बांग्लादेशी मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि ढाका ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से नई दिल्ली को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की टिप्पणियों पर अपनी नाराजगी से अवगत कराया है। (शेष पेज 9)

महाराष्ट्र में बारिश का कहर, पुणे में चार की मौत

- मुंबई और पुणे में स्कूल-कॉलेज में छुट्टियां, कई घरों और आवासीय सोसाइटियों में भरा पानी

पायनियर समाचार सेवा। पुणे/मुंबई

मुंबई में बृहस्पतिवार को पानी भरे रास्तों से गुजरते लोग।

महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश ने कहर बरपाया, जहां बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जबकि शहर के निचले इलाकों में कई घरों और आवासीय सोसाइटी में पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को निकाला जा रहा है। पड़ोसी मुंबई में भी लगातार बारिश हो रही है और आईएमडी ने मुंबई के आसपास के सभी शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और पुणे प्रशासन ने सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए छुट्टी की घोषणा की है। बारिश ने ठाणे के अधिकांश हिस्सों को भी प्रभावित किया, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई और अंबरनाथ और कुछ अन्य क्षेत्रों में बचाव कार्यों की आवश्यकता पड़ी। भारी बारिश के बीच ठाणे जिले के बारवी बांध में घुसने से दो लोगों के मरने की आशंका है।

पुणे में सिंहगढ़ रोड के एकता नगर में सेना की टीमें तैनात की गई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पुणे जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया और लोगों से सावधानी बरतने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिले के अधिकांश हिस्सों में स्कूलों और कॉलेजों ने छुट्टी घोषित कर दी है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फड़नवीस ने मुंबई, ठाणे और पुणे शहरों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया, जहां अत्यधिक भारी बारिश हो रही है। पुणे शहर और वेल्हा, मुलशी, भोर तालुका सहित जिले के अन्य हिस्सों और खडकवासला सहित कई बांधों के जलग्रहण क्षेत्रों में बुधवार रात से लगातार बारिश हो रही है। पानी छोड़े जाने और भारी बारिश से स्थिति बिगड़ गई लेकिन राहत तंत्र की तैनाती पहले ही कर दी गई और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।

पुणे के जिला कलेक्टर सुहास दिवसे ने कहा कि खडकवासला बांध के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के मद्देनजर जलाशय से पानी छोड़ा गया है। चूंकि खड़कवासला बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, इसलिए 35,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है और यह बढ़कर 45,000 क्यूसेक हो जाएगा। पानी छोड़े जाने के कारण, मुथा नदी के किनारे कई निचले इलाकों में बाढ़ देखी गई। प्रशासन ने कहा, एनडीआरएफ की टीमों को 18 स्थानों पर तैनात किया गया है, जबकि एसडीआरएफ की छह टीमें मुंबई के कुर्ला और घाटकोपर के साथ-साथ ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा और सांगली में तैनात हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस बीच, जिले के लोनावाला हिल स्टेशन के पास मालावली इलाके में रिसॉर्ट्स और बंगलों में बाढ़ के कारण फंसे 29 पर्यटकों को बुधवार शाम को निकाल लिया गया। बृहस्पतिवार सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच मुंबई के कई इलाकों में 100 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। बीएमसी अधिकारी ने कहा कि आईएमडी ने मुंबई शहर और पड़ोसी ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिन के दौरान कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। महाराष्ट्र के तटीय कोंकण क्षेत्र में, आईएमडी ने बृहस्पतिवार के लिए रत्नागिरी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट (भारी से बहुत भारी वर्षा) और सिंधुदुर्ग जिले के लिए पीला अलर्ट जारी किया है।

राज्यों के पास खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

पीटीआई। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कोई कर नहीं है और संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधाई अधिकार है। इस फैसले से झारखंड और ओडिशा जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उन्होंने उच्चतम न्यायालय से केंद्र द्वारा खदानों और खनिजों पर अब तक लगाए गए हजारों करोड़ रुपए के करों की वसूली पर फैसला करने का आग्रह किया था। राज्यों ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि केंद्र से करों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए फैसले को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हालांकि दलीलों का कड़ा विरोध किया। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र और

राज्यों से इस पहलू पर लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा और कहा कि वह 31 जुलाई को इस मुद्दे पर फैसला करेगी। उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर नहीं है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपने और पीठ के सात न्यायाधीशों के फैसले को पढ़ा जिसमें कहा गया कि संविधान की दूसरी सूची की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत संसद को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। बहुमत के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वर्ष 1989 में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया वह फैसला सही नहीं है जिसमें कहा गया था कि खनिजों पर रॉयल्टी कर है। (शेष पेज 9)

बजट पर चर्चा के बजाय पीएम पर निशाना साध रहा विपक्ष: रिजिजू

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केंद्र ने बृहस्पतिवार को विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए तर्क दिया कि उन्होंने दस्तावेज़ के बारीक पहलुओं पर बोलने के बजाय संसद में केंद्रीय बजट पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का सहारा लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जिस तरह से कुछ विपक्षी नेताओं ने अपने भाषण दिए, वह सदन का अपमान करने और बजट सत्र की गरिमा को कम करने जैसा है। रिजिजू ने एक प्रेस वार्ता में कहा, आइए हम लोगों के जनादेश का सम्मान करें। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार जनादेश दिया है। अगर कोई लोगों के फैसले का अपमान करने की कोशिश करता है तो उन्हें चुनाव में दंडित किया जाएगा।

उनकी यह टिप्पणी विपक्ष के इस दावे के एक दिन बाद आई है कि केंद्रीय बजट गैर-एनडीए शासित राज्यों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री पर अस्थिर और कमजोर गठबंधन सरकार चलाने का आरोप लगाया। बुधवार को लोकसभा में 2024-25 के बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान, विभिन्न विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर प्रमुख सहयोगियों जेडी-यू और टीडीपी को रियायतें देने का आरोप लगाया, जो क्रमश: बिहार और आंध्र प्रदेश पर शासन करते हैं, ताकि सरकार सुनिश्चित कर सके। अपने गठबंधन सहयोगियों से कोई बाधा नहीं आती। रिजिजू ने कहा कि चुनाव खत्म हो गए हैं और अब ध्यान विकसित भारत की दिशा में काम करने और केंद्रीय बजट पर रचनात्मक चर्चा करने पर होना चाहिए। रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि चुनाव खत्म हो गए हैं और अब समय राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर देश के लिए मिलकर काम करने का है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदस्यों से सम्मान बनाए रखने और ऐसी टिप्पणी नहीं करने को कहा (शेष पेज 9)

तकनीक से परीक्षा सुरक्षा बढ़ाएगा यूपीएससी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

यूपीएससी और सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षाओं सहित इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं से संबंधित कई विवादों के बाद, आयोग अब आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण, चेहरे की पहचान प्रणाली और एआई जैसे उन्नत तकनीकी समाधानों को शामिल करके अपने परीक्षा सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यह बदलाव, यूपीएससी परीक्षाओं की अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से, हाल ही में एनईईटी जैसी कुछ राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में धोखाधड़ी के व्यापक आरोपों के बाद किया गया है। आयोग ने एक वास्तविक समय उपस्थिति निगरानी प्रणाली का प्रस्ताव दिया है जिसमें यह पुष्टि करने के लिए जीपीएस निर्देशांक शामिल हैं कि नामांकन निर्दिष्ट पाली के भीतर होता है।

यूपीएससी निर्दिष्ट करता है कि एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड, जिसमें उम्मीदवार का रोल नंबर शामिल है, को एप्लिकेशन डेटाबेस से उम्मीदवार की जानकारी स्वचालित रूप से पुनर्प्राप्त करने के लिए स्कैन किया जाना चाहिए। यदि क्यूआर कोड स्कैन नहीं किया जा सकता है, तो उम्मीदवार का रोल नंबर एडमिट कार्ड से मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। यूपीएससी देश भर में विभिन्न केंद्रों और स्थानों पर उम्मीदवारों और परीक्षा कर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रिकॉर्डिंग और लाइव प्रसारण क्षमताओं के साथ सीसीटीवी/वीडियो निगरानी लागू करने की भी योजना बना रहा है। सेवा प्रदाता को प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी रंगीन कैमरे स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जिससे प्रत्येक 24 उम्मीदवारों के लिए कम से कम एक कैमरा सुनिश्चित किया जा सके। प्रवेश और निकास द्वारों और नियंत्रण कक्षों पर भी कैमरे लगाए जाएंगे जहां परीक्षा से पहले और बाद की संवेदनशील सामग्री संभाली जाती है। यूपीएससी ने अपनी परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से बोलियां मांगी हैं। यह कदम प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर से जुड़े विवाद के बाद उठाया गया है, जिन पर सीएसई में 12 बार उपस्थित होने के लिए जाली दस्तावेज रखने का आरोप है, जो प्रयासों की स्वीकृत संख्या से अधिक है। यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। यूपीएससी ने कहा, आयोग का इरादा उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक विवरणों का मिलान और क्रॉस-चेक करने और परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी, अनुचित साधनों और प्रतिरूपण को रोकने के लिए उम्मीदवारों की विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नवीनतम डिजिटल तकनीक का उपयोग करने का है।

यूपीएससी प्रतिरूपण को रोकने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत डेटा और छवियां सेवा प्रदाता को प्रदान करेगा। इस डेटा का उपयोग परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को सत्यापित करने के लिए आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और चेहरे की पहचान प्रणालियों के लिए किया जाएगा। उम्मीदवारों की पहचान सटीक रूप से सत्यापित हो यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर फिंगरप्रिंट स्कैनर और चेहरे की पहचान करने वाले उपकरण तैनात किए जाएंगे। यूपीएससी भारत सरकार के भीतर समूह ए और समूह बी पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं (शेष पेज 9)

उप्र में पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान

- 23 से 25 अगस्त और 30 व 31 अगस्त को दो-दो पालियों में होगी लिखित परीक्षा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों में लगे लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार द्वारा हाल ही में निरस्त की गई पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा अब 23,24,25 अगस्त एवं 30,31 अगस्त 2024 को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। पेपर लीक के आरोपों के चलते छात्रों की मांग पर यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा निरस्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया था कि यह परीक्षा 6 माह के अंदर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के अनुसार पुन: आयोजित कराई जाए। प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने की प्रतिबद्धता के क्रम में यह कार्यक्रम घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में परीक्षा संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं, जिनमें परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, छद्मनिरूपण रोके जाने आदि के लिए विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19 जून 2024 को जारी किए गए है। यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार आयोजित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा निर्धारित तिथियों में आयोजित की जाएगी। जन्माष्टमी त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है। इन तिथियों को प्रतिदिन 2 पालियों में यह परीक्षा संपन्न कराई जाएगी तथा प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य (शेष पेज 9)

रील बनाने वालों पर दिल्ली मेट्रो का शिकंजा

- रील बनाने समेत अन्य नियमों के उल्लंघन पर 1647 के खिलाफ केस दर्ज

सौम्या शुक्ला। नई दिल्ली

शहर की लाइफ लाइन दिल्ली मेट्रो में रीलर्स पर लगाम कसनी शुरू हो गई है। इन्होंने ट्रेन को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइक और व्यूज के लिए वीडियो बनाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अप्रैल से जून महीने के दौरान मेट्रो परिसर में रील बनाने सहित अन्य नियम उल्लंघन करने को लेकर 1,600 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले इस वर्ष मामलों की संख्या में तीन फीसदी की वृद्धि हुई है। डीएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ रील बनाने को लेकर कितने लोग नामजद किए गए हैं, इसका कोई अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। नियम उल्लंघन की दूसरी घटनाओं में ट्रेन के फर्श पर बैठना और ट्रेन के भीतर खाना खाने समेत अन्य अपराध शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक, मेट्रो रेलवे (परिचालन और रखरखाव) अधिनियम की धारा 59 के तहत 1,647 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान यह संख्या 1,600 रही थी।

आंकड़ों के मुताबिक, डीएमआरसी ने अप्रैल, मई और जून में क्रमश 610, 518 और 519 मामले दर्ज किए जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 528, 485 और 587 रही थी। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने बताया कि इन लोगों पर मेट्रो परिसर में नियमों के उल्लंघन को लेकर मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा, हम अपने तंत्र का इस्तेमाल करते हैं ताकि मेट्रो परिसर में इस तरह की घटनाएं न हों। हमारे यहां दंड का प्रावधान है। अगर कोई मेट्रो परिसर में नियमों का उल्लंघन करता है तो हम उसे दंडित कर सकते हैं। (शेष पेज 9)

राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप

- अशोक हॉल का भी नाम बदला अब कहलाएगा अशोक मंडप

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल (बाएं) और अशोक हाल (दाएं), जिनका नाम अब बदल दिया गया है।

राष्ट्रपति के ऐतिहासिक निवास और कार्यस्थल राष्ट्रपति भवन के परिसर में प्रसिद्ध मुगल गार्डन का नाम बदलकर 'अमृत उद्यान' करने के एक साल बाद इस प्रतिष्ठित इमारत को एक गणतंत्र के रूप में भारत की स्थिति के साथ संरेखित करने और भारत में गहराई से निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों को रेखांकित करने के प्रयास जारी हैं। बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति के इस ऐतिहासिक निवास और कार्यस्थल के दो ऐतिहासिक हॉल दरबार हॉल और अशोक हॉल को क्रमश: गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप नाम दिया गया है।

राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास राष्ट्रपति भवन, राष्ट्र का प्रतीक और देश की एक अमूल्य धरोहर है। बयान में कहा गया, लोगों के लिए इसे और अधिक सुलभ बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के माहौल को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और लोकाचार को प्रतिबिंबित करने वाला बनाने का लगातार प्रयास किया गया है। इसमें कहा गया कि इसी क्रम में राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉल - दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमश: गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रसन्नता है। राष्ट्रपति भवन के मध्य गुंबद के नीचे स्थित दरबार हॉल राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोहों और कार्यक्रम के आयोजन का स्थान है। बयान में कहा गया, दरबार शब्द भारतीय शासकों और ब्रिटिश अदालतों तथा सभाओं को संदर्भित करता है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद दरबार की प्रासंगिकता खत्म गई। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से भारतीय समाज में गहराई से निहित है। गणतंत्र मंडप आयोजन स्थल के लिए एक उपयुक्त नाम है। (शेष पेज 9)

दिल्ली-मेरठ रोड पर दिखने लगा भगवा रंग

बोल बम के जयघोष से लगातार गूंज रहा मार्ग, बच्चे-युवा-बुजर्ग और महिलाएं ला रहें कांवड़

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

श्रावण माह की शिवरात्रि में जलाभिषेक को महज एक सप्ताह रह गया है। ऐसे में दिल्ली-मेरठ रोड पर कांवडियों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। कांवड़ मार्ग पर भगवा कपड़े पहने शिवभक्त हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर बढ रहे हैं। बोल बम के जयघोष से कांवड़ मार्ग लगातार गूंज रहा है। बच्चे, युवा, बुजर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में कांवड लेकर आगे बढ़ रही हैं।

हालांकि अभी एक सप्ताह का समय होने के चलते अभी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुरुग्राम, आगरा, मथुरा आदि शहरों के कांवडियों का आगमन हो रहा है। 27 जुलाई से दिल्ली और आसपास के कांवडियों का आना शुरू हो जाएगा तो वहीं 30 जुलाई से स्थानीय कांवडियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वहीं एक अगस्त से बड़ी संख्या में डाक कांवडिया गुजरेंगे। अकेले गाजियाबाद से ही करीब सौ की संख्या में डाक कांवड़ियां हरिद्वार से जल लेकर दूधेश्वरनाथ मंदिर पहुचेंगे। 22 जुलाई से इस मार्ग से बड़े वाहनों का प्रवेश पहले ही बंद किया जा चुका है। अभी वनवे नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही कांवड़ियों की संख्या में इजाफा होगा, रोड को वाहनों व अन्य लोगों के आगमन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। दिन के समय कांवडियां शिविरा में आराम कर रहे हैं, लेकिन रात के समय बडी संख्या में कांवडिया अपनी कांवड़ लेकर गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं।

उमस और गर्मी की परवाह किए बगैर कांवड़ियां भोले की भक्ति में झूमते हुए पैरों के छालों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। अपने आराध्य देव का जलाभिषेक करने के लिए कांवडियां उत्साहित हैं। मेरठ रोड़ पर बड़ी संख्या में दुकानदार भगवा शिव पताका बेच रहे हैं। हर साल लाखों की संख्या में शिवभक्त कांवड़ लेकर इस रोड से निकलते हैं। जो कांवड़ के साथ-साथ शिव पताका, हनुमान पताका आदि भी लेकर चलते हैं।

इसके चलते मेरठ रोड इन पताकाओं से अटा पड़ा है। छोटे से लेकर बड़े साइज की पताका इन दुकानों पर उपलब्ध हैं। मेरठ रोड पर आरआरटीएस का स्टेशन भी हैं और लगातार वहां काम भी चल रहा है। हालांकि कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर काम रोक दिया जाता है। लेकिन स्टेशन प्रशासन की ओर से मेरठ मार्ग की दिवार पर रेपिड ट्रेन की पेंटिंग बनाई गई है, इसके अलावा एक दिवार को जय श्रीराम और उनकी तस्वीर से पेंट किया गया है। जिसे देखकर रोड़ से गुजरने वाले भी खूब आर्कषित हो रहे हैं। कांवडियों के लिए मेरठ रोड मुख्य मार्ग है। गाजियाबाद जिले की सीमा में ही कांवडियों के लिए दो सौ से भी अधिक कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं।

अभी कांवड़ियों की संख्या कम है लेकिन कई संस्थाओं ने अपने शिविर शुरू कर दिए हैं जहां कांवडिया आराम कर आगे की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। हालांकि अन्य शिविर लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इन शिविरों में कांवड़ियों के आराम करने से लेकर उनके खाने-पीने, नहाने, सोने तक के इंतजाम किए गए हैं। महिला कांवड़ियों के लिए शिविरों में अलग व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा कांवडियों की सेहत को देखते हुए मेडिकल कैंप भी जगह-जगह लगाए गए हैं। कांवड़ियों की यात्रा में कोई समस्या न हो इसके लिए सुरक्षा के चलते मेरठ रोड की एक साइड पर बेरिकेट्स लगा दिए गए हैं।

नोएडा में रोजाना 71 किमी सड़क होगी साफ

नोएडा। तीन नई मशीनों के जरिए नोएडा प्राधिकरण 71 किलोमीटर सड़क की साफ सफाई के लिए इंटीग्रेटेड मैकेनिकल एवं मैन्युअल स्वीपिंग की योजना पर काम कर रहा है। प्राधिकरण की यह योजना सितंबर से धरातल पर उतरेगी। इसमें सबसे बड़ी ख़ासियत यह होगी कि पहली बार शहर के फुटपाथ की धुलाई को भी शामिल किया गया है। प्राधिकरण ने इसके लिए 60 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है। जो भी कंपनी चयनित होगी, उसको पांच साल तक काम करना होगा।

प्राधिकरण के डीजीएम एसपी सिंह ने बताया कि शहर की साफ सफाई के लिए प्राधिकरण ने तैयारी पूरी कर ली है। 71 किलोमीटर एरिया में इंटीग्रेटेड मैकेनिकल एवं मैन्युअल स्वीपिंग शुरू करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया है। पहली बार फुटपाथ की धुलाई की जाएगी। यह काम रात में किया जाएगा। जिस कंपनी को चुना जाएगा वो पांच साल तक संचालन का जिम्मा संभालेगी। अभी जो कंपनी काम कर रही है उसका टेंडर का समय पूरा हो चुका है।

संक्षिप्त समाचार

चोरी के मामले में दो गिरफ्तार। कब्जे से 2 मोबाइल फोन व बाइक बरामद।

दादरी स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की उठाई मांग

नोएडा। जनपद का दर्जा प्राप्त रेलवे स्टेशन दादरी पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष डॉ आनंद आर्य ने रेल मंत्री से मांग की है। आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष डॉ आनंद आर्य ने भारतीय रेल मंत्री से की गई मांग में कहा कि दादरी रेलवे स्टेशन जनपद का सबसे बड़ा स्टेशन है। यहां पर ग्रेटर नोएडा और नोएडा आने जाने वाले लोगों के लिए नजदीक का स्टेशन है। यहां साथ ही जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालय भी है। लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव नहीं होने के चलते यात्रियों को दिल्ली गाजियाबाद के स्टेशनों पर आवागमन करने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे यहां पर एक्सप्रेस ट्रेन रुकनी चाहिए। जबकि दादरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने पर सड़क मार्ग भी बेहतर ढंग से जुड़े हुए हैं।

एक्सप्रेस ट्रेन में चेन पुलिंग के आरोप में यात्री गिरफ्तार

नोएडा। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर भागलपुर से नई दिल्ली जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में दादरी रेलवे स्टेशन के समीप चेन पुलिंग कर दी गई । चेन पुलिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है । पुलिस ने बताया कि भागलपुर से नई दिल्ली के लिए एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 03483 जा रही थी। जब ट्रेन दादरी रेलवे स्टेशन के समीप पहुंची तो ट्रेन में चेन पुलिंग कर दी गई। चेन पुलिंग की सूचना आरपीएफ पुलिस को दी गई तब तक ट्रेन के रुकने पर बिहार के जनपद पटना के गांव आनंद गोला निवासी सुजीत कुमार ट्रेन से उतरकर चल दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह सूरजपुर नोएडा स्थित एक कंपनी में नौकरी करते हैं । और नजदीक होने के चलते चेन पुलिंग की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है ।

स्कूल के कैशियर पर 84 लाख के गबन का आरोप

नोएडा। उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर के थाना सेक्टर 126 में एक स्कूल के ट्रस्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि स्कूल के कैशियर ने छात्रों की फीस स्कूल के खाते में जमा नहीं कराई और 84 लाख रुपए का गबन किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। थाना सेक्टर 126 के प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र बालियान ने बताया कि स्कूल के ट्रस्टी नवनीत काबरा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 128 स्थित स्कूल में छात्रों की फीस के संबंध में वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार उसने स्कूल की प्रधानाचार्या के साथ अकाउंट विभाग में कार्यरत कैशियर किरणपाल सिंह रावत से पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में पता चला कि कैशियर ने छात्रों से फीस के तौर पर जो धनराशि प्राप्त की उसकी फर्जी रसीदें काटी और रुपए स्कूल के खाते में जमा कराने के बजाय अपने पास रख लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कैशियर ने 84 लाख रुपए का गबन किया है। उन्होंने बताया कि रावत 2021 से स्कूल में कैशियर पद पर कार्यरत था और मामला उजागर होने के बाद वह फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सड़क किनारे सो रहे तीन को कैंटर ने कुचला

- नोएडा में दो लोगों की मौत, एक घायल, चालक हुआ फरार

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

सेंट्रल नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में देर रात रोड किनारे सो रहे लोगों को कैंटर ने कुचल दिया, जिसमे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। जिसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। कैंटर चालक मौके से कैंटर लेकर फरार हो गया।

बुधवार रात में लगभग 11:30 बजे थाना बिसरख क्षेत्र के गौर माल के सामने चार मूर्ति की ओर सर्विस रोड पर हाइड्रा एवं रिकवरी वैन के चालक स ?क के किनारे चारपाई पर सो रहे थे। इसी दौरान ईटेडा गोल चक्कर की ओर से सर्विस रोड पर एक तेज रफ्तार कैंटर आया, जो पहले एक ट्रांसफॉर्मर से टकराया और उसके बाद चारपाई में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही चीख पुकार मच गई, जिससे मौके पर दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान पूरन सिंह (30) निवासी ग्राम लहगांव थाना बेवर जनपद मैनपुरी और विनोद (22) निवासी ग्राम ननाखेड़ी थाना उझानी जनपद बदायूं के रूप में हुई। हादसे में श्याम सिंह निवासी ग्राम देवसराय थाना सिकंदराराऊ हाथरस गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला चिकित्सालय से दिल्ली सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनों मृतकों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। वहीं घटना के खुलासे के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द घटना में शामिल कैंटर को बरामद किया जाएगा।

वहीं एक अन्य मामले में थाना दनकौर क्षेत्र में बीती रात को दो लोग सड़क हादसे के शिकार हो गए। बताया जा रहे कि ये लोग हरिद्वार से बल्लभगढ़ जा रहे थे। थाना दनकौर के प्रभारी निरीक्षक मुनेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बल्लभगढ़ के रहने वाले अमित और मोहित नामक दो लोग हरिद्वार से गंगा स्नान करके वापस बल्लभगढ़ जा रहे थे, तभी दनकौर क्षेत्र में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।

स्कूटी सवार दो बच्ची समेत चार घायल

नोएडा। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित सहारा सिटी के सामने छोटा हाथी व स्कूटी की टक्कर हो गई। टक्कर होने पर दो बच्ची समेत चार घायल हो गए । घायलों का उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में लगी है । पुलिस ने बताया कि बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में आदित्य मिश्रा परिवार के साथ रहते हैं । आदित्य मिश्रा अपनी भाभी नम्रता मिश्रा और बेटी अवंतिका व अंविता स्कूटी पर सवार होकर दादरी की तरफ से गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे। जो वह जीटी रोड पर सहारा सिटी के सामने पहुंचे तो छोटा हाथी व स्कूटी की टक्कर हो गई ।

अब आरटीओ में नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट

- बिसाहड़ा में प्राइवेट कंपनी ने बनाया मोटर ट्रेनिंग सेंटर

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल, अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए होने वाले टेस्ट आरटीओ कार्यालय में नहीं होगा।

ये टेस्ट प्राइवेट मोटर ट्रेनिंग सेटर में होगा। ये सेंटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में है। दरअसल, राज्य सरकार के स्तर से सभी जिलों में प्राइवेट मोटर ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए 2023 में आवेदन मांगे गए थे। नोएडा में अब तक 02 मोटर ट्रेनिंग सेंटर जिसमें पहला मैसर्स शिवम मार्बल व दूसरा मैसर्स साई फायर एप्लीकेंस प्राइवेट लिमिटेड के आवेदकों को लेटर आफ इन्टेंट परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी किया गया, जिसमें से मैसर्स शिवम मार्वल मोटर ट्रेनिंग सेंटर दादरी के पास बिसाहड़ा में बन कर तैयार हो गया है। बिसाहड़ा में बने इसी ट्रेनिंग सेंटर में अब होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट। बिसाहड़ा में बने इसी ट्रेनिंग सेंटर में अब होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट। परिवहन आयुक्त ने गुरुवार को इस सेंटर को टेस्ट करने की मान्यता दी गई। इसके साथ 1 अगस्त से ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके निर्देश भी कंपनी को दे दिए गए है। ताकि यहां ड्राइविंग टेस्ट हो सके। इसके अलावा जनपद में कुछ अन्य आवेदक द्वारा प्राइवेट मोटर ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए आवेदन दिया गया है।

Arcil

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल)

विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए

एआरसीआईएल कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई-400 028

शाखा कार्यालय: कार्यालय नं. 1008, 11वीं मंजिल, वेस्टएंड मॉल, डिस्ट्रीक्ट सेंटर, जनकपुरी, पश्चिम नई दिल्ली-110058

वेबसाइट : https://auction.arcil.co.in; CIN-U65999MH2002PLC134884

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 6, 8 और 9 के नियमों को पढ़ते हुए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (सरफेसी एक्ट) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।

सामान्य जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं)/गॅरेन्टर (ओं) /बंधककर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के पास गिरवी रखी/प्रभारित की गई है, विभिन्न एआरसीआईएल ट्रस्टों (''एआरसीआईएल'') के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए (पंजीकृत असाइनमेंट समझौतों के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्ति के असाइनमेंट के अनुसार), को अतिरिक्त ब्याज, शुल्कों और लागत आदि सहित बकाया राशि की वसूली के लिए ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से ''जहां है'', ''जैसा है'', और ''जो कुछ भी है'' और ''बिना किसी समर्थन के आधार पर'' पर बेचा जाएगा, जैसा कि सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 (''रूल्स'') के नियम 6, 8 और 9 के नियमों को पढ़ते हुए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (''एक्ट'') के प्रावधानों के संदर्भ में नीचे बताया गया है।

उधारकर्ता/सह - उधारकर्ता/गॅरेन्टर/ बंधककर्ता के नाम	एलएएन नंबर और विक्रय बैंक	ट्रस्ट का नाम	सरफेसी सूचना की तिथि 12.10.2017 और 22.12.2021 अनुसार बकाया राशि क्रमशः	कब्जे का प्रकार और तिथि	निरीक्षण की तिथि	संपत्ति का प्रकार और क्षेत्रफल	अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य	ई-नीलामी की तिथि और समय
उधारकर्ता : 1. बादल दास 2. देबाश्री दास 3. दुलाल चंद रॉय (गारंटर)	कर्ज खाता क्र. HHLNOD00246904 एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी)	एआरसी आईएल-सीपीएस-IV-ट्रस्ट	रु. 16,62,106/- (रुपए सोलह लाख बासठ हजार एक सौ छह मात्र) 12.10.2017 तक + उस पर अतिरिक्त ब्याज + कानूनी व्यय	वास्तविक कब्जा 16.02.2024 को	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्री होल्ड - 460 वर्ग फीट (निर्मित क्षेत्र)	रु. 1,40,000/- (रुपए एक लाख चालीस हजार मात्र)	रु. 14,00,000/- (रुपए चौदह लाख मात्र)	12.08.2024 को दोपहर 12.00 बजे

नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण: श्रीमती देबाश्री दास के स्वामित्व वाली संपत्ति :
अचल संपत्ति का क्षेत्रफल - 460 वर्ग फीट (निर्मित क्षेत्र) और निम्नानुसार सीमाबद्ध है : पूरी दूसरी मंजिल, आवासीय प्लॉट नंबर 45 में निर्मित, छत के अधिकारों के साथ, जिसका क्षेत्रफल 38.08 वर्ग मीटर और कवर्ड क्षेत्रफल 38.08 वर्ग मीटर है, नवीन पार्क में स्थित है, हदबस्त ग्राम जगोला, तहसील और जिला गाज़ियाबाद - 201010, उत्तर प्रदेश। प्लॉट नंबर 45 निम्नानुसार सीमाबद्ध है :
पूर्व : प्लॉट नंबर 44 और प्लॉट का शेष भाग, पश्चिम : प्लॉट नंबर 46 और गुरुद्वारा, उत्तर : वेदव्रत सेठ का प्लॉट, दक्षिण : 40 फीट चौड़ी सड़क।

लंबित मुकदमे जिनकी एआरसीआईएल को जानकारी है	शून्य	ज्ञात ऋणभार/बकाया जिनकी एआरसीआईएल को जानकारी है	शून्य

उधारकर्ता : 1. इमरान खान 2. निदा प्रवीण	कर्ज खाता क्र. HHLDPR00492736 एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी)	एआरसी आईएल-सीपीएस-IV-ट्रस्ट	रु. 33,16,151.26/- (रुपए तैंतीस लाख सोलह हजार एक सौ इक्यावन और छब्बीस पैसे मात्र) 20.12.2021 तक + उस पर अतिरिक्त ब्याज + कानूनी व्यय	वास्तविक कब्जा 29.05.2023 को	अनुरोध पर व्यवस्था की जाएगी	फ्री होल्ड - 855 वर्ग फीट (निर्मित क्षेत्र)	रु. 2,30,000/- (रुपए दो लाख तीस हजार मात्र)	रु. 23,00,000/- (रुपए तेईस लाख मात्र)	12.08.2024 को दोपहर 12.30 बजे

नीलाम की जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरण: श्री इमरान खान और निदा प्रवीण के स्वामित्व वाली संपत्ति :
अचल संपत्ति का क्षेत्रफल - 855 वर्ग फीट (निर्मित क्षेत्र) और निम्नानुसार सीमाबद्ध है : प्लॉट नंबर-सी-1ए (भाग सी-001ए) की छत के अधिकारों के बिना पूरी पहली मंजिल, पहली मंजिल के उत्तरी हिस्से में निर्मित, क्षेत्रफल 96.15 वर्ग मीटर, सेक्टर-3, अंसल चिरंजीवी विहार, कॉलोनी, गांव मेहरोली, परगना दसाना, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201001।
सीमाएं :
पूर्व : 8 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम : 9 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तर : प्लॉट सी-002, दक्षिण : प्लॉट सी-001 (सुरेश चंद का हिस्सा)।

लंबित मुकदमे जिनकी एआरसीआईएल को जानकारी है	शून्य	ज्ञात ऋणभार/बकाया जिनकी एआरसीआईएल को जानकारी है	शून्य
बोली जमा करने की अंतिम तिथि	उसी दिन नीलामी से 2 घंटे पहले	बोली वृद्धि की राशि	जैसा कि बोली के दस्तावेज में उल्लिखित है
डिमांड ड्राफ्ट जिसके नाम से बनाया जाना है:	एआरसीआईएल-सीपीएस-IV-ट्रस्ट	सममूल्य पर देय	
आरटीजीएस के विवरण	एआरसीआईएल-सीपीएस-IV-ट्रस्ट, ट्रस्ट खाता संख्या - 57500001353101, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, शाखा: कमला मिल, मुंबई, आईएफएससी कोड: HDFC0000542		
संपर्ककर्ता का नाम और नंबर	मनजीत सिंह - 0124-6910910; +91 70654 51024 (auctionhelpline@sammaancapital.com), विक्रम सिंह तंवर - 9004173256 (vikram.tanwar@arcil.co.in), शैलेश गायकवाड - 9867929121 (shailesh.gaikwad@arcil.co.in), महेश बंगेरा - 9004173256 (mahesh.bangera@arcil.co.in).		

नियम और शर्तें:
1. नीलामी बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेबसाइट https://auction.arcil.co.in के माध्यम से और बोली दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी (''एओ'')/एआरसीआईएल को इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क की समस्याओं, सिस्टम क्रैश होने, बिजली न होने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
3. नीलामी के किसी भी चरण में, ''एओ'' बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/ बोली रद्द कर सकता है या नीलामी को स्थगित कर सकता है।
4. सफल क्रेता/बोलीदाता को किसी भी वैधानिक बकाया, कर, देय शुल्क, खरीद पर लागू जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा, जिसका लागू कानून के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को उसके पक्ष में हस्तांतरित/सुपुर्द करने के लिए इसका भुगतान करना आवश्यक है।
5. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्रभावित करने वाले दायित्वों, सुरक्षित संपत्ति के टाइटल और वैधानिक बकाया आदि सहित दावों/अधिकारों/बकाया के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ/उचित आकलन करना चाहिए। नीलामी विज्ञापन में एआरसीआईएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है और न ही होगा। एआरसीआईएल का प्राधिकृत अधिकारी तृतीय पक्ष के किसी भी दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. समाचार - पत्र में प्रकाशित नीलामी सूचना में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं; हालांकि अधोहस्ताक्षरी किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जिम्मेदार/ उत्तरदायी नहीं होगा।
7. उधारकर्ता/गॅरेन्टर/बंधककर्ता, जो उक्त बकाया राशि के लिए उत्तरदायी हैं, इस बिक्री सूचना को उपरोक्त उल्लिखित नीलामी बिक्री के आयोजन के बारे में सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स के नियम 8 और 9 के तहत सूचना के रूप में मानेंगे।
8. यदि ऊपर निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है, तो एआरसीआईएल को सुरक्षित संपत्ति को नियमों और अधिनियम के नियम 8(5) के प्रावधानों के तहत किसी अन्य तरीके से बेचने का अधिकार है।

स्थान : गाज़ियाबाद
दिनांक : 18.07.2024

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
ऊधमसिंह नगर

पत्रांक : 1098/निविदा/2024-25 दिनांक: 25.07.2024

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

मुख्य महाप्रबन्धक महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा ''जल जीवन मिशन'' के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान में उल्लेखित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मो से आईटमवार दर अनुबन्ध के आधार पर ई-निविदा **(सिंगल बिड)** के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित सभी सूचना **www.uktenders.gov.in** पर दिनांक **29.07.2024** के सायं 5:00 बजे से उपलब्ध होगी।

क्र. सं.	निविदा सूचना सं0	योजना/कार्य का नाम	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा की वैधता	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	01/ 2024-25	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वि0ख0 बाजपुर की मुडिया पिस्तौर एकल पेयजल योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य (पम्प हाउस निर्माण, बाउण्ड्रीवॉल निर्माण व सॉयल फिलिंग आदि) समस्त श्रम व सामग्री सहित।	119200	Rs. 4000+GST	60 दिन	03 माह	''डी'' श्रेणी/ उच्चतर
2	02/ 2024-25	जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वि0ख0 बाजपुर की भजुवानगला एकल पेयजल योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य (पम्प हाउस निर्माण, ओ0एच0टी0 रिपेयर व सेप्टिक टैंक/सोक पिट निर्माण आदि) समस्त श्रम व सामग्री सहित ।	89500	Rs. 3000+GST	60 दिन	03 माह	''डी'' श्रेणी/ उच्चतर

शर्तें:-
1. धरोहर धनराशि की एफ.डी.आर./टी.डी.पी./एन.एस.सी, किसी भी शैड्यूल बैंक/नॉन शैड्यूल बैंक/डाकघर द्वारा निर्गत हो एवं 90 दिन के लिए वैध हो तथा ''अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऊधमसिंह नगर'' के पदनाम से बन्धक हों, निविदा के साथ जमा करनी होगी। धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. ई-निविदा दिनांक **29.07.2024** के सायं 5:00 बजे से डाउनलोड की जा सकेगी एवं दिनांक **12.08.2024** की सायं 5:00 बजे तक पोर्टल पर अपलोड की जा सकेगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड की गई धरोहर धनराशि, निविदा प्रपत्र का मूल्य, शपथ पत्र, स्टाम्प पेपर्स आदि के Original documents अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ऊधमसिंह नगर के कार्यालय में दिनांक **12.08.2024** के सायं 5:00 बजे तक जमा कराये जाने होंगे।
4. निविदा दिनांक **13.08.2024** को अपरान्ह 03:00 बजे खोली जायेगी।
5. उपरोक्त निविदा सूचना में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो संशोधित निविदा सूचना सीधे वैबसाईट **www.uktenders.gov.in** पर ही अपलोड की जायेगी। संशोधित निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र में नहीं किया जायेगा।
6. शेष शर्ते निविदा प्रपत्र के अनुसार होंगी।

''जल संचय-जीवन संचय''

(अजय कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

PUBLIC NOTICE

It is inform to the Public Notice at large that i Chandan Kumar is Purchasing the 3rd Floor with Roof rights out of Property No-73, area measuring 200 Sqyds out of Khasra No-15/24/1 Area village Dabri, Colony known as Raghu Nagar New Delhi. The owner of the floor is Vinod Kumar, he is the owner from GPA (Notarized), ATS and will dated 18/10/2011 and he was Purchased from Mrs. Dimble Kumar and Mr. Laxmi Narain from GPA/ATS/will. I am aware that in this Property the CTC of the Khatoni is not available and I Purchase this Property from GPA Holder. I am giving the news Paper Publication regarding this paper. If any person having any type of Claim/rights/title interest over the said property may inform in writing within 7 days. said property is free from all type of Encumbrance lien etc.

Basukee Nath Jha (Advocate)
Plot No 714, A/A, A Block Inder Enclave
Ph-2, Kirari Suleman Nagar, ND-86

PUBLIC NOTICE

Public Notice in respect of Property bearing No. I-4/1V, First Floor, situated at Old Double Storey, Nirmal Puri, Lajpat Nagar, New Delhi-110024, measuring 255.5 sq. ft..

That my client Shri Suresh Matnani son of Shri Nenumal Thakurdas Matnani resident of House No. B-604, Plot No. 21, Dwarka Appartments, Dwarka Phase-I, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110075 is the sole and absolute owner and in physical possession of the Property bearing No. I-4/1V, First Floor, situated at Old Double Storey, Nirmal Puri, Lajpat Nagar, New Delhi-110024, measuring 255.5 sq. ft.. on the basis of Will dated 20.05.2003, executed by his sister Late Ms. Jaya Matnani daughter of Late Shri Nenumal Thakurdas Matnani resident of I-4/1V, First Floor, Old Double Storey, Nirmal Puri, Lajpat Nagar, New Delhi-110024 during her life time, which is duly registered as Document No. 1740, in Additional Book No. III, Volume No. 354, on pages 53 to 56, on 20.05.2003, in the office of Sub-Registrar-VII, New Delhi and she died on 25.04.2021. Further, declare that the said property is free from all disputes, litigations, charges, liens, prior sale, gift, mortgage, will, prior agreement, HUF, acquisition, attachments in the decree of any court, court injunction and other encumbrances whatsoever.

If anybody has any claim, against, into or upon the said property or any part thereof by virtue of sale, gift, will, inheritance, agreement, contract, mortgage, HUF, lien, charges etc. or otherwise howsoever and whatsoever nature is hereby required to notify the same in writing along with supporting documents, if any, evidencing to the undersigned within 15 days, from the date of publication of this Notice, failing which my client shall conclude the ownership of the said property, thereafter, the objections/ claims, if any, shall be considered as waived and abandoned and shall not be binding upon my client.

AMIT ANAND, Advocate
Enrol. No. D-1452/2003

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 4/10, मैथ्री टॉवर, बोम्मनहल्ली होसुर मेन रोड, बैंगलोर- 560068

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।
कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	शमाह रबर्स, विजयकुमार पी, शोबा विजयकुमार और डेनियल पी/ 25-23ए मुंडकला विलाई, कीलापावूर, चेरुपल्लूर मार्तंडम, कन्याकुमारी-629161/ 418905004089	संपत्ति 1. कन्याकुमारी जिले में, मार्तंडम पंजीकरण जिला, थिरुवत्तार उप पंजीकरण जिला, कलकुलम तालुक, थुम्बाकोड गांव, अरमन्नम देशम आरई.एस.वाई. सं. 119/2एच में शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 34.5 एकड़ (21 सेंट 500 वर्ग लिंक्स) है, जिसका क्षेत्रफल 5 सेंट (202.35 वर्ग मी.) है, जिसमें घर है, जिसका बेयरिंग दरवाजा नंबर: 25-23ए है, चतुर्सीमा- पूर्व: सड़क, पश्चिम: जमीन कोचु कुंजन की है, उत्तर: जमीन पोन्नुमुत्तु नादर की है, दक्षिण: जमीन पोन्नुमुत्तु नादर की है, संपत्ति का पुराना एसवाई. सं. 121/बी है। संपत्ति 2. कन्याकुमारी जिले में, मार्तंडम पंजीकरण जिला, थिरुवत्तार उप पंजीकरण जिला, कलकुलम तालुक, थिरपरप्पु नगर पंचायत, थुम्बाकोड ए गांव, अरनमन्नम देशम पुराना एसवाई.सं.121बी, जेनमम आरई.एसवाई. सं.119/2एच में शामिल है, जिसका माप 34.5 एकड़ है, जिसका माप 21 सेंट (500 वर्ग लिंक्स) है, जिसका बेयरिंग कंदम सं. 04 है, जिसका माप 242.82 वर्ग मी. (6 सेंट) भूमि है, जिसमें आवासीय भवन है, जिसका बेयरिंग दरवाजा सं.25-23 है, चतुर्सीमा- पूर्व: सड़क, पश्चिम: भूमि पुष्पम और परिवार की है, उत्तर: भूमि विजयकुमार और परिवार की है, दक्षिण: भूमि गुनासीलन और परिवार की है।/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि जुलाई 23, 2024	फरवरी 17, 2024 रु. 51,19,054.00/-	कन्या-कुमारी

उपरोक्त कर्ज़दार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(याँ) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।

दिनांक : जुलाई 26, 2024
स्थान : दिल्ली

भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

एआई तैयार करेगा मोहल्ला बसों का मार्ग

आईआईटी दिल्ली के सहयोग से केजरीवाल सरकार योजना को अमली जामा पहनाएगी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि प्रदेश सरकार आईआईटी-दिल्ली के सहयोग से राजधानी में मोहल्ला बसों के लिए मार्गों को अंतिम रूप देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का लाभ उठाएगी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि केजरीवाल सरकार प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित करने और कुशल बस मार्गों को डिजाइन करने के लिए उन्नत बिग डेटा एनालिटिक्स और एआई-संचालित समाधानों का नियोजन करेगी। इसके लिए 32 सहायक यातायात निरीक्षकों (एटीआई) की एक टीम बनाई गई है, जिन्हें चार ज़ोन में विभाजित किया गया है, प्रत्येक ज़ोन में चार एटीआई की दो टीमें होंगी। वे मार्गों की पहचान करने और क्षेत्र में मोहल्ला बसों के संचालन की व्यवहार्यता का आकलन करेंगे।

एक बयान में कहा गया है, उनका मिशन दिल्ली में इन मार्गों पर नौ मीटर लंबी मोहल्ला बसों के संचालन की व्यावहारिक चुनौतियों को समझने के लिए मौके पर पहुंचाना होगा। टीम इन क्षेत्रों में नए मार्ग शुरू करने पर जनता से इनपुट भी एकत्र करेगी। इस पर टिप्पणी करते हुए, गहलोत ने कहा, सार्वजनिक परिवहन में एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग दिल्ली के लिए एक परिवर्तनकारी (गेम-चेंजर) पहल है। हम मोहल्ला बस मार्गों को अंतिम रूप देने में एटीआई की मदद भी ले रहे हैं। कम सेवा वाले और अधिक पैदल चलने वाले क्षेत्रों की पहचान करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा मोहल्ला बस नेटवर्क न केवल कनेक्टिविटी को बढ़ाएं बल्कि कुशलतापूर्वक और स्थायी रूप से संचालित हो। यह पहल दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, बयान में कहा गया है कि इससे परिवहन मांग में बढ़ोतरी करने के साथ अनुकूलित रूट तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो को बेहतर इंट्रा-रीजन और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, इलेक्ट्रिक वाहनों और रणनीतिक रूट प्लानिंग के उपयोग के माध्यम से लागत-प्रभावशीलता और पर्यावरणीय स्थिरता पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह आईआईटी-दिल्ली की मदद से किया जाएगा जो मूल-गंतव्य जोड़ों की पहचान करने के लिए एक मॉडल विकसित करेगा। एक व्यापक आपूर्ति मॉडल बनाने के लिए वर्तमान नेटवर्क के स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी का मूल्यांकन करने के लिए वास्तविक दुनिया के यात्रा समय डेटा का उपयोग करेगा।

बयान में कहा गया है कि यह परिवहन एजेंसियों और गूगल मैप्स सहित यात्री सूचना प्लेटफार्मों से पारगमन और यात्रा समय के आंकड़ों को भी समाहित करेगा। ताकि स्थानों के बीच यात्रा की आसानी का निर्धारण किया जा सके।

गांवों के विकास के लिए 318 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

- विकास मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में विभागों के साथ की समीक्षा बैठक
- एक सप्ताह के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के निर्देश

अधिकारियों के साथ बैठक करते विकास मंत्री गोपाल राय।

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में गुरुवार को दिल्ली के गांवों के विकास कार्यों को गति देने के लिए दिल्ली सचिवालय में विकास विभाग, एमसीडी और आईएंडएफसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई।

विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के गांवों के विकास से संबंधित 455 करोड़ की 318 परियोजनाओं को ग्राम विकास विभाग ने स्वीकृति दे दी है। आईएंडएफसी एवं एमसीडी के अधिकारियों को दिल्ली के गांवों के विकास कार्यो से सम्बंधित परियोजनाओं और लंबित प्रस्तावों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर गांवों के विकास से संबंधित कार्यों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के गांवों में हर तरह की मूलभूत सेवाएं सुनिश्चित करना है। इसी संदर्भ में दिल्ली के गांवों से संबंधित विकास कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली सचिवालय में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान चल रही परियोजनाओं एवं लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की गई और आईएंडएफसी एवं एमसीडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम विकास से संबंधित कार्य को तय सीमा के भीतर पूरा करें। विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि गांवों के विकास से सम्बंधित 455 करो? की 318 परियोजनाओं को ग्राम विकास बोर्ड विभाग ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने आईएंडएफसी एवं एमसीडी के अधिकारियों को जल्द टेंडर करने का निर्देश दिया है, ताकि गांवो के विकास कार्य जल्द पूरा किया जा सके।

आप का मूलभूत सुविधाओं पर जोर: गोपाल

राजधानी के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए पिछली बोर्ड मीटिंग में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने जिन योजनाओं को मंजूरी दी थी, इसी के संदर्भ में यह समीक्षा बैठक की गई। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार गांवों में सड़कों, पार्कों, नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी के माध्यम से किया जा रहा है। विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि केजरीवाल सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात कर सकेंगे केजरीवाल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- हाईकोर्ट ने मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए राहत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में अपने वकीलों के साथ हर सप्ताह दो अतिरिक्त ऑनलाइन बैठक करने की अनुमति देते हुए कहा कि विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की जरूरत होती है। केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाला मामले में जेल नियमों के अनुसार अब तक सप्ताह में दो बार अपने वकीलों से मुलाकात की अनुमति थी।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के उनके मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल को राहत प्रदान की। आम आदमी पार्टी (आप) नेता के वकील ने कहा कि वह देशभर में लगभग 35 मामलों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठक करने की जरूरत है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और तिहाड़ जेल अधिकारियों के वकीलों ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया।उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह केजरीवाल के लिए विशेष सुविधा होगी। न्यायालय ने कहा कि यह ऐसी स्थिति नहीं है जहां कोई विशेष लाभ मांगा गया हो। न्यायाधीश ने कहा कि यह एक मौलिक अधिकार है जिसे लागू करने का प्रयास किया गया है।

उच्च न्यायालय द्वारा 18 जुलाई को पारित आदेश उपलब्ध कराया गया। न्यायालय ने कहा, विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त बहस के मद्देनजर, यह माना जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वकील के साथ दो अतिरिक्त बैठक करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि जेल नियम संबंधित जेल अधिकारियों द्वारा सभी तौर-तरीकों, बुनियादी ढांचे और वहां कैदियों की संख्या पर विचार करने के बाद तैयार किए गए हैं।

मुख्यमंत्री, सिसोदिया व कविता की हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दी।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज धनशोधन मामले में केजरीवाल की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी जबकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी न्यायिक हिरासत आठ अगस्त तक बढ़ा दी गई।

राजधानी में पीएसयू केंद्रों की हड़ताल खत्म

- डीपीडीए और परिवहन विभाग की बैठक में संशोधित दरों पर हुई चर्चा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (डीपीडीए) और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद 15 जुलाई से बंद पड़े प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) केंद्रों में फिर से कामकाज शुरू करेगा।

एसोसिएशन ने प्रदूषण प्रमाण पत्रों की दरों में प्रस्तावित वृद्धि से असंतुष्टि जताते हुए 15 जुलाई से पीयूसीसी केंद्र बंद कर दिए थे। उसने कहा कि यह वृद्धि केंद्रों के संचालन में लगने वाली लागत के अनुरूप नहीं है। डीपीडीए ने एक बयान में कहा कि उसके प्रतिनिधियों ने परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक की। बयान के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि डीपीडीए तुरंत हड़ताल वापस लेगी और दिल्ली की आम जनता के हित में पीयूसीसी का परिचालन फिर से शुरू करेगी।

इसमें कहा गया है, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने भी प्रक्रिया में शामिल वास्तविक लागतों के आधार पर दरों में और संशोधन के पहलू पर पुनर्विचार करने पर सहमति व्यक्त की है। डीपीडीए इस संबंध में विस्तृत समर्थ प्रस्तुत करेगा। जनहित में डीपीडीए ने अपने पेट्रोल पंपों पर पीयूसीसी केंद्रों की हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया है।

11 जुलाई को दिल्ली सरकार ने करीब 13 साल बाद पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों के लिए पीयूसीसी शुल्क में बढ़ोतरी की। यह बढ़ोतरी 20 से 40 रुपए के बीच है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि सरकार द्वारा नई दरें अधिसूचित होते ही लागू हो जाएंगी। दिल्ली में कुल 900 से अधिक पीयूसी जांच केंद्र है, इसमें से 700 से अधिक केंद्र पेट्रोल पंपों पर स्थित हैं।

डीयू के कई कोर्सों की फीस में बढ़ोतरी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- विश्वविद्यालय कुलपति योगेश सिंह ने इसे जून में दी थी मंजूरी

दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक, परास्नातक और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले छात्रों के साथ-साथ 2024-2025 शैक्षणिक सत्र से प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों के लिए फीस में बढ़ोतरी की है। कुलपति योगेश सिंह ने अगस्त से शुरू होने वाले शैक्षणिक कैलेंडर के लिए नई फीस संरचना को जून में मंजूरी दी थी। नई फीस संरचना के अनुसार, प्रथम वर्ष के बीटेक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क में 3.70 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, यानी 2.16 लाख रुपये से 2.24 लाख रुपये तक।प्रौद्योगिकी संकाय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह बढ़ोतरी वर्तमान में विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए लागू की गई है। विश्वविद्यालय ने ट्यूशन फीस, छात्र कल्याण कोष, विकास शुल्क, सुविधा और सेवा शुल्क और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहायता कोष सहित शुल्क संरचना के कई घटकों में वृद्धि की है।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के लिए अंशदान का हिस्सा विभाग की फीस संरचना से हटा दिया गया है। एलएलबी और एमबीए फीस स्ट्रक्चर से डीयूएसयू का अंशदान भी हटा दिया गया है, जबकि बाकी यूजी और पीजी कोर्स के लिए अंशदान 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, शैक्षणिक वर्ष के लिए पांच वर्षीय एकीकृत विधि कार्यक्रमों की फीस में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, यानी 1.90 लाख रुपये से 1.99 लाख रुपये।

शिक्षा संकाय के तहत बीईएल.एड की जगह लेने वाले चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) की फीस बढ़ाकर 57,400 रुपये कर दी गई है। पीएचडी पाठ्यक्रमों की फीस संरचना के घटकों में संशोधन के परिणामस्वरूप कुल फीस में 60.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें विद्वानों को आगामी सत्र से 4,450 रुपये की पिछली फीस की तुलना में 7,130 रुपये का भुगतान करना होगा। डीयू डीन एडमिशन, हनीत गांधी ने पुष्टि की कि विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों के लिए भी फीस बढ़ा दी गई है। इस बीच, दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए हिंदू अध्ययन में प्रवेश लेने वाले विदेशी नागरिकों को कम कोर्स फीस देनी होगी।

भाजपा कार्यकर्ता गांव के हर बूथ तक पहुंचे : वीरेंद्र सचदेवा

- प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा किसान मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक में किया आह्वान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बृहस्पतिवार को प्रदेश किसान मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे ग्राम परिक्रमा अभियान शुरू करें और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में हर गांव में हर बूथ पर जाएं।

सचदेवा ने कहा, अगर हमने दिल्ली में 23 विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में जीत हासिल की है, तो आप सभी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ग्राम परिक्रमा अभियान शुरू करें और हर गांव में हर बूथ पर जाकर जनसंपर्क करें और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। भाजपा के दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक अलीपुर स्थित खाटू श्याम दिल्ली धाम में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सहरावत ने की।

संक्षिप्त समाचार

संजय सिंह ने एनएचपीसी निदेशक का पदभार संभाला

नई दिल्ली। संजय कुमार सिंह ने जलविद्युत कंपनी और अनुसूची 'ए' उद्यम, एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक (परियोजनाएं) का पदभार ग्रहण किया है। सिंह ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (सिविल) की डिग्री हासिल की है। उनके पास भारत और भूटान में ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की बड़ी और प्रतिष्ठित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 32 वर्षों से अधिक का विशाल और विविध अनुभव है। एनएचपीसी में निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में नियुक्ति से पहले सिंह एसजेवीएन लिमिटेड में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। एसजेवीएन में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई प्रमुख परियोजनाओं का नेतृत्व किया है जिसमें सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना (निर्माण चरण), नैटवाड़ मोरी जलविद्युत परियोजना (निर्माण चरण), लुहरी जलविद्युत परियोजना चरण (सर्वेक्षण एवं जांच चरण) तथा जखोल संकरी जलविद्युत परियोजना (सर्वेक्षण एवं जांच चरण) शामिल हैं।

हंसराज कॉलेज स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति होंगे शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के 77 वें स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. योगेश सिंह करेंगे। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ. प्रभांशु ओझा ने बताया कि हंसराज कॉलेज 26 जुलाई को अपनी स्थापना के 77 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। कार्यक्रम सायं 5 बजे से हंसराज कॉलेज के मदन मोहन मालवीय सभागार में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डीएवी प्रबंधकर्ता समिति के उपाध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल होंगे। कॉलेज प्राचार्य प्रो. रमा ने बताया कि इस अवसर पर उपराष्ट्रपति नए प्रशासनिक खण्ड का उद्घाटन भी करेंगे। यह जानकारी कार्यक्रम संयोजक डॉ. शैलू सिंह एवं समन्वयक डॉ. प्रभांशु ओझा ने दी।

मालीवाल मारपीट मामले में बिभव ने मांगी जमानत

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, कुमार ने 19 जुलाई को जमानत याचिका दायर की थी और 24 जुलाई को इसे पंजीकृत किया गया। बिभव कुमार ने मामले में जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है और दावा किया है कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं। कुमार ने यह भी कहा है कि जांच पूरी हो जाने के कारण अब उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा जिसमें धनशोधन के एक मामले में उनके और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और 15 दिन के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को तय की है। जैन ने धनशोधन मामले में ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने संबंधी निचली अदालत के 29 जुलाई, 2022 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका में बंदूक दिखाकर 16 वर्षीय एक लड़की के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के बाद उसे इमारत की पांचवीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया।

पुलिस ने बताया कि घटना सोमवार को उस समय हुई जब आरोपी पीड़िता के घर में जबरन घुस गया। पुलिस के मुताबिक, घटना के वक्त लड़की के माता-पिता घर में नहीं थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी लड़की को पास की एक इमारत में ले गया, जहां उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया और उसे इमारत की पांचवीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता को में दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि नीचे गिरने से लड़की के पैरों में फ्रैक्चर हो गया।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की काउंसलिंग कर उसका बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 (2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 65 (1) (16 साल से कम उम्र की युवती से दुष्कर्म के लिए सजा) व 109 (1) (हत्या का प्रयास) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

केंद्रीय विद्यालय एजीसीआर में मना शिक्षा सप्ताह

- सांस्कृतिक विविधता थीम पर हुआ कार्यक्रम

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एजीसीआर कॉलोनी में शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत भारत की सांस्कृतिक विविधता थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्या प्राची दीक्षित ने छात्रों को शिक्षा सप्ताह के महत्व और उद्देश्य से अवगत कराया।

कार्यक्रम का उद्घाटन देवन शर्मा द्वारा गीता के श्लोक से किया गया। भरत नाट्यम, भांगड़ा, गरबा, लावनी आदि की प्रस्तुति छात्रा मनस्वी, कास्वी, अवनी नेगी,न्यासा, आशा और अनामिका के द्वारा की गई। प्राचार्या प्राची दीक्षित ने सभी छात्रों को अद्भुत प्रस्तुति हेतु बधाई और शाबाशी दी। इस अवसर पर उप प्राचार्य शेर सिंह, मुख्य अध्यापिका सविता महेंद्रू, नरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, सीसीए कार्डिनेटर कुमुद रंजन झा, आकाश संगीत शिक्षक जीएन झा, मिथुन सहित सभी शिक्षक, छात्र कार्यक्रम में उत्साह पूर्वक सम्मिलित हुए।

पिंक लाइन के पांच स्टेशनों पर दीवार की जगह लगाई रेलिंग

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर हादसे के बाद की गई कार्रवाई

गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर दीवार का एक हिस्सा ढहने पर एक व्यक्ति की मौत के बाद डीएमआरसी ने पिंक लाइन पर पड़ने वाले पांच स्टेशनों पर कंक्रीट की दीवारें हटाकर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाई हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने लाइन पर सभी एलिवेटेड स्टेशनों का निरीक्षण किया और आगे की कार्वाई के लिए पांच स्टेशनों – गोकुलपुरी, जाफराबाद, वेलकम, ईस्ट आजाद नगर और कृष्णा नगर की पहचान की। अधिकारी ने कहा, पिंक लाइन के सभी एलिवेटेड स्टेशनों पर स्थापित प्लेटफॉर्म के पास पैरापेट नामक कंक्रीट संरचना का निरीक्षण किया गया। हमने पांच स्टेशनों से कंक्रीट संरचना को हटाकर उसकी जगह स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगा दी। पूर्वोत्तर दिल्ली में एलिवेटेड गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की दीवार का एक हिस्सा 8 फरवरी को ढह गया था, जिसमें 53 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार घायल हो गए थे। मेट्रो की पिंक लाइन मजलिस पार्क को शिव विहार से जोड़ती है।

आप को लुटियंस दिल्ली में मिला नया कार्यालय

- पंडित रविशंकर शुक्ल लेन में स्थित बंगला नंबर का आंवटन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

फोटो: रंजन डिमरी

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी (आप) को लुटियंस दिल्ली क्षेत्र में एक नया कार्यालय आवंटित किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल लेन में स्थित बंगला नंबर एक आप का नया कार्यालय है।

उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद पार्टी को पंडित रविशंकर शुक्ला लेन में एक नया कार्यालय आवंटित किया गया है।

आप का कार्यालय पहले राउज एवेन्यू में स्थित था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर आप को मान्यता देते हुए उसे कार्यालय के लिए स्थान आवंटित करने का निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को बृहस्पतिवार तक का समय दिया था। बता दें कि ये दफ्तर कभी शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का था। बता दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी को कार्यालय के लिए जमीन आवंटन की मांग संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को कहा है कि वह 25 जुलाई तक फैसला ले. कोर्ट की सुनवाई के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने और अधिक समय की मांग की, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया था। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय का कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद ही पार्टी ने जमीन के लिए आवेदन कर दिया था. नियमों के मुताबिक जमीन के आवंटन के तीन साल के भीतर पार्टी को अपना कार्यालय बनाना होता है। लेकिन इसमें देरी हुई।

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024

स्वीमिंग पूल में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत

लापरवाही बरतने पर दो लाइफ गार्ड गिरफ्तार, एक आरोपी 10 और दूसरा दो दिन पहले लगा था नौकरी पर

● 1.5 फुट की जगह 4 फुट गहरे पानी में जाने के कारण गई जान

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

सेक्टर-10 थाना के अंतर्गत एक सोसायटी के स्वीमिंग पूल में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर लापरवाही बरतने का आरोप है।

बच्चे के दादा ने पुलिस को शिकायत देकर कहा कि वह बीपीटीपी पार्क सेरेन सेक्टर-37डी में रहते हैं। क्लब में 3 अलग-अलग स्वीमिंग पूल हैं। तीनों की गहराई अलग-अलग है। उसकी पत्नी 5 साल के पौते मीवांश को सोसायटी के क्लब में 1.5 फीट गहराई वाले स्वीमिंग पूल में लेकर गई थी। वहां बच्चे जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी पोते के लिए कुछ सामान लेने के लिए फ्लैट में आ गई। इस बीच उसके पास फोन आया कि मिवांश को अस्पताल ले जाया गया है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि मिवांश की मृत्यु हो चुकी है।

पूछताछ में पता चला कि पोते मिवांश की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि उनके पोते की मृत्यु लाईफ गाड्र्स, सिक्योरिटी गाड्र्स, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, स्वीमिंग पूल संचालक, कंपनी प्रबंधन तथा कुछ अन्य लोगों की लापरवाही के कारण 4 फुट वाले स्वीमिंग पूल में डूबने की वजह से हुई है। वहां पर बच्चों का जाना वर्जित है। इस शिकायत पर थाना सेक्टर-10 में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। थाना सेक्टर-10 पुलिस टीम ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों की पहचान दुर्ग निवासी हिणवानी जिला दमोह (मध्य-प्रदेश) व आकाश निवासी गांव डेकुली जिला गोपालगंज (बिहार) के रूप में हुई है। दोनों आरोपी सोसायटी क्लब के स्वीमिंग पूल में लाइफ गार्ड का काम करते हैं। आरोपी दुर्ग 10 दिन पहले व आरोपी आकाश 2 दिन पहले ही नौकरी पर आया था। दोनों आरोपियों ने लापरवाही बरतते हुए बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। जिससे बच्चा 4 फीट गहराई वाले स्वीमिंग पूल में चला गया। पूल में डूब जाने के कारण बच्चे की मौत हो गई।

नेताओं ने जमा की अकूत संपत्ति, पता लगाने को हो नारको टेस्ट: जयहिंद

● हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पेश की दावेदारी

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम में पत्रकारों से बातचीत करते नवीन जयहिंद।

जयहिंद सेना सुप्रीमो एवं आम आदमी पार्टी के पूर्व हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने कहा कि राजनीति में आकर नेताओं ने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है। उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। साथ ही उनके नार्को टैस्ट भी होना चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

नवीन जयहिंद गुरुवार को यहां पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्रकार वार्ता में घी और लंगोट लेकर पहुंचे नवीन जयहिंद ने कहा कि हरियाणा में राज्य सभा का चुनाव होने जा रहा है। वे भी इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। उन्होंने गुरुग्राम के सभी विधायकों के मोबाइल नंबर जारी करते हुए कहा कि आम जनता विधायकों से बात करे। उनके लिए समर्थन की अपील करके अपनी समस्याओं की जानकारी भी दे। साथ ही विधायकों के लिए भी यह अवसर है कि जब भी किसी का फोन आए तो वे अपने भविष्य के लिए वोट भी पक्के कर सकते हैं। जयहिंद ने मोबाइल नंबर-7027822822 जारी करते हुए जनता से अपील की कि इस नंबर पर कॉल करके वोट जरुर डालें।

जयहिन्द ने बताया की सरपंच, हरियाणा पुलिस, आशा वर्कर्स, दलित, बाहरी भर्ती, खेल कोटा, पहरावर, फैमिली आईडी ये मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। जिन भी लोगों को इन मुद्दों के उठने से लाभ हुआ है वे लोग अपने-अपने विधायकों को फोन जरूर करें।

नवीन जयहिन्द ने हरियाणा में होने वाले राज्यसभा के चुनावी मैदान में पक्ष व विपक्ष के लिए पहले नंबर की छुट्टी बोल रखी है। अगर पक्ष या विपक्ष के पास कोई संघर्षशील व योग्य उम्मीदवार है, जिसने 21 साल सरकारों से लड़ाई लड़ी हो तो उसे हमारे सामने लाए। ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारें। उन्होंने कहा कि वे डबल ईंजन की नहीं चार-चार ईंजन की सरकारों से लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने समर्थन के लिए उन्होंने महम के विधायक बलराज कुंडू का भी आभार जताया। नवीन जयहिंद ने कहा कि पूर्व सीएम हुड्डा कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार उतारे और दुष्यंत चौटाला कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वे ईडी-सीबीआई से डर रहे हैं तो उन्हें हमारे तम्बू में भेज दें। जयहिंद ने कहा कि दुष्यंत चौटाला अपना व अपनी माता का समर्थन हमें दे दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना समर्थन दे दें।

खेड़ा खुर्रमपुर में हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद

गुरुग्राम। वर्ष 2019 में लाठी-डंडों से पीटकर व गोली मारकर हत्या के आरोपियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 22 मार्च 2019 का थाना फर्रूखनगर के अंतर्गत गांव खेड़ा खुर्रमपुर में एक व्यकित की हत्या करने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर मृतक के भाई ने बताया कि उसके भाई पवन की कुछ व्यक्तियों ने रंजिश रखते हुए लाठी डंडों से पीटकर व गोली मारकर हत्या कर दी है। इस शिकायत पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने इस हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिनकी पहचान चेतन निवासी गांव जोनियावास, पवन निवासी गांव खेड़ा खुर्रमपुर, रिंकू निवासी ताज नगर गुरुग्राम व प्रवीण निवासी फर्रुखनगर जिला गुरुग्राम के रूप में हुई थी।

बजट देश को विकसित राष्ट्र बनाने का रोडमैप: बख्शी

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पूर्व आईआरएस एवं हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल के चेयरमैन अनुराग बख्शी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश बजट में कुल 48.21 लाख करोड़ के खर्चे का प्रावधान है, जिसमें कुल प्राप्तियों 32.07 लाख करोड़ और 11.63 लाख करोड़ की उधारी के साथ वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसद है। चेयरमैन अनुराग बख्शी ने कहा कि ये बजट मोदीनॉमिक्स के मूल मंत्र विकास भी और विरासत भी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोडमैप। पूंजीगत मद में 11.11 लाख करोड़ का प्रावधान मोदी सरकार की विकास के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। बख्शी ने कहा कि बजट डॉक्यूमेंट में 9 प्राथमिकताएं वर्णित की गई हैं।

उद्योग जगत को नहीं मिल पा रहे तकनीकी रूप से सक्षम युवा: बोधराज सीकरी

● प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की मासिक बैठक संपन्न

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बैठक में बोधराज सीकरी को सम्मानित करते संस्था के सदस्य।

प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने बोधराज सीकरी समाजसेवी एवं प्रदेश संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भाजपा को अपनी मासिक बैठक में सम्मानित किया। इस बैठक में उद्योग जगत (लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग) के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

एसोसिएशन के वार्षिक दिवस पर बोधराज सीकरी ने सभी को बधाई दी। सभी उद्योगपतियों को आग्रह भी किया कि वे समाज के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। मैंने संगठन से टिकट की प्रार्थना भी की है। उद्योगपतियों का सहयोग भी मेरे लिए उतना आवश्यक है, जितना बाकी श्रेणी का आवश्यक है। इस कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. दिनेश कुमार भी उपस्थित थे।

खम्भे में उतर रहे करेंट की चपेट में आने से दो गायों की मौत

● कांग्रेस नेता बलजीत कौशिक ने कहा, भाजपा सरकार में गौमाता की हो रही दुर्गति

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

ट्यूबवेल नंबर दो के समीप करंट से मरी गाय दिखाते कांग्रेस नेता बलजीत कौशिक।

ओल्ड फरीदाबाद के हीरा मंदिर रोड ट्युबवैल नंबर-2 के समीप बिजली के खम्भे में करंट उतरने से दो गायों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही कांग्रेस के पूर्व महासचिव बलजीत कौशिक मौके पर पहुंचे और कालोनीवासियों से सारी घटना की जानकारी ली।

लोगों ने बताया कि सुबह उक्त बिजली के खम्भे में करंट आया था, जिससे एक गाय की मौत हो गई, इसकी जानकारी विभाग के कर्मचारियों को दी, जिस पर उन्होंने अपनी कार्यवाही शुरू की और कुछ समय बाद कहा कि अब खम्भे में करंट नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद वहां से गुजर रही एक अन्य गाय करंट लगने से मर गई। बिजली कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर कालोनीवासियों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। इस मौके पर कांग्रेसी नेता बलजीत कौशिक ने कहा कि एक तरफ तो भाजपा सरकार गायों को मां का दर्जा देने की बात करती है, दूसरी तरफ उन्हें सड़कों पर गंदगी खाने के लिए छोड़ देती है, इनके रखरखाव के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं करती। पूरे शहर में जगह-जगह गायों को गंदगी खाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल वोट की राजनीति करती है, गौमाता और धर्म की आड़ में वोट ले लेती है और सत्ता प्राप्ति के बाद सब भूल जाती है। श्री कौशिक ने सरकार व प्रशासन से मांग की कि इस घटना के लिए दोषी जेई व एसडीओ के खिलाफ कार्यवाही होगी और जिस पशुपालक की गायें इस घटना में मारी गई है, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इस मौके पर शगुनचंद जैन, एनके शर्मा, नरेंद्र कुमार, नरेश कुमार, रोहित, सतबीर, मनीष, कपिल, रामपाल, जुबैर, सुरेश, डालचंद सहित अनेकों कालोनीवासी मौजूद थे।

हरियाणवी बागवानी का मुरीद हुआ दक्षिण अफ्रीका

● पॉली ग्रीन हाऊस पहुंचा प्रतिनिधिमंडल, उन्नत तकनीकियों का किया अध्ययन

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

पॉली ग्रीन हाउस में तैयार हो रहे पौधों की जानकारी लेते प्रतिनिधिमंडल के सदस्य।

बागवानी फसलों के माध्यम से भी हरियाणा की विदेशों में धाक है। इसी को देखने के लिए यहां इंडिया मिलेट मिशन के तहत दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। सदस्यों ने यहां उद्यान विभाग के पॉली ग्रीन हाउस में सब्सिडी के तहत तैयार की जा रही किसानों की विभिन्न फसलों के पौधों की जानकारी ली। विदेशियों की निगाह में यहां के पॉली ग्रीन हाउस से यह साबित हो जाता है कि हरियाणा में बागवानी क्षेत्र में कम लागत के साथ अधिक उत्पादन व उन्नत तकनीक के साथ जोखिम मुक्त फसलों में कितना सफल हो रहा है। यह कार्यक्रम कृषि व किसान कल्याण विभाग और बागवानी विभाग की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

नर्सरी में पौध तैयार करने की प्रक्रिया में दिखाई रुचि

प्रतिनिधिमंडल ने नर्सरी में पौध तैयार करने की प्रक्रिया की बारीकियों को समझा। जिसकी जानकारी देते हुए नर्सरी एक्सपर्ट डॉ. नीरू ने बताया कि किसानों से प्राप्त बीजों को कोकोपिट, पर्लाइट और वर्मीकुलाइट के निर्धारित अनुपात मिश्रण में एक प्रोट्रे में रोपित किया जाता है। इसके उपरांत संबंधित बीज की पौध तैयार होने की एक निश्चित अवधि तक हाईटेक नर्सरी में निर्धारित तापमान पर उसकी देखरेख की जाती है। इससे किसानों का दवाई व स्प्रे का पैसा भी बचता है।

खांडसा मंडी में फैली गंदगी अधिकारियों की देन: पंकज

खांडसा सब्जी मंडी में कीचड़ के बीच दुकानदारों के साथ खड़े पंकज डावर।

● कहा, सरकार व जिला प्रशासन सब्जी मंडी की सफाई पर दे ध्यान

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम की एकमात्र थोक सब्जी मंडी व अनाज मंडी खांडसा में छोटे से लेकर बड़े सभी व्यापारी व यहां आने वाले हजारों ग्राहक मंडी में फैली गंदगी व कूड़े के ढेर से परेशान हैं। यह कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर का।

वे गुरुवार को मंडी के व्यापारियों के बुलावे पर उनकी समस्याएं जानने पहुंचे थे। इस मौके पर पंकज डावर ने कहा कि अनाज मंडी की गंदगी देखकर लगता है कि यहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने कभी भी अपने एसी कार्यालय से बाहर जाकर मौजूदा स्थिति पर नजर नहीं डाली। उन्होंने कहा कि यहां सुबह-शाम सब्जियां व फल बेचने वालों से अवैध तरीके से सफाई के नाम पर 10-10 रुपये सुबह व शाम को दो बार वसूल किये जाते है।

इस तरह का अवैध टैक्स मंडी में कौन वसूल करता है यह जानकारी किसी के पास नहीं है। यहां के व्यापारी कहते हैं कि उन्हे सफाई के नाम पर पैसे देने में परेशानी नहीं है, सफाई हो तो वे इससे भी अधिक पैसे देने को तैयार है। यहां सफाई के ठेकेदार बरसात होने के कई दिनों तक सफाई ही नहीं करते। सफाई के नाम पर पूरी मंडी में एक ट्रैक्टर में ऐरों के माध्यम से कचरा खींचकर एक जगह एकत्र किया जाता है।

संक्षिप्त समाचार

प्रतियोगिता जीतने के बाद स्टाफ के साथ सेक्टर-9 कालेज के छात्र।

सेक्टर-9 कालेज के छात्रों की डॉक्यूमेंट्री ने जीती प्रतियोगिता

गुरुग्राम। राजकीय महाविद्यालय सेक्टर-9 के विद्यार्थियों ने डिविजन स्तरीय कानून साक्षरता प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्री प्रतियोगिता में विकास एवं पूजा की डॉक्यूमेंट्री ने प्रथम पुरस्कार जीता। इसी श्रेणी में करण की डॉक्यूमेंट्री ने द्वितीय पुरस्कार हासिल किया। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत वाद-विवाद प्रतियोगिता में शीतल एवं पायल ने द्वितीय पुरस्कार हासिल किया। पेंटिंग प्रतियोगिता में अंकित ने तृतीय पुरस्कार जीता। महाविद्यालय की प्राचार्या मधु अरोड़ा ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगिण विकास के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जो विद्यार्थी इन प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ?र भाग लेते हैं, वह अवश्य ही जीवन में सफल होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को इसी प्रकार प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

'मानवता के कार्यों में सामाजिक संगठनों की विशेष भूमिका'

फरीदाबाद। मारवाड़ी युवा मंच फरीदाबाद के द्वारा निशुल्क ट्राई साइकिल राजस्थान भवन सेक्टर 10 में वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिजेंद्र सौरोत सचिव रेडक्रॉस सोसायटी फरीदाबाद, विशिष्ट अतिथि के रूप में कमलेश शास्त्री मण्डल बाल कल्याण अधिकारी एवं पुरुषोत्तम सैनी जिला प्रशिक्षण अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि कि दिव्यांग भाइयों का जीवन सरल बनाने के लिए निशुल्क ट्राई साइकिल वितरण किया गया निश्चित रूप से वह अपनी दैनिक दिनचर्या में सुविधा प्रदान होगी। वह बेहतर रूप से अपने कार्य को कर सकेंगे। हम सभी का उद्देश्य दिव्यांग भाइयों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का होना चाहिए। नर सेवा नारायण सेवा होती है। मारवाड़ी युवा मंच अध्यक्ष विमल खंडेलवाल ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में मारवाड़ी युवा मंच की 850 शाखों के साथ में मानवता का कार्य किया जा रहा है।

आने वाले दशक में भारत में बढ़ेंगे कैंसर के मामले: साहनी

फरीदाबाद। सिर और गर्दन कैंसर दिवस हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। इसे लेकर अमृता अस्पताल फरीदाबाद ने गुरूवार को सिर और गर्दन के कैंसर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बडा खुलासा किया है। जिसका आयोजन जागरूकता के उद्देश्य से किया गया। अमृता हॉस्पिटल, फरीदाबाद के हेड एंड नेक कैंसर विभाग के कंसल्टेंट डॉ शिखर साहनी ने कहा, भारत और पश्चिम में हेड एंड नेक (एचएन) कैंसर की दर और महामारी विज्ञान अलग-अलग हैं। भारत में मुंह का कैंसर अधिक प्रचलित है, जिसके कारण इसे विश्व की मुंह के कैंसर की राजधानी का खिताब मिला है। पश्चिम के विपरीत, जहां तंबाकू पर नियंत्रण बढ़ने से इसके मामले कम हुए हैं, भारत में यह दूसरा सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। दूसरी ओर, एचपीवी से जुड़ा ऑरोफरीन्जियल कैंसर पश्चिम में व्यापक हो गया है और महामारी बन गया है, जबकि यह अभी भी केवल 5-10 फीसदी भारतीयों को प्रभावित करता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले एक दशक में पश्चिम की तरह भारत में भी एचपीवी से संबंधित कैंसर बढ़ जाएगा। भारत में, एचएन कैंसर की घटनाओं में 2025 तक 12 फीसदी तक की वृद्धि होने की उम्मीद है।

मोठूका गांव में कूड़ाघर रुकवाने को विधायक से मिले ग्रामीण

दयाराम वशिष्ट। फरीदाबाद: गांव मोठूका में प्रस्तावित कूड़ाघर के खिलाफ लामबंद ग्रामीणों ने आज तिगांव से भाजपा विधायक राजेश नागर से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। करीब एक दर्जन गांवों के प्रतिनिधियों ने नागर से कहा कि उनके यहां कूड़ा घर बनने से माहौल बद से बदतर हो जाएगा। इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। जिस पर विधायक ने उनकी हर संभव सहायता करने की बात कही।

आज विधायक राजेश नागर के भतौला स्थित निवास पर गांव मोठूका, नंगला, नया गांव, अरुआ, फैज्जूपुर खादर, साहूपुरा खादर, शाहजहांपुर खादर, अहसान नगर, दूल्हेपुर, ईमामुद्दीनपुर, चांदपुर, बहादुरपुर, कौराली, अटाली, मौजपुर, गढ?ड़ा, दयालपुर, नरहावली, छायंसा, पंचायत झुग्गी के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। लोगों ने बताया कि सरकार ने उनके गांव मोठूका में कूड़ाघर बनाने की घोषणा की है। जिससे यहां करीब 20 गांव प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ मोठूका में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों पर भी असर होगा। यहां अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भी है, गांव नंगला में प्राइमरी स्कूल, गांव मोठूका में कन्या स्कूल, अरुआ में सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदि में करीब 4000 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कूड़ाघर बनने के बाद इन सबके स्वास्थ्य पर असर पडने की आशंका है, जिसे अभी रोका जाए।

लोगों ने विधायक राजेश नागर के समक्ष इस कूड़ाघर के बन जाने के बाद भूजल के दूषित होने की भी आशंका जताई। उन्होंने कहा कि यहां बने रेनीवेल से शहरों में आपूर्ति हो रहे पानी के भी प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ग्रामीणों ने विधायक राजेश नागर से कहा कि वह अपने प्रयास कर इस प्लांट को कहीं और स्थानांतरित करवाकर उन्हें राहत दिलवाएं। जिस पर नागर ने उनकी हर संभव मदद की बात कही। नागर ने कहा कि आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, मैं भी आपकी परेशानी को यथासंभव दूर करवाने की कोशिश जरूर करूंगा।

दाखिले के भ्रामक दावों से किया सावधान

● जेसी विश्वविद्यालय ने किया स्पष्ट, कहा पूर्णत: योग्यता पर आधारित है प्रवेश प्रक्रिया

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद ने छात्रों तथा उनके अभिभावकों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने का झूठा दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह से सावधान किया है जोकि दाखिला दिलाने के नाम पर उनसे पैसा ऐंठने का प्रयास हो सकता है।

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया पूर्णत: योग्यता पर आधारित है। विश्वविद्यालय की दाखिला समिति द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन किया जाता है। चयन प्रक्रिया में कई घटक और कट-ऑफ होते हैं, जो जेईई मेन रैंक स्कोर, प्रवेश परीक्षा तथा योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर तय किए जाते हैं। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि दाखिले के लिए विश्वविद्यालय में अलग से कोई प्रबंधन कोटा नहीं है।

लंबे जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है स्वस्थ लीवर

फल, सब्जी, साबुत अनाज और संतुलित प्रोटीन से भरपूर आहार लीवर की बेहतरी में करता है मदद

विश्व हेपेटाइटिस जागरुकता सप्ताह पर विशेष

● नियमित जांच जरूरी पीलिया, थकान या पेट दर्द महसूस हो तो बिना देरी किए लें चिकित्सक से सलाह

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

लीवर, जो कि हमारी समूचे शारीरिक संरचना को स्वास्थ्य रखने की आधारशिला है। लीवर पाचन, डिटॉक्सिकेशन और पोषक तत्वों के भंडारण के लिए बेहद जरुरी शक्तिशाली अंग है। इसे प्राथमिकता देने से न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकता है। इसलिए लीवर स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

विश्व हेपेटाइटिस वीक (22 जुलाई से 28 जुलाई) हमें यही याद दिलाता है कि लीवर शारीरिक संरचना के अनुसार लचीला तो है लेकिन अजेय नहीं। हम यदि अभी से भी लीवर के अनुकूल जीवनशैली को अपनाना शुरू करेंगे तो आने वाले कल में लीवर से सम्बंधित स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकेंगे। लीवर के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। यह लंबे स्वस्थ जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। हेपेटाइटिस दिवस एक वैश्विक पहल है, जिसका लक्ष्य वायरल हेपेटाइटिस के बारे में आम जनता के मध्य में जागरुकता बढ़ाना और इस संभावित जानलेवा बीमारी को रोकने और नियंत्रित करने के उपायों को अग्रसर करना है।

वरिष्ठ सलाहकार हेपेटोलॉजिस्ट एवं एंडोस्कोपिस्ट डॉ. नितिन मांगलिक का कहना है कि फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और संतुलित प्रोटीन से भरपूर आहार लीवर की बेहतरी में मदद करता है। अधिक मात्रा में शराब और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के परहेज से फैटी लीवर सम्बंधित रोग और सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। लीवर को हाइड्रेटेड रखना उसकी डिटॉक्सिकेशन प्रक्रियाओं में मदद करता है। प्रतिदिन व्यायाम न केवल स्वस्थ वजन बनाए रखता है, बल्कि लीवर की चर्बी को भी कम करने में मदद करता है। जिससे वह शरीर को स्वस्थ रखने में बेहतर काम कर सकता है। हेपेटाइटिस-ए और बी के खिलाफ टीका लगवाना और सुरक्षित स्वच्छता का अभ्यास करना वायरल हेपेटाइटिस को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह लापरवाही के चलते गंभीर लीवर के नुकसान का कारण बन सकता है। उनका कहना है कि नियमित चिकित्सा जांच आवश्यक है। ब्लड टेस्ट से लिवर की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी का पता पहले ही लग जाता है, जिससे उसके उपचार में काफी मददगार साबित होता है। यदि आपको पीलिया, थकान या पेट दर्द जैसे लक्षण महसूस होते हैं तो बिना देरी के चिकित्सक से सलाह लें।

डाक्टरों की हड़ताल से हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं रहीं ठप

प्रदेश के डेढ़ सौ से अधिक अस्पतालों में नहीं चली ओपीडी

- पोस्टमार्टम सेवाएं भी कई जिलों में रहीं बंद
- डिलीवरी की सुविधा बंद होने से गर्भवती महिलाएं रहीं परेशान

शिखा शर्मा। चंडीगढ़

हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में गुरुवार को स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप रहीं। एक तरफ हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएस) के आह्वान पर डाक्टरों ने ओपीडी व इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर हड़ताल की। हड़ताल के कारण प्रदेश में पूरे दिन जहां मरीज परेशान होते रहे वहीं चंडीगढ़ में बैठकों का दौर जारी रहा।

प्रदेश के डेढ़ सौ से अधिक अस्पतालों में गुरुवार को दिनभर हड़ताल रही। ओपीडी में आने वाले मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जिलों में तो पोस्टमार्टम भी नहीं किए गए। सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी की सुविधा भी बंद है। इस वजह से मरीजों को अस्पतालों में आकर भटकना पड़ रहा है। सरकार ने हालात बिगड़ते देख मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों को मरीजों के इलाज के लिए बुलाया है।

एसोसिएशन के प्रधान डॉ.राजेश ख्यालिया ने कहा कि कई मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ी है। हड़ताल के चलते रेवाड़ी में पोस्टमार्टम नहीं हो सका। जिसकी वजह से शव को रोहतक पीजीआई में भेज दिया गया है। अंबाला, पानीपत में मरीजों को वापस लौटना पड़ा। सोनीपत के सिविल अस्पताल में भी मरीजों की ऐसी ही स्थिति रही।

पानीपत सिविल अस्पताल में सीएमओ ने खुद मरीजों को देखा। भिवानी सिविल सर्जन डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने बैकल्पिक प्रबंध किए जाने का दावा किया लेकिन यहां से भी मरीज को परेशानी की सूचना है। रेवाड़ी की ही तरह फतेहाबाद में भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज पूरा दिन स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हाल ही में मैंने मुख्यमंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ इन मामलों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक बैठक की थी। हम आपकी मांगों के महत्व को समझते हैं और इसके लिए हम एक ऐसा समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं जो सभी संबंधित पक्षों के लिए भी संतोषजनक हो। उन्होंने कहा, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हड़ताल से मरीजों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध बनी रहें, खासकर उन लोगों के लिए जो जरूरत के समय हम पर निर्भर रहते हैं।

गुरुग्राम में इंटर्न व रिटायर्ड डॉक्टर्स के भरोसे रहा अस्पताल

गुरुग्राम में डॉक्टर्स की हड़ताल के दौरान कार्ड की लाइन में लगे मरीज व अस्पताल में मरीज को घुमाते तीमारदार।

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को डॉक्टर्स ने हड़ताल की। सभी डॉक्टर्स छुट्टी पर रहे। इस दौरान मरीज इलाज के लिए भटकते रहे। इंटर्न और रिटायर्ड डॉक्टर्स ने ही मरीजों को देखा। इनकी कम संख्या होने के चलते मरीजों को काफी परेशानी हुई।

हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टर्स ने गुरुवार को पूरी तरह हड़ताल रखी। ओपीडी के समय सुबह आठ बजे से ही मरीज सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल में पहुंचने लगे थे। ओपीडी कार्ड, ओपीडी व दवाईयों के लिए कई घंटे तक मरीज भटकते रहे। अस्पताल में जहां रोजाना तीन हजार तक ओपीडी में मरीज पहुंचते थे, गुरुवार को हड़ताल के कारण 1582 मरीजों के ही ओपीडी कार्ड बने। बहुत से मरीज वापस ही लौट गए। गुरुग्राम, सोहना, पटौदी व फर्रूखनगर के अस्पतालों के अलावा सभी पीएचसी में करीब 175 डॉक्टर्स हैं, जिनमें से 160 डाक्टर्स हड़ताल पर रहे। 15 डॉक्टर्स सीएमओ ऑफिस पर रहे। वे हड़ताल में शामिल नहीं हुए। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते सीएमओ डॉ. विरेंद्र यादव ने इंटर्न व रिटायर्ड डॉक्टर्स को ओपीडी, इमरजेंसी में तैनात किया। जो मरीज अस्पताल में पहुंचे उन्हें इलाज के नाम पर खानापूर्ति की गई। मरीजों को डॉक्टर्स ही नहीं स्ट्रेचर, अटेंडेंट तक नहीं मिल पाए।

कुमारी सैलजा हरियाणा में निकालेंगी कांग्रेस संदेश यात्रा

- यात्रा के पोस्टरों से उदयभान, हुड्डा व दीपक बाबरिया गायब

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा 27 जुलाई से हरियाणा में कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू करने जा रही हैं। यात्रा से पहले जारी किए गए पोस्टर ने कांग्रेस की गुटबाजी को उजागर कर दिया है।

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के एक गुट द्वारा हिसाब मांगो कार्यक्रमों का आयोजन करके सरकार को घेरा जा रहा है। इस बीच अब कुमारी सैलजा भी शनिवार से फील्ड में उतर रही हैं। कुमारी सैलजा ने लोकसभा चुनाव से पहले भी हरियाणा के कुछ हिस्सों में यात्रा निकाली थी। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने पहले सैलजा की यात्रा को उनकी निजी यात्रा बताया था लेकिन बाद में पत्र जारी करके उसे कांग्रेस का कार्यक्रम करार दिया था।

अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली दरबार के नेताओं की परोक्ष सहमति के बाद ही कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। सैलजा ने जब पिछली बार यात्रा निकाली थी तो उस समय किरण चौधरी उनके साथ थीं। अब किरण चौधरी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा से कांग्रेस में आ चुके हैं। इन समीकरणों के चलते सैलजा की यात्रा का स्वरूप भी बदला हुआ है।

गायब युवक को आगरा नहर में ढूंढा

- तीन दिन पहले बघौला से गायब हुआ था युवक
- डीग गांव में नहर के समीप खड़ी मिली थी कुलदीप की बाइक

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

कुलदीप का फाइल फोटो।

बघौला गांव से 25 वर्षीय एक युवक कुलदीप उर्फ कोकी संदिग्ध परिस्थति बाइक समेत गायब हो गया। जिसका तीन दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने उसकी बाइक डीग गांव में आगरा नहर किनारे से बरामद की है। इसके आधार पर उसकी आगरा नहर में तलाश की जा रही है। इसे लेकर भौंडसी से एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई, जो डीग गांव से छज्जू नगर तक गायब युवक की तलाश में जुटी है।

बघौला गांव के रहने वाले गिर्राज के बेटे टेकचंद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका भाई कुलदीप उर्फ कोकी 22 जुलाई की शाम घर से बाइक लेकर निकला था, जो देर रात तक वापस नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू की गई। जिसकी बघौला पुलिस चौकी में सूचना दी गई। शिकायत मिलते ही बघौला चौकी पुलिस ने गुमशुदगी कर रपट दर्ज की। इसे लेकर पुलिस की दो टीमें बनाई गई हैं। बुधवार को पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से डीग से लेकर छज्जू नगर तक आगरा नहर में गायब युवक की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका है। इसके बाद पुलिस ने उच्च अधिकारियों को सूचना देकर भौंडसी से एनडीआरएफ की टीम बुलाई है, ताकि गोताखोरों की मदद से नहर में युवक की तलाशी की जा सके।

गुरूवार दोपहर बाद करीब पांच बजे एनडीआरएफ की टीम डीग गांव पहुंची। जहां एनडीआरफ की टीम ने नहर में युवक की तलाशी शुरू कर दी है।

सुनीता केजरीवाल संभालेंगी हरियाणा में प्रचार का जिम्मा

- आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान, कहा- 15 दिन में करेंगे 45 रैलियां

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लिए चुनाव प्रचार अभियान का ऐलान कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा में प्रचार का जिम्मा संभालेंगी।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी अगले 15 दिनों में 45 बड़ी रैलियां करने जा रही है।

आम आदमी पार्टी 15 दिनों में हर दो विधानसभा में एक चुनावी रैली करेगी। जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) डॉ. संदीप पाठक और प्रदेश की पूरी लीडरशिप इस अभियान में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई को बरवाला और डबवाली में रैली करके की जाएगी। इन रैलियों को पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान संबोधित करेंगे।

पीएम के समक्ष रखा हिरणों की मौत का मामला

- कुलदीप बिश्नोई ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उठाई कठोर कानून बनाने की मांग

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

राजस्थान में हिरणों की मौत का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरबार में पहुंच गया है। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात करके यह मुद्दा उठाया।

भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने परिवार समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कुलदीप बिश्नोई पिछले कई दिनों से दिल्ली दरबार में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात में उनके साथ विधायक पुत्र भव्य बिश्नोई, पत्नी रेणुका बिश्नोई तथा पुत्र वधु एवं आईएएस परी बिश्नोई साथ रही।

कुलदीप बिश्नोई ने इस मुलाकात के दौरान हरियाणा की राजनीति पर चर्चा की है। कुलदीप बिश्नोई लोकसभा चुनाव के दौरान हिसार से भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार थे लेकिन पार्टी ने उनकी टिकट काटकर रणजीत चौटाला को मैदान में उतार दिया।

भाजपा में आने के बाद बिश्नोई हरियाणा व राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं। राजनीतिक मुद्दों के अलावा कुलदीप बिश्नोई ने राजस्थान में हिरणों की मौत का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया है। बिश्नोई समाज के लोगों में हिरणों की मौत से रोष है।

स्कूटी सवार युवकों को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, एक की मौत

- दिल्ली से बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे दोनों दोस्त

पायनियर समाचार सेवा। पलवल/होडल

दिल्ली से बांके बिहारी मंदिर वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे स्कूटी सवार दो दोस्तों को अज्ञात ट्रैक्टर ट्राला चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी सवार दोनों युवक सड़क पर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक के मामा की शिकायत पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी दौलतराम के अनुसार, जितेंद्र निवासी अशोक विहार दिल्ली ने बताया कि उसका भांजा जतिन 22 वर्ष और उसका दोस्त तरुण 26 वर्ष गुरुवार सुबह तीन बजे वृंदावन जा रहे थे, जब वह गौढोता चौक पहुंचे तो अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली चालक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी।

कुवि कुलपति ने स्पेन यात्रा के अनुभव राज्यपाल से किए साझा

कुरुक्षेत्र। हरियाणा के राज्यपाल व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू) की ओर से आयोजित स्पेन दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा को उनके दौरे की सफलता के लिए बधाई दी और आशा प्रकट की कि आने वाले समय में स्पेन और हरियाणा राज्य के विश्वविद्यालयों के बीच जो एमओयू होंगे उससे स्पेन के विद्यार्थी भी हरियाणा में आकर यहां की शिक्षा पद्धति एवं संस्कृति से रूबरू होंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने गुरुवार को हरियाणा के राज्यपाल एवम् कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय को बताया कि स्पेन में लगभग 80 विश्वविद्यालय हैं जिनमे से 45 सरकारी एवम बाकी गैर सरकारी विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों की वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी है। दौरे के दौरान एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (ए.आई.यू) के क्रू जो कि स्पेन यूनिवर्सिटी के रेक्टर (भारतीय विश्वविद्यालयों के कुलपति पद के समकक्ष) की एक एसोसिएशन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

PUBLIC NOTICE

It is informed that my client Sanjay Rana S/o Sh. Amar Pal Sinah & his wife Pushpa Rana R/o H-17/121, Ratiya Marg, Sangam Vihar, New Delhi-110080 have disowned and debarred their son Kamal Rana R/o above address. from their all movable & immovable properties. My client shall not be responsible in any way of his acts or claim as they have broken all relation, whatsoever, him forever.

S.P. Verma (Advocate)
Ch. No.66, Saket Court Complex,
New Delhi-110017 # 9871140140

THE PIONEER CLASSIFIEDS

CHANGE OF NAME

I, Prince S/o Shri Bablu Kumar, R/o House-No, J- 664, 5/35, Kirti Nagar Industrial Area, New Delhi-110015, that I have changed my name from Prince Kumar to Prince for all future purposes.
PD(623)C

LOST & FOUND

I, Lost my original Registered Sale Deed dated 02/09/2015 of House No E837,of entire 2nd floor Chittranjan Park ND-19 executed by Suprakas Bhattacharjya in favour of Prashant Mallick and Maya Mallick has been lost at Market No 2 CR Park area.Finder may contact Gitaanjali Jayantilal Mahida 9818111168
PD(625)A

PUBLIC NOTICE

Lost original English DDA ALLOTMENT LETTER Vide Doc. No. F1815831185 HBM/NP Dated 05/06/1986 Of Flat no 77-C, Pocket A, 2nd Floor, Vikaspuri Puri EXTN, Vikaspuri, West Delhi-110018 on the name of Harindra Partap Singh. Finder contact at Flat No 1039, Plot no 23 Apna Villa Apartment sector-10 Dwarka New Delhi-110075.

सार्वजनिक सूचना

जन साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रविंदर कुमार पाहवा और श्री सुभाष चंद उर्फ सुभाष चंदर, संपत्ति Entire Basement Floor, Entire Ground Floor, Entire First Floor, Entire Second Floor and Entire Third Floor with its terrace rights Built on Property No. B-1/34, area measuring 200 Sq. Yds., i.e., 167.22 Sq. Mtrs., situated at Lajpat Nagar, New दिल्ली, की त्याग/रिलीज़ डीड दिनांक 15.07.2019 और त्याग/रिलीज़ डीड दिनांक 15.07.2019 के द्वारा मालिक थे। दुर्भाग्य से, स्वर्गीय सुभाष चंदर की मृत्यु निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारियों के बाद जीवित रहने के बाद हुई, रीना मल्होत्रा और स्वर्गीय रविंदर कुमार पाहवा की भी मृत्यु हो गई, श्री रविंदर कुमार पाहवा और श्री सुभाष चंद की मृत्यु के बाद निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारियों कोनल पाहवा, नीलम पाहवा के जीवित रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कानूनी उत्तराधिकारी श्रीमती रीना मल्होत्रा, (संपूर्ण बेसमेंट फ्लोर, संपूर्ण ग्राउंड फ्लोर) को पीछे छोड़ते हुए श्री कोनल पाहवा और श्रीमती नीलम पाहवा (संपूर्ण प्रथम तल, संपूर्ण द्वितीय तल और छत के अधिकार के साथ संपूर्ण तृतीय तल) पूर्ण और वैध बन गए हैं। विरासत में मिली संपत्ति के मालिक, उपरोक्त संपत्ति को मेरे मुवक्किल यानि एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा वित्तपोषित व बंधक प्रस्तावित है। यदि किसी व्यक्ति (ओं) को इस संपत्ति में कोई आपत्ति या दावा है, तो हमें इस नोटिस की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्न पते पर संपर्क करें। अगर कोई दावा नहीं आया तो यह माना जाएगा की किसी का कोई दावा या हक इस प्रॉपर्टी में नहीं है।

राघव तिवारी, अधिवक्ता
830, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली 110001
Mob.:+91-8076188328

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 09.07.1999 को राजेन्द्र सिंह राव एडवोकेट नि० सराय ख्वाजा फरीदाबाद ने अपने ससुर स्व० श्री भगवान सिंह यादव नि० नजफगढ़ दिल्ली के साथ मिलकर एक 100 वर्गगज का प्लाट खसरा नम्बरान 30/3 व 31/23/2. गांव नजफगढ़ के टोडरमल कालौनी एक्सटेंशन में स्थित है। दोनों ने बराबर-2 हिस्सा इसकी पूरी रकम रूबरू गवाहान अदा करके इसके कागजात मालकान श्री सूरज मान नि० घोषगढ़ डा० जमालपुर हरियाणा से खरीद करके कब्जा हासिल कर लिया था व इसके सभी कागजात विक्रेता के हस्ताक्षर रोबरू गवाहान सत्यापित काजात (IRREVOCABLE) करवाकर हासिल कर लिये थे व इसके बाद हिस्सेदार भगवान सिह यादव से उनके हिस्से की पूरी रकम अदा करके उनका 50 वर्गगज वाला हिस्सा भी मुझ राजेन्द्र सिंह राव एडवोकेट ने दिनांक 13.04.2004 को खरीद कर कब्जा सालिम रकबा 100 वर्गगज का हो गया था जिसका हर प्रकार से पाक साफ कब्जा आज भी मेरे पास बिना किसी व्यवधान के चला आ रहा है।
यदि कोई व्यक्ति फर्जी, झूठे नकली, कागजात के आधार पर अपने आप को इस उपरोक्त सम्पत्ति का मालिक बताता है तो वह ठग व धोखेबाज होगा। उनके साथ अनुबंध, खरीददारी व लेन देन करने वाला स्वयं जिम्मेवार होगा और निश्चित रूप से उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

फोन न08766200570
दिनांक 25.07.2024 निवेदक
राजेन्द्र सिह राव एडवोकेट
गांव व डा.सराय ख्वाजा फरीदाबाद।

PUBLIC NOTICE

It is hereby brought to the Notice of general public that my clients (i) Ketan Kaher S/o Brij Kumar, R/o M-117, Guru Harkishan Nagar, Paschim Vihar, New Delhi-110087 and (ii) Varun Mehta S/o. Late Naveen Mehta, R/o 9/308, Sunder Vihar, Paschim Vihar, New Delhi-110087, intends to purchase the Entire First Floor with undivided one-half share in Roof/Terrace Rights (over and above first floor), being Part of Entire Property Bearing No. 92, Measuring 200 Square Yards, at Block- J, in the Layout Plan of the Reserve Bank Staff Co-operative House Building Society Ltd., also known as Reserve Bank Enclave (R.B.I Colony), Situated at Paschim Vihar, New Delhi-110063, with undivided one-half share in the land underneath (which at present is leasehold property) from (i) Aditya Sharma Late B.S. Sharma, R/o. B-101,Sannmati Kunj, Plot No. 19A, Dwarka Sector-6, Delhi-110075 and (ii) Smt. Namita Sharma W/o Late Bhim Sen Sharma, R/o G-75, Harsh Path, Shyam Nagar Extension, New Sanganer Road, Jaipur, Rajasthan-302019, who have represented themselves to be absolute and exclusive owners of the said property and have assured that the said property is free from all sorts of encumbrances (registered or un-registered) including but not limited to prior sale, gift, mortgage, charges, lien, claims, disputes etc. Therefore any person(s) having any claim in respect of the above referred properly or part thereof by way of sale, exchange, mortgage, charge, gift, maintenance, inheritance, possession, lease, tenancy,sub tenancy,lien,license, hypothecation,transfer of title or beneficial interest under any trust right of prescription or preemption or under any Agreement or other disposition or under any decree, order or Award or otherwise claiming, howsoever, are hereby requested to make the same known in writing together with supporting documents to the undersigned at their office within Fifteen (15) days from the publication of this notice, failing which my client shall conduct the purchase and any claim and/or objection if any shall be considered or waived & abandoned and shall not be binding upon my client
Date:22/07/24, Archit Singh Tomar, Place-New Delhi

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large, on behalf of our client, **Mr. Prameet Kumar S/o-Mr. Prem Chand** R/o 164, Nawada Birondi, Chakarsenpur, Kasna, Gautam Budh Nagar, **(Mortgagor)**", that Mr. Prem Singh alias **Mr. Prem Chand** was the owner of the Scheduled Property vide Revenue Record, and Mr. Prem Singh alias Mr. Prem Chand Gifted the Scheduled Property to **Mr. Prameet Kumar**, vide Gift Deed dated 25.07.2024 Doc. No. 22462, Book No. 1, Vol. No. 45179, Page No. 1-16, on dated 25.07.2024 **SRO-Sadar, Greater Noida.**
Same property Mr. Prameet Kumar (Mortgagor) mortgage the schedule property with Fed Bank Financial Services Ltd. Kirti Nagar Branch, New Delhi. If any person race any objection for mortgaging the schedule property please **race your Objection with documentary proof within 7 days** of Publication below address: -

Schedule of Property

Residential area measuring- 400 sq. yds., Out of Khasra No. 767, Situated at Village Kasna, Pargana Dankor, Tehsil & Distt. G. B. Nagar 201310. hereinafter referred to as **"said property"**.

Sachin Maheshwari & Associates (SMA)
Sachin Maheshwari Advocate
Molarband Extn. Badarpur Border, New Delhi.
Phone: 011-69653588, Mob.-9911380328

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large, on behalf of our client, **Mr. Prem Chand S/o Mr. Kishan Lal** R/o 164, Nawada Birondi, Chakarsenpur, Kasna, Gautam Budh Nagar, **Mr. Prem Chand declare that Mr. Prem Chand & Mr. Prem Singh are the same person** and Mr. Prem Singh alias Mr. Prem Chand was the owner of the Scheduled Property vide Revenue Record, and Mr. Prem Singh alias Mr. Prem Chand Gifted the Scheduled Property to **Mr. Prameet Kumar,** vide Gift Deed dated 25.07.2024 Doc. No. 22462, Book No. 1, Vol. No. 45179, Page No. 1-16, on dated 25.07.2024 **SRO-Sadar, Greater Noida.**
Same property Mr. Prameet Kumar (Mortgagor) mortgage the schedule property with Fed Bank Financial Services Ltd. Kirti Nagar Branch, New Delhi. If any person race any objection for mortgaging the schedule property please **race your Objection with documentary proof within 7 days of Publication below address: -**

Schedule of Property

Residential area measuring- 400 sq. yds., Out of Khasra No. 767, Situated at Village Kasna, Pargana Dankor, Tehsil & Distt. G. B. Nagar 201310. hereinafter referred to as **"said property"**.

Sachin Maheshwari & Associates (SMA)
Sachin Maheshwari Advocate
Molarband Extn. Badarpur Border, New Delhi.
Phone: 011-69653588, Mob.-9911380328

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,
सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **विशाल आनंद और लिज़ा आनंद** को **26.10.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLNOD00291690** की राशि **रू.26,44,646.96 /- (रुपए छब्बीस लाख चौवालीस हजार छ सौ छियालीस और छियानवे पैसे मात्र)** और **29.09.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।
धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वियन करके **24.07.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।
विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू.26,44,646.96 /- (रुपए छब्बीस लाख चौवालीस हजार छ सौ छियालीस और छियानवे पैसे मात्र) 29.09.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था)** के आधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
संपुर्ण दुसरी मंजिल, रूफ राइट्स के साथ, प्लॉट नं.एफ-88, ब्लॉक एफ, एसएलएफ वेद विहार, लोनी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश -201012 ।

सही/-
दिनांक :24.07.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान :गाज़ियाबाद सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था)

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,
सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **प्रदीप माहेश्वरी, अनिता माहेश्वरी और परितोष माहेश्वरी** को **29.10.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. **HHLNOI00416661** की राशि **रू.28,16,616.45 /- (रुपए अठ्ठाईस लाख सोलह हजार छ सौ सोलह और पैंतालीस पैसे मात्र)** और **27.10.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।
धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **(4)** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वियन करके **24.07.2024** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।
विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशि रू.28,16,616.45 /- (रुपए अठ्ठाईस लाख सोलह हजार छ सौ सोलह और पैंतालीस पैसे मात्र) 27.10.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था)** के आधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
फ्लैट नं.युजीएफ 1, ऊपरी तल मंजिल, सामने बाईं ओर, प्लॉट नं.बी42, ब्लॉक बी, एसएलएफ वेद विहार, लोनी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश -201010 ।

सही/-
दिनांक :24.07.2024 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान :गाज़ियाबाद सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनांस लिमिटेड से जाना जाता था)

ACRE MAKING ASSETS WORK
एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय : यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी – 66, जी – ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051 । टेलीफोन : 022 68643101
पंजीकृत कार्यालय : 14वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019
ई-मेल : acre.arc@acreindia.in । वेबसाइट : www.acreindia.in । CIN : U65993DL2002PLC115769

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHENOD00206434 1. सोमदत्त शर्मा 2. विभा शर्मा	यूनिट नंबर 0208, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-एच, सुपरटेक अप कंट्री प्लॉट नंबर टीएस-1, सेक्टर 17-ए, यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा -201301 उत्तर प्रदेश	31.12.2022	रु. 1,94,183.12/- (रुपए एक लाख चौरानवे हजार एक सौ तिरासी और बारह पैसे मात्र) 12.06.2024 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।
उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।
उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''।
सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।
''किसी भी शिकायत के लिए आप श्री मोहम्मद शारिक मलिक, शिकायत निवारण अधिकारी से, फोन नंबर 011 - 66115609, ईमेल : complaint@acreindia.in पर संपर्क कर सकते हैं. विस्तृत नीति संगठन के अंदर शिकायत निवारण तंत्र पर https ://www.acreindia.in/compliance पर देखी जा सकती है''।

कृते एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड
ए सी आर ई - 102 - के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए
स्थान : नोएडा प्राधिकृत अधिकारी

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLNOI00327564 1. देवेंद्र 2. सुशीला सिंह	फ्लैट नंबर यूजी-01, ऊपरी तल मंजिल, सामने की तरफ प्लॉट नंबर 136, विक्रम एन्क्लेव कॉलोनी, गांव पसौंदा परगना लोनी, गाज़ियाबाद-201005, उत्तर प्रदेश	04.07.2024	रु. 12,71,444.15/- (रुपए बारह लाख इकहत्तर हजार चार सौ चौवालीस और पंद्रह पैसे मात्र) 09.07.2024 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क्र. HHLNDA00367552 1. उर्मिला 2. हेमंत 3. संजय मेहरा (गारंटर)	फ्लैट नंबर- 0106, पहली मंजिल, टावर-ए2, सुपरटेक गोल्फ विलेज, टीएस-5, सेक्टर 22-डी, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्ध नगर-201303, उत्तर प्रदेश	09.12.2023	रु. 5,94,938.87/- (रुपए पांच लाख चौरानवे हजार नौ सौ अड़तीस और सत्तासी पैसे मात्र) 10.07.2024 के अनुसार
3.	कर्ज खाता क्र. HHLNOD00497933 1. रफीक खान 2. रुकसाना उर्फ रुकसाना खान 3. अयूब खान (गारंटर)	प्लॉट नंबर सी-53, साइट-सी हाउसिंग, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, सूरजपुर, गांव गुलिस्तानपुर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा-201311, उत्तर प्रदेश	04.07.2024	रु. 23,67,293.92/- (रुपए तेईस लाख सड़सठ हजार दो सौ तिरानवे और बानवे पैसे मात्र) 12.07.2024 के अनुसार
4.	कर्ज खाता क्र. HHLRHN00512180 1. अरुण कुमार 2. ज्योति	फ्लैट नंबर एफ.एफ.-4, पहली मंजिल, एलआईजी, पीछे बाईं तरफ (छत के अधिकारों के बिना), प्लॉट नंबर बी-245, स्वर्ण जयंतीपुरम, गाज़ियाबाद-201013, उत्तर प्रदेश	08.06.2024	रु. 14,80,355/- (रुपए चौदह लाख अस्सी हजार तीन सौ पचपन मात्र) 08.07.2024 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।
उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।
उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चो, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''
सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
स्थान : गाज़ियाबाद/गौतम बुद्ध नगर/नोएडा प्राधिकृत अधिकारी

बजट 2024

संतुलन के प्रयास

बजट 2024 विकास-केन्द्रित है, पर इसमें लोकरंजक तत्व हैं तथा 'राजग' सहयोगियों के सरोकारों को संबोधित करने के प्रयास हैं। वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट 23 जनवरी, 2024 को पेश किया। इसका लक्ष्य भारत की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करते हुए सामाजिक समानता तथा राजग सहयोगियों के हितों की पूर्ति भी है। यह बजट आर्थिक विकास तथा राजनीतिक लाभों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इस बजट में ढांचागत संरचना, हरित ऊर्जा पहलों तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था हेतु आबंटनों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए विकास के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। केन्द्रीय बजट 2024-25 मैक्रोइकोनामिक प्रगति तथा राजकोषीय स्थिरता पर केन्द्रित है। इसमें गरीबों के लिए कल्याणकारी उपाय भी शामिल हैं जो सफलता के लिए प्रभावी नीतिगत क्रियान्वयन पर निर्भर होंगे। हालांकि, राजकोषीय घाटे की स्थिति सुधरी है और यह जीडीपी का 4.9 प्रतिशत हो गया है, पर काफी असमानतायें बनी हुई हैं। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाया गया है, पर शहरी-ग्रामीण तथा आय असमानतायें बनी हुई हैं। इस बजट में अंतरिम बजट की तरह ही कृषि, ग्रामीण विकास, आवास तथा रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई को केन्द्र में रख कर आबंटन किया गया है। नए कदमों में पहली बार कर्मचारियों को सीधे भुगतान तथा सेवायोजकों को प्रोत्साहन शामिल हैं ताकि वे नौकरियों की संख्या बढ़ाएं। लेकिन बजट में लगभग 5.08 प्रतिशत मुद्रास्फीति को समुचित रूप से संबोधित करने के प्रयास नहीं हैं। विनिर्माण को सहायता देने के लिए सरकार ने एमएसएमई के

लिए क्रेडिट गारंटी तथा मुद्रा लोन की सीमायें बढ़ाने के साथ अन्य पहलें भी की हैं। 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर'-डीपीआई के माध्यम से कृषि व्यवहारों को प्रोत्साहन देने हेतु औद्योगिक पार्कों के विकास के साथ ही 'प्राकृतिक खेती' को सहायता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद बजट की सफलता प्रभावी क्रियान्वयन तथा व्यापक आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने में निहित है।

केन्द्रीय बजट 2024 में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए नौजवानों के कौशल संवर्धन की समग्र योजना पेश की गई है। इसके अंतर्गत पांच साल में 20 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों-आईटीआई का उच्चीकरण कर इनमें उपयुक्त उन्मुखीकरण हेतु व्यवस्थायें की जाएंगी। इनके पाठ्यक्रम की विषयवस्तु तथा डिजाइन उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। बजट के सकारात्मक तत्वों में ढांचागत संरचनाओं में भारी निवेश शामिल है जिससे रोजगारों का सृजन होगा तथा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बजट में कुछ चुनौतियां भी शामिल हैं। खर्च की महत्वाकांक्षी योजनाओं से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है जिससे मैक्रोइकोनोमिक स्थिरता व मुद्रास्फीति नियंत्रण की चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। बजट में प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अतीत में अनेक प्रकार के विलंब व अक्षमतायें दिखी हैं। 2024 के बजट में एक लोकरंजक दृष्टिकोण भी है जिसका उद्देश्य अपने सहयोगी-नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू की चिन्ताओं को संबोधित करना है। इसके लिए उदारता से धन आबंटन किया गया है। ढांचागत विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण तथा सामाजिक कल्याण क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाने के माध्यम से यह बजट सरकार द्वारा उन लोगों का समर्थन पुन: प्राप्त करने का प्रयास करता है जो उससे थोड़ा असंतुष्ट हो गए थे।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार

भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अयोध्या व उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिले चुनावी झटके के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मूलाधारों पर आत्मावलोकन की आवश्यकता सामने आई है।

सिद्धार्थ मिश्रा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अयोध्या व उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिले चुनावी झटके के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मूलाधारों पर आत्मावलोकन की आवश्यकता सामने आई है। सिद्धार्थ मिश्रा ने 'हिंदू परंपरा' में ईश्वर के बारे में चर्चा करते हुए किसी आंदोलन से अलग रहते हुए कहा है कि भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं, वे हमेशा सत्य बोलते हैं तथा 'त्रिकालदर्शी' हैं, यानी वे अतीत, वर्तमान व भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरितमानस' में भगवान शंकर अपनी पत्नी देवी सती से कहते हैं, 'होइहै सोई जो राम रचि राखा', अर्थात वही होगा जिसका निर्धारण पहे ही भगवान राम ने कर रखा है। भगवान शंकर देवी सती से कहते हैं कि राम 'परम ब्रह्म' हैं और वे प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित करते हैं। भगवान राम के अनुयाइयों के लिए इस चौपाई का अर्थ राम के देवत्व और उनकी महिमा से है।

इस चौपाई के प्रारम्भ के बाद तुलसीदास कहते हैं, 'को करि तर्क बढ़ावै शाखा', अर्थात निरर्थक चर्चा के माध्यम से उनके निर्णय पर विवाद करने का कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद यह चौपाई इस कथन के साथ समाप्त होती है कि 'अस कहि लगे जपन हरिनामा, गई सती जहं प्रभु सुखधामा।' इस कथन का अर्थ मूलत: यही है कि जो लोग राम की शरण में जाते हैं उनको उसी प्रकार शांति प्राप्त होती है जिस प्रकार भगवान शंकर की पत्नी देवी सती को प्राप्त हुई थी।

हालांकि, भगवान राम में गोस्वामी तुलसीदास के विश्वास में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं है कि मनुष्यों को उसके अपने 'कर्म' के आधार पर फल प्राप्त होता है और राम की 'रचना' पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जो लोग भगवान राम को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित करने का प्रतीक मानते हैं, उनको अपने 'कर्म' का आत्मावलोकन करना चाहिए जिसके कारण भगवान राम की 'रचना' सामने आई है। ऐसे तत्वों को हालिया लोकसभा चुनाव में अयोध्या में पराजय से झटका लगा है और यह भी एक प्रतीक है। इसका विस्तार भगवान राम के क्षेत्र अवध और उसके आगे तक हुआ है। हालांकि, इसके अनेक अन्य सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक व सांगठनिक कारण भी हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि 'रामजन्मभूमि आंदोलन' ने 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की अवधारणा को पुनर्जीवित करने और इसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

सैकड़ों सालों से प्रतीक्षित भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से भगवान राम में लोगों की आस्था और मजबूत होनी चाहिए थी और इसका स्वाभाविक परिणाम भारतीय जनता पार्टी-भाजपा को मिलने वाले चुनावी लाभ के रूप में सामने आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। प्रख्यात अंग्रेजी कवि टी.एस. इलियट ने अपनी लोकप्रिय कविता 'हालो मैन' में लिखा है, 'दुनिया इसी प्रकार समाप्त होती है, किसी विस्फोट के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत हल्की सी आवाज से'। इसी कविता के प्रारंभ में इलियट ने लिखा था, 'बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रियेशन, बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पांस फाल्स द शैडो', अर्थात अवधारणा और रचना के बीच तथा भावनाओं और प्रतिक्रिया के बीच खाली स्थान होता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि रामजन्मभूमि आंदोलन की समाप्ति चुनावी रूप से किसी विस्फोट के बजाय एक हल्की सी आवाज के रूप में क्यों हुई।

इस वर्ष जनवरी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इस शताब्दी का महत्वपूर्ण आयोजन था। अनेक राज्यों में भगवान राम के प्रतीकों वाली फहराती ध्वजाओं तथा लोकप्रिय बालीवुड परंपराओं के अनुसार इस अवसर पर होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों ने संदेहवादियों को भी विश्वास दिला दिया था कि यह आंदोलन हमारी संस्कृति और प्रकृति की आत्मा है। यह आयोजन असाधारण कैमरा कवरेज तथा एकदम सटीक कार्यक्रम के साथ आमतौर से निराशाजनक परिवेश में संभावित 'राम राज्य' के उदय की व्यापक उम्मीदों से भरा था। भगवान राम के शासन यानी 'राम राज्य' को शासन का आदर्श रूप माना जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस आयोजन ने भाजपा को अच्छा चुनावी लाभ नहीं दिलाया। पार्टी के रणनीतिकार इस नैतिक रूप से निराशाजनक चुनावी धक्के से हतप्रभ रह गए। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पैरोकारों के लिए 'अवधारणा और रचना तथा भावनाओं व प्रतिक्रिया के बीच खाली स्थान' का पता तब तक नहीं चला जब तक वे 'वीआईपी रूट' और लाखों लोगों द्वारा भगवान रामलला के 'दर्शन' की प्रतिध्वनियों से बाहर नहीं निकले। राम राज्य का अर्थ समाज की उस आदर्श स्थिति से है जिसकी इच्छा भगवान राम ने की थी। इसमें पूर्ण सद्भावना, न्याय, धर्म व समृद्धि शामिल हैं जहां लोग शांति और प्रसन्नता से रह सकें।

महात्मा गांधी ने इस व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि सत्य ही राम राज्य है जिसमें राजाओं और निर्धनों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित होंगे। भगवान रामलला के दर्शनों की लाइनों में खड़े गरीब रामभक्तों से पूछें कि क्या आदर्श राज्य आ गया है। रामजन्मभूमि मंदिर में पूरी 'दर्शन' प्रक्रिया के प्रबंधन पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि यह संभवत: 'राम राज्य' के माडल के अनुकूल न हो। मंदिर प्रवेश से गर्भ गृह तक लाल सैंडस्टोन का बिना कारपेट से ढका मार्ग भयानक गर्मी में भक्तों के लिए बहुत कष्टदायक है। यदि गर्म पत्थरों की फर्श पर कारपेट बिछा दिए जाते तथा रास्ते में भयानक गरमी में राहत देने के लिए कारगर एयर कूलर तथा लाइन में लगे लोगों की प्यास बुझाने के लिए वाटर कूलर लगा दिए जाते तो बहुत अच्छा होता। इससे स्पष्ट होता कि मंदिर प्रशासन यहां आने वाले रामभक्तों व श्रद्धालुओं की 'देखभाल' करता है और यह उसके प्रबंधन दायरे से बाहर भी नहीं था।

लेकिन विडंबना है कि मंदिर प्रबंधन तथा वहां व्यवस्था देखने वाले लोगों की ओर से देखभाल के ऐसे कदम नहीं उठाए गए अथवा वे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए नाकाफी थे। सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर अपनी संरचना और वास्तु के दृष्टिकोण से भव्य है और दावा किया जाता है कि सैकड़ों वर्षों तक उसे किसी प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मंदिर के भीतर का पूरा परिवेश 'सेवा' के बजाय 'सुरक्षा' के दृष्टिकोण से ज्यादा प्रभावित लगता है। ऐसे में प्रशिक्षण विहीन निजी सुरक्षा गार्डों की भीड़ एक और समस्या खड़ी करती है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा मांगी गई जानकारियों पर इन सुरक्षा गार्डों के असभ्य जवाबों से मंदिर आंदोलन के बारे में अनेक लोगों की बची-खुची श्रद्धा को भारी धक्का लगता है।

लेकिन इन कष्टों व असुविधाओं के बावजूद रोज लाखों भक्त देश के सभी कोनों से भगवान रामलला के दर्शन के लिए आते हैं। इनके लिए अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करने तथा उनको उपयुक्त जानकारियां देने के प्रयास किए जाने चाहिए। बालीवुड की सुपरहिट फिल्म 'नील कमल' में प्रख्यात गीतकार साहिर लुधियानवी की ये पंक्तियां बहुत मशहूर हैं-'मेरे रोम रोम में बसने वाले राम'। इसका अर्थ है कि भगवान राम का सभी मनुष्यों में वास है।

सालों से गाया जाने वाला यह गीत अनेक रामभक्तों की भावनाओं को उजागर करने वाला है। लेकिन यदि अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालु राम भक्तों के कष्टों का निवारण नहीं होता है तथा मंदिर प्रशासन का उनके प्रति सेवा भाव जाग्रत नहीं होता है तो इससे 'राम मंदिर आंदोलन' से जुड़े लोगों के प्रति करोड़ों रामभक्तों में श्रद्धा की भावना नहीं जाग्रत होगी।

निश्चित रूप से इन परेशानियों के बावजूद देश-विदेश के करोड़ों भक्तों की भगवान राम के प्रति आस्था में कमी नहीं आएगी, पर वह मंदिर प्रशासन तक विस्तार नहीं लेगी।

आम बजट: एक आलोचनात्मक विश्लेषण

प्रियंका चतुर्वेदी
(लेखिका शिवसेना नेत्री व राज्यसभा सांसद हैं)

नव निर्वाचित गठबंधन सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। भारत की वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया, और एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। भारत के लोगों से बहुत सारे वादे किए गए थे और उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थीं - बेरोज़गारी, महंगाई, स्थिर आय - कोई उम्मीद कर सकता था कि आम चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा कुछ सबक सीखेगी और सही रास्ता अपनाएगी। हालाँकि यह देखना निराशाजनक था कि जन की बात को नज़रअंदाज़ करने की वही गलती हुई, मैडम मंत्री ने भी प्रधानमंत्री की तरह मन की बात भाषण दिया।

यह केंद्रीय बजट होना था, लेकिन अब इसे आसानी से प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना की घोषणा कहा जा सकता है, जिसमें उन राज्यों के लिए बड़े वित्तीय पैकेज निर्धारित किए गए हैं जो उनके गठबंधन सहयोगियों द्वारा चलाए जा रहे हैं और जिनके समर्थन की उन्हें अपनी सरकार को निर्बाध रूप से चलाने के लिए ज़रूरत है - बिहार में जेडीयू और आंध्र प्रदेश में टीडीपी। जबकि बिहार के लिए 59000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई, यह आंध्र प्रदेश के लिए 15000 करोड़ था।

हालांकि, विशेष दर्जे की उनकी मांग पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। अन्य राज्यों के हितों की अनदेखी करके राजनीतिक रूप से प्रेरित राज्य बजट आवंटन करना भविष्य की सरकारों के लिए गलत मिसाल कायम करता है। ये फंड आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहे हैं। गठबंधन द्वारा संचालित महाराष्ट्र, एक ऐसा राज्य जो केंद्र को सबसे अधिक कर देता है, को कई विपक्षी-शासित राज्यों के अलावा (प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना) से कोई विशेष आवंटन नहीं मिला।

यह शर्म की बात है कि केंद्र ने समानता के सिद्धांत की खुलेआम अवहेलना की है और राज्यों के बीच भेदभाव करना चुना है। महाराष्ट्र नए हवाई अड्डों, समर्पित व्यापार / स्मार्ट सिटी, राजमार्गों और सड़कों जैसे उपहार शहर की मांग करता है, लेकिन इन सभी को नजरअंदाज कर दिया गया। महाराष्ट्र के प्रति भाजपा की असली नफरत एक बार फिर उजागर हुई है। विपक्ष के नेतृत्व वाले राज्य ने अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की आगामी बैठक का बहिष्कार करके इस भेदभाव पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। बजट में वित्त मंत्री ने 20-30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम पेश किया और भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में युवाओं के लिए 1 करोड़ इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई। इसका मतलब यह होगा कि प्रत्येक कंपनी को अपने सीएसआर से निर्धारित 5000 रुपये प्रति माह के वजीफे पर 20,000 प्रशिक्षुओं को काम पर रखना होगा।

इसका यह भी मतलब है कि स्नातक/स्नातकोत्तर जो रिकॉर्ड 9.2त्न बेरोजगारी दर का हिस्सा हैं और सार्थक रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस कार्यक्रम से संतुष्ट होना पड़ेगा, जो यह संबोधित नहीं करता है वह अत्यधिक कुशल युवाओं के लिए रोजगार या उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना है। यह कॉर्पोरेट अग्निवीर कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कमरे में मौजूद हाथी को संबोधित करना नहीं है जो बेरोजगारी है बल्कि युवाओं की दुर्दशा का मजाक उड़ाना है। इसी तरह, वित्त मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की बात की, लेकिन लिंग वेतन अंतर को दूर करने, उन्हें अधिक नौकरियां दिलाने, कर छूट के माध्यम से बचत को प्रोत्साहित करने या पारिवारिक बजट चलाने में मुद्रास्फीति के बोझ को कम करने में मदद करने वाली कोई भी पेशकश नहीं की।

संबल एक छत्र योजना है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, नारी अदालत, महिला पुलिस स्वयंसेवक, महिला हेल्पलाइन आदि शामिल हैं। 2020-21 में, जब ये योजनाएं अलग थीं, संबल के तहत शामिल केवल चार के लिए बजट अनुमान 640 करोड़ था, जो कि 24-25 के लिए बजट अनुमान में आवंटित राशि (629 करोड़ रुपये) से अधिक है।

वित्त मंत्री और पूरी सरकार राजकोषीय विवेक बनाए रखने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन यह एक क्लासिक मामला है कि ऑपरेशन सफल रहा लेकिन धैर्य खत्म हो गया, आम जनता के पास पर्याप्त बचत नहीं है, निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और उपभोग वृद्धि अब तक की सबसे कमजोर है।

तथ्य यह है कि 2023-24 में निजी अंतिम उपभोग वृद्धि केवल 4 प्रतिशत थी, जबकि कुल जीडीपी वृद्धि दर 8 प्रतिशत से अधिक थी, जो इसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सरकार एक बार फिर किसानों की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दे पाई है। यदि इंटरनेट सेवाओं को बंद करना और किसानों को विरोध करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले का उपयोग करना पर्याप्त नहीं था, तो केंद्रीय बजट में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी या छूट या कम ब्याज दरों के माध्यम से कृषि ऋण के लिए किसी भी तरह की सहायता का कोई उल्लेख नहीं है। अरबपतियों द्वारा हजारों करोड़ की शादियां करने और बेरोजगार युवाओं द्वारा नौकरियों को लेकर मोहर लगाने जैसी स्थितियों के साथ, केंद्रीय बजट बड़े पैमाने पर धन असमानता को संबोधित करने से चूक गया है।

जबकि युवाओं के रोजगार के लिए पैकेज पेश किए गए हैं, बजट में आबादी के सबसे गरीब और सबसे अमीर वर्गों के बीच की खाई को कम करने पर ध्यान नहीं दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में आय में असमानता को इंगित करने के बावजूद, जिसमें शीर्ष 10 प्रतिशत की आय का एक तिहाई हिस्सा है, किसानों और मजदूरों के उत्थान या धन करों में वृद्धि के उपाय अनुपस्थित हैं। वित्त मंत्री द्वारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स घटाने की घोषणा एक तरह से धोखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स 20त्न से घटकर 12.5त्न ??हो गया है, लेकिन इंडेक्सेशन लाभ समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि संपत्ति, सोना और अन्य गैर-सूचीबद्ध संपत्तियों की बिक्री से होने वाले मुनाफे को मुद्रास्फीति के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा और अधिक राशि पर कर लगेगा, जिससे निवेशकों पर कर का बोझ बढ़ेगा और संपत्ति, सोना और शेयरों में निवेश लाभहीन हो जाएगा। प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना भाजपा के आवश्यक सहयोगियों को पूरा करती है।

जनता, विपक्ष और अधिकांश राज्यों की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। जबकि देश के 90 प्रतिशत लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज करना इस सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आम चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन के बाद भी इसे जारी देखना निराशाजनक है। हालांकि, कोई भी उम्मीद कर सकता है कि संसद में विपक्षी सदस्यों का बढ़ता प्रतिनिधित्व और उत्साह इस सत्र में केंद्रीय बजट में उपयोगी विचार-विमर्श और परिवर्धन का कारण बन सकता है।

आप की बात

उमर अब्दुल्ला से सवाल

उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के दौरान भोजनालयों पर उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के सहयोग के बिना तो हमारे यहां अमरनाथ यात्रा तक संभव नहीं है और अमरनाथ यात्री तो मुस्लिमों के कंधों पर भी यात्रा करते हैं। ऐसे में किसी को उनका धर्म नहीं दिखाई देता है। उनकी बातें ठीक हैं, लेकिन हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि आपके राज्य में आज भी अनेक हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदारी आप जैसे कश्मीरी राजनेताओं की नहीं है? आज भी मौका मिलते ही कश्मीर में हिंदुओं व सेना के जवानों को कौन गोलियां मार कर उनकी जान ले रहा है? अक्सर आप जैसे नेता आतंकियों के बेकसूर और बेगुनाह होने की बात करते तथा पाकिस्तान से बातचीत की पैरोकारी करते हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज हिंदू-मुस्लिम संबंध भारी तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि कुछ मुस्लिम अपनी पहचान छिपाना क्यों चाहते हैं? क्या ऐसा कर वे हिंदुओं के बिजनेसों पर कब्जा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? जब सभी स्थानों पर नाम प्रदर्शित करना सामान्य बात है तो मुस्लिम दूकानदार अपना नाम लिखने से क्यों बचना चाहते हैं?

- **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

मोदी का निरर्थक विरोध

राष्ट्रहित और जनहित में मोदी सरकार कोई भी काम करे, विपक्ष हर वक्त उसकी आलोचना के लिए एक पांव पर खड़ा रहता है। हालांकि विपक्षियों को संवैधानिक अधिकार है कि वे सरकार की खामियों को बतायें और उसमें सुधार हेतु सुझाव दें किन्तु सदैव संसद में शोर-शराबा मचाना ही उसका उद्देश्य रहा है। इस बार संतुलित बजट आया है, पर इसके बावजूद विपक्ष इसका विरोध करते हुए बजट सत्र में बहस में भाग भी नहीं ले रहा है। इस पर राज्यसभा के उप-सभापति ने कहा है कि इस प्रकार संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात करने वाला विपक्ष खुद लोकतंत्र और संविधान का उल्लंघन कर रहा है। विपक्ष ने बजट पर अनेक सवाल उठाए, लेकिन जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देने खड़ी हुईं तो विपक्ष ने उनकी बात सुने बिना वाकआउट कर दिया। इससे लगता है कि विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और इसके लिए सदन, संविधान और लोकतंत्र की गरिमा उसके लिए कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान नेताओं को बुला कर उनको ऐसे समय सरकार के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया, जब सर्वोच्च न्यायालय इससे संबंधित एक मामले पर फैसला दे चुका था।

- **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

ममता की रणनीति

घुसपैठियों के माध्यम से अपना वोटबैंक बढ़ाने के ममता के कुत्सित प्रयासों में अभी भी कमी नहीं आई है। इसका ताजा प्रमाण हाल में दिया बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि बंगलादेश के शरणार्थियों के लिए बंगाल के दरवाजे खुले हैं। उनका यह बयान भारत सरकार को चुनौती के साथ यह भी दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को अपनी निजी जागीर मानती हैं। ममता को समझना चाहिए कि किसी विदेशी को शरण देना या न देना विशुद्ध रूप से केन्द्र सरकार का विषय है। लेकिन ममता बनर्जी वोट बैंक के पीछे इतनी अंधी और स्वार्थी हो गई है कि उन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए देश हित को भी ताक पर रख दिया है। ये वही ममता है जिन्होंने अटल बिहारी सरकार में देश से रोहिंग्याओं को निकालने के लिए संसद में सबसे पहले मांग की थी। लेकिन विडंबना है कि आज वे बंगाल की सीमाओं पर बंगलादेशियों के स्वागत के लिए पुष्प गुच्छ लिए खड़ी हैं। देश के सभी लोगों तथा सभी राजनीतिक दलों को ममता बनर्जी की इस रणनीति का विरोध करना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि मोदी के विरोध में कुछ भी करने को तैयार विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने इसके प्रति अपनी आंखें बंद कर ली हैं।

- **नरेन्द्र टोंक,** मेरठ

जलभराव से संकट

दिल्ली के पटेल नगर में जलभराव के साथ ही गेट में करंट आने पर गाजीपुर के एक युवा की मृत्यु हो गई। इसकी गंभीरता से जांच जरूरी है। आखिर इस मौत का कौन जिम्मेदार है? जलभराव की स्थितियों में अक्सर करेंट उतर आने से खतरा और बढ़ जाता है। इस मानसूनी मौसम में दिल्ली में जलभराव की घटनायें अनेक स्थानों पर सामने आई हैं। जलभराव के कारण अनेक स्थानों पर कुल मिलाकर दो बच्चों के डूबने सहित कुल 11 लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि, दिल्ली के उप-राज्यपाल गंभीर दिखाई देते हैं और आप सरकार की मंत्री भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करती हैं, लेकिन समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं निकल पाता है। प्रत्येक वर्ष बारिश के दिनों में अंडरपास में पानी भर जाता है, गाड़ियां डूब जाती है और यात्रियों को आने-जाने में कठिनाई होती है। जलभराव होने पर मोटर पंप लगा कर पानी निकाल दिया जाता है लेकिन एक भारी बारिश के बाद फिर वही समस्या खड़ी हो जाती है। आवश्यकता है कि देश की राजधानी तथा महत्वपूर्ण आयोजनों का स्थल दिल्ली में जलभराव का स्थाई समाधान निकाला जाए।

- **वीरेंद्र कुमार जाटव,** दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

343 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी यूपी एसएसएफ द्वितीय वाहिनी की हाईटेक बिल्डिंग

● गोरखपुर के ताल जहदा में 50 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगी वाहिनी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

खास स्थानों, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपी एसएसएफ) की द्वितीय वाहिनी गोरखपुर में है। अभी यह वाहिनी अपना कामकाज पीएसी कैम्पस से कर रही है लेकिन आने वाले समय में इसकी खुद की हाईटेक बिल्डिंग होगी। शासन की तरफ से यूपी एसएसएफ द्वितीय वाहिनी के अत्याधुनिक और सभी सुविधाओं से युक्त भवन के लिए करीब 343 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह बिल्डिंग गोरखपुर के चिलुआताल क्षेत्र स्थित ताल जहदा में 50.136 हेक्टेयर भूमि पर बनेगी। इसके लिए प्रक्रियात्मक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। बरसात का सीजन समाप्त होते ही इसका निर्माण शुरू हो जएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर, 2020 में न्यायालयों, प्रमुख धार्मिक स्थलों, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया था। जिसके बाद जून, 2021 में यूपी एसएसएफ की पांच वाहिनी गठित की गई थीं, जिनमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा व सहारनपुर शामिल हैं। इसके बाद छठवीं वाहिनी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए गठित की गई। गोरखपुर के लिए गठित एसएसएफ की द्वितीय वाहिनी गोरखपुर और कुशीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रही है। जल्द ही इसके जिम्मे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान भी आएंगे। यूपी एसएसएफ के गठन के बाद से ही योगी सरकार इसे सूबे की सबसे एडवांस फोर्स बनाने में जुटी है। इस फोर्स को अत्याधुनिक असलहों से लैस करने के साथ ही इसकी बटालियन के लिए हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी व्यवस्थाओं के लिए करीब 343 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दी है। गोरखपुर में यूपी एसएसएफ की द्वितीय वाहिनी के आवासीय भवनों के लिए योगी सरकार ने 186 करोड़ 33 लाख 43 हजार रुपये तथा अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 156 करोड़ 39 लाख 89 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं। कार्यदायी संस्था के रूप निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड (भवन) को दी गई है। कार्यदायी संस्था की तरफ से निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड (भवन) के अधिशासी अभियंता अर्जुन मित्रा का कहना है कि बरसात के बाद निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू करा दिया जाएगा।

ताल जहदा में यूपी एसएसएफ द्वितीय वाहिनी के परिसर में लिफ्ट युक्त टाइप ए, बी और टाइप फोर व फाइव के बहुमंजिला भवन बनाए जाएंगे। इसके अलावा लिफ्ट युक्त प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड, पार्किंग, संतरी पोस्ट, अस्पताल, इंडोर जिम, डॉग कैनेल, टॉयलेट ब्लॉक और 400 की क्षमता का बैरक बनाया जाएगा। यहां सलामी मंच के साथ भव्य परेड ग्राउंड का विकास भी होगा। सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ इसके परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इंतजाम होगा।

परीक्षा केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिएः मुख्य सचिव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह एवं पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा-2023 के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों , जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षाओं को नकलविहीन, पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। परीक्षा केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने स्तर से इन सभी परीक्षा केन्द्रों की सुरक्षा और परीक्षार्थियों के बैठने के लिये फर्नीचर एवं पीने के पानी आदि की व्यवस्था की जांच करायें, कोई अव्यवस्था होने पर संबंधित केन्द्र के प्रमुख से संपर्क कर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें।

उन्होंने पुलिस भर्ती परीक्षा की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पूरी सतर्कता बरती जाए। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा भ्रमणशील रहकर विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाये। सभी जिलाधिकारियों से कहा कि ईवीएम मशीनों की भांति परीक्षा प्रश्न पत्रों की निगरानी व सुरक्षा सुनिश्चित करायें।

पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कड़ी सुरक्षा में पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न होनी चाहिए। परीक्षा में नकल माफिया सक्रिय न हो, इस पर विशेष तौर पर नजर रखी जाए। वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी नाम के स्थान पर पदनाम से लगाई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो। बैठक में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड डीजी राजीव कृष्ण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यात्रियों की शिकायत का विवरण प्रतिदिन मुख्यालय कराए उपलब्धः परिवहन मंत्री

● 10 हजार परिचालकों की जल्द भर्ती के दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने परिचालकों की कमी के दृष्टिगत 10 हजार परिचालकों की जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परिचालकों की कमी से परिवहन निगम की बहुत सी बसें आफरूट हो रही है, इससे परिवहन निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने टेक्निकल स्टाफ की कमी को भी जल्द दूर करने के निर्देश भी दिये।

परिवहन मंत्री ने कहा कि बस स्टेशनों के साथ-साथ अच्छी क्वालिटी की बसें लोगों को मुहैया हो सके, इसके लिए गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य करने की जरूरत है। वर्कशाप में बसों की अच्छी ढंग से मरम्मत कार्य किया जाए, जिससे कि बसों की छत टपकने की समस्या दूर हो सके। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम की बसों से यात्रा करते समय लोगों को सुखद एवं आरामदायक यात्रा की अनुभूति हो सके। इसके लिए बसों की सीटें, शीशे इत्यादि बेहतर कंडीशन में हो। उन्होंने आनलाइन बुकिंग की व्यवस्था पर और बेहतर करने पर जोर दिया। साथ ही चालक/परिचालक वर्दी में हो, नेम प्लेट लगा होना चाहिए। बस स्टेशनों एवं डिपो पर एक हेल्पलाइन नम्बर की व्यवस्था की जाए, जिसपर यात्री किसी भी समय शिकायत दर्ज करा सकें। परिवहन मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान क्षेत्रों में संचालित बसों की लोड फैक्टर, फ्यूल एवरेज एवं आय की समीक्षा की। उन्होंने नोएडा, गाजियाबाद, चित्रकूट एवं बरेली के प्रबंधकों को बेहतर कार्य एवं प्रदर्शन के लिए बधाई दी। जबकि मेरठ, मुरादाबाद और वाराणसी के क्षेत्रीय प्रबंधकों को खराब प्रदर्शन करने पर चेतावनी दी और कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिये। अलीगढ़, आजमगढ़, झांसी, मेरठ एवं देवीपाटन के क्षेत्रीय प्रबंधकों को उनके यहां अनुपयोगी बसों की संख्या ज्यादा पाये जाने पर चेतावनी दी। उन्होंने खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने एवं उनके खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधकों को यात्रियों की शिकायतों का विवरण प्रतिदिन मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। परिवहन मंत्री ने उत्तराखंड एवं उप्र के निगम बसों के पार्किंग फीस में अंतर को समाप्त करने के निर्देश दिये। उत्तराखंड परिवहन निगम अपने यहां पार्किंग फीस 550 रुपए रखा है जबकि उप्र परिवहन निगम अपने यहां पार्किंग फीस मात्र 220 रुपए रखा है। इससे परिवहन निगम की बसों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने टिकट/डीजल चोरी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैमरों के माध्यम से मॉनीटरिंग किया जाए। परिवहन मंत्री ने परिवहन निगम द्वारा अनुबंधित ढांबों पर साफ-सफाई बेहतर रखें एवं शौचालय की व्यवस्था उत्तम रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जो भी अनुबंधित ढ़ाबा उक्त व्यवस्थाओं को पूरा करने में विफल रहता है उसका अनुबंध समाप्त कर दिया जाए।

ग्रेटर नोएडा में होगी 'सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर टेक्नोलॉजी' बेस्ड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना

● 79.57 करोड़ रुपए की लागत से होगा ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शुरू की तैयारियां

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश की प्रगति व उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर उसे उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में प्रयासरत योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में विकास को गति देने के लिए दो प्रमुख योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना व संचालन के साथ ही गंगा जल प्रोजेक्ट से संबंधित परियोजनाओं को गति देने का कार्य शुरू हो गया है।

सीएम योगी के विजन अनुसार, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-1 में में सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर टेक्नोलॉजी बेस्ड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना निर्धारित है। 79.57 करोड़ की लागत से बनने वाले 45 एमएलडी कैपेसिटी युक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व वॉटर रीक्लेमशन फैसिलिटी की स्थापना, संचालन व टेस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एजेंसी निर्धारण व कार्यावंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी प्रकार, 85 क्यूसेक कैपेसिटी वाले गंगा जल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 जोनल रिजरवॉयर में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल व अन्य सिविल वर्क्स को जल्द पूरा करने के लिए एजेंसी निर्धारण व कार्यावंटन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इस कार्य में कुल मिलाकर 11.44 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। इन दोनों ही कार्यों को पूरा करने के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से प्रक्रिया शुरू हो गई है और सभी कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के समेकित विकास के लिए सीएम योगी के विजन में तैयार की गई विस्तृत कार्ययोजना के अनुसार, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-1 में 79.57 करोड़ रुपए की लागत से सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर (एसबीआर) टेक्नोलॉजी युक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का विकास किया जाएगा। यह 45 एमएलडी कैपेसिटी वाला एसटीपी होगा जिसे एजेंसी निर्धारण व कार्यावंटन के बाद 15 महीनों में पूरा किया जाएगा। वहीं, ऑपरेशन व मैनेजमेंट के लिए 120 महीनों की कार्यावधि निर्धारित की गई है। इस प्लांट के निर्माण को लेकर पहले एजेंसी द्वारा साइट एनवॉयरमेंट प्लान (एसईपी) तैयार किया जाएगा। सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न मानकों का ध्यान रखा जाएगा जिसमें वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण के स्तर को भी मॉनिटर करते हुए कम से कम रखा जाएगा। यह ट्रीटमेंट प्लांट वॉटर रीक्लेमेशन फैसिलिटी भी होगा। प्लांट के संचालन के लिए 3 महीने का ट्रायल पीरियड भी निर्धारित किया गया है जिसमें इसके संचालन के विभिन्न मानकों को मॉनिटर करते हुए क्रियान्वित किया जाएगा। इस दौरान, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड की समयावधि 12 महीने निर्धारित की गई है। प्लांट का डिस्पोजल चैनल हिंडन नदी के किनारे स्थित होगा। प्लांट को सौर ऊर्जा युक्त भी किया जाएगा और इसके हाइड्रोलिक पंपों का संचालन सौर ऊर्जा के जरिए किए जाने की योजना है।

प्लांट में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सीवरेज आउटकम को गहरे गुरुत्वाकर्षण आउटफॉल सीवर द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जो रॉ सीवेज को एक रिसीविंग चैंबर में डिस्चार्ज करेगा, जहां से इसे डाउनस्ट्रीम मोटे स्क्रीन में ले जाया जाएगा। सीवेज के साथ आने वाली सामग्रियों को हटाने के लिए उसे गीले कुएं के ऊपर मोटे स्क्रीन चैनल में छाना जाएगा। स्क्रीनिंग के बाद सीवेज वेट वेल में प्रवेश करेगा। प्लांट वेट वेल युक्त होगा जिसकी क्षमता औसत और पीक फ्लो स्थितियों के दौरान पर्याप्त हाइड्रोलिक प्रतिधारण करने की होगी। प्लांट में फ्लो मैनेजमेंट, इनलेट चैंबर, फाइन स्क्रीनिंग व डी-ग्रिटिंग व्यवस्था को भी पूर्ण किया जाएगा।

प्लांट में उपचारित सीवेज में से बीओडी, सीओडी, निलंबित ठोस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को हटाने तथा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक रिमूवल के लिए एसबीआर इकाइयों में डाला जाएगा। एसबीआर बेसिन को दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जोकि सिलेक्शन जोन व ऐरेशन जोन युक्त होंगे। एसबीआर एकल चरण में चक्रीय/बैच मोड में काम करेगा।

व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठों को बनाया जाए और अधिक प्रभावी

● डीजीपी ने व्यापारियों व उद्यमियों से सम्मानजनक शिष्टतापूर्ण व सहयोगात्मक व्यवहार करने के पुलिस कर्मियों को दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रदेश के सभी जिलों में गठित व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठों को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में व्यापारियों, उद्यमियों, निर्यातकों की समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए शासन के निर्देश पर समस्त कमिश्नरेट और जिलों में अपर पुलिस आयुक्त/ अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। डीजीपी ने निर्देशित किया है कि व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण तथा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए गठित व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह नियमित बैठकें आयोजित कराकर समस्याओं एवं शिकायतों को पूर्णत: गम्भीरता से लेकर निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। पुलिस के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों एवं उद्यमियों के साथ सम्मानजनक, शिष्टतापूर्ण एवं सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए। सर्राफा व्यापारियों, अन्य व्यापारियों/ उद्यमियों के आवागमन के दौरान उनके संगठन द्वारा निर्गत किए गए गोल्डन कार्ड/ परिचय-पत्र एवं सम्बन्धित कागजात दिखाये जाने हेतु उनके साथ परिमार्जित ढंग से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाय। परिचय-पत्र एवं सम्बन्धित कागजात सही पाये जाने पर उन्हें कदापि प्रताड़ित न किया जाए। सर्राफा व्यापारियों को समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए तथा मुख्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, व्यस्त बाजारों तथा सर्राफा मार्केट आदि स्थलों पर समुचित एवं पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगायी जाए तथा पुलिस पेट्रोलिंग भी कराई जाए। समय-समय पर थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऐसे स्थानों पर लगाए गए पुलिस बल की चेकिंग कर उन्हें अपनी ड्यूटी पर सदैव सतर्क रहने के लिए ब्रीफ किया जाए।

मसालों की खुशबू से महकेगी बुद्ध के महापरिनिर्वाण की धरा

● कुशीनगर में हल्दी के साथ ही अब जीरा, सौंफ, मंगरैल, धनिया और अजवाइन की खेती का बढ़ेगा दायरा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ कुशीनगर

भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की धरती। कभी इसी धरती से सत्य और अहिंसा के संदेश से दुनिया का बड़ा हिस्सा आलोकित हुआ था। अब उसी धरती से उपजे मसालों की खुशबू शुरू में स्थानीय और बाद में देश-दुनिया में रहने वाले हर भारतीय के किचन के भोजन की लज्जत बढ़ाएंगे। इसमें वर्षों से कुशीनगर में होने वाली हल्दी की खेती का योगदान तो होगा ही, धनिया जीरा, सौंफ, मंगरैल, सौंफ और अजवाइन की खेती इसका दायरा बढ़ाएंगे। इस बावत डबल इंजन (मोदी और योगी) की सरकार पहल भी कर चुकी है।

राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर की मदद से इस साल रबी की फसलीय सीजन में सीमित संख्या में कुछ किसानों के खेतों में मसाले की कुछ प्रजातियों की खेती शुरू होगी। कृषि विज्ञान केंद्र कुशीनगर के प्रभारी अशोक राय के अनुसार कुशीनगर में हल्दी की खेती की परंपरा पुरानी है। कुशीनगर और आसपास की जलवायु बीजीय मसालों के लिए भी अनुकूल है। इसलिए यहां इसकी अच्छी संभावना है। यहां के किसान भी जागरूक हैं। इसलिए अपेक्षाकृत अधिक लाभ वाले मसालों की खेती की संभावना और बेहतर हो जाती है।

किसानों के बीच टाटा ट्रस्ट और अजीमजी प्रेमजी फाउंडेशन की मदद से कई वर्षों से हल्दी की खेती पर फोकस होकर काम करने वाले सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के बीएम त्रिपाठी मसालों की खेती के लिए भी राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अनुसंधान केंद्र का भी मेथी, सौंफ, जीरा और अजवाइन के फ्लेवर और औषधीय गुणों के कारण इनके प्रसंस्करण पर खासा जोर है। इनको मिलेट के साथ मिलाकर और पौष्टिक बनाया जा सकता है। कालांतर में कुशीनगर के किसानों को भी अगर मसाले की खेती रास आई तो उनके लिए भी ये सारी संभावनाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के हित के प्रति जिस तरह प्रतिबद्ध हैं उसमें कोई एफपीओ खेती से लेकर प्रसंस्करण इकाई लगाने और मार्केटिंग की अगुआई कर सकता है। योगी सरकार की यही मंशा भी है। भारत को मसालों की धरती भी कहा जाता है। पुर्तगाली जब पहली बार भारत आए तो उनका मूल उद्देश्य भारतीय मसालों के कारोबार से कमाई करना ही था। भारत में करीब 18 लाख हेक्टेयर जमीन पर मसालों की खेती होती है। जीरा गुजरात और राजस्थान की मुख्य फसल है तो बाकी तमाम मसाले अधिकांशत: दक्षिण भारत में होते हैं। मसाले भारतीय भोजन की जान होते हैं। देश दुनिया में जहां भी भारतीय हैं वहां बिना मसाले के उनके किचन की कल्पना नहीं की जा सकती। बढ़ती बीमारियों और औषधीय खूबियों के कारण मसालों का क्रेज और बढ़ा है। खासकर कोविड के बाद तो और भी। इसलिए इसकी खेती की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन संभावनाओं को आने वाले समय में और चार चांद लगाएगा।

50 फीसदी से अधिक राजस्व वृद्धि करने वाले नगर निगमों को मिलेगा 100 करोड़ तक का अनुदान

● पंचवर्षीय विजन प्लान के तहत तैयार होगी वार्षिक कार्ययोजना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश में नगरों के सर्वांगीण विकास और नगरीय स्थानीय निकायों के रेवेन्यू कलेक्शन में वृद्धि को लेकर योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में नगर विकास विभाग ने राज्य की समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में संचालित विभिन्न योजनाओं और अन्य मिशनों को 'मिशन टू मूवमेंट' के रूप में विस्तारित कर मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत नगर निगमों में न्यूनतम 25 प्रतिशत टैक्स/नॉन टैक्स में वृद्धि करने वाले नगर निगमों को न्यूनतम 2.5 करोड़ और अधिकतम 50 करोड़, नगर पालिका परिषदों व जिला मुख्यालयों (एक लाख से अधिक जनसंख्या) में न्यूनतम 15 प्रतिशत टैक्स/नॉन टैक्स में वृद्धि करने वाले निकायों को न्यूनतम 25 लाख रुपए और अधिकतम 20 करोड़ रुपए और नगर पालिका परिषद व जिला मुख्यालय (एक लाख से कम जनसंख्या) व नगर पंचायतों में न्यूनतम 10 प्रतिशत टैक्स/नॉन टैक्स में वृद्धि करने वाले निकायों को न्यूनतम 10 लाख और अधिकतम 5 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में 50 प्रतिशत से अधिक राजस्व वृद्धि करने, नवोन्मेषी परियोजनाएं, राजस्व उत्पादक परियोजनाएं एवं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए प्रति नगर निगम अधिकतम 100 करोड़ रुपए की निधि जारी की जा सकती है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी एसओपी में इसका प्राविधान किया गया है। योजना के तहत, सेल्फ रेवेन्यू कलेक्शन को आधार वर्ष 2022-23 की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ाया जाएगा, जो पात्रता मानदंड होगा। यह योजना 2024-25 से शुरू होकर पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी। 2024-25 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस योजना से उत्तर प्रदेश के समस्त 762 नगरीय स्थानीय निकायों को आच्छादित किया जाएगा। यह योजना राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों में सतत आर्थिक वृद्धि, समानता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए 3ई दृष्टिकोण अपनाएगी। योजना के प्रयोजन के लिए नगरीय स्थानीय निकाय के प्रकार, जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर नगरीय स्थानीय निकाय को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी-1 में नगर निगम (3 लाख से अधिक जनसंख्या), श्रेणी-2 में नगर पालिका परिषद एवं जिला मुख्यालय (1 लाख से अधिक जनसंख्या) और श्रेणी-3 में नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतें और जिला मुख्यालय (1 लाख से कम जनसंख्या) को शामिल किया गया है। इन श्रेणियों के तहत विभिन्न परियोजनाएं अनुमन्य की गई हैं।

योजना के लिए उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के लिए आवंटित संरचना श्रेणी-1 के लिए आवंटन का 40 प्रतिशत, श्रेणी-2 के लिए कुल आवंटन का 40 प्रतिशत एवं श्रेणी-3 के लिए कुल आवंटन का 20 प्रतिशत तक आरक्षित किया गया है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के लिए अनुमोदित बजट आवंटन की धनराशि में मंत्री नगर विकास विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

घुप अंधेरा, तेज बहाव, 40 मिनट का रेस्क्यू ऑपरेशन और 4 को मिली नई जिंदगी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ कुशीनगर

● संकट की घड़ी में साथी बन कुशीनगर जिला प्रशासन के देवदूतों ने बड़ी गंडक नदी के तेज बहाव में फंसे चार लोगों की बचाई जान

बुधवार देर रात कुशीनगर जिला प्रशासन ने खड्डा तहसील की बड़ी गंडक नदी में अचानक बढ़े हुए जलप्रवाह के बीच फंसे चार लोगों को अदम्य साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू किया। टीम ने देर रात घुप अंधेरे और तेज बहाव के बीच महज कुछ मिनटों में रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए सभी को सुरक्षित बचा लिया। इस पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के रेस्क्यू ऑपरेशन की काफी तारीफ की। बता दें कि वर्ष 2003 में यहां पर तेज बहाव की वजह से 16 लोगों की जान चली गयी थी। राहत आयुक्त जीएस नवीन के मुताबिक बुधवार रात आठ बजे कुशीनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि खड्डा तहसील के एसडीएम ऋषभ पुंडीर और एडीएम एफआर वैभव मिश्रा ने बड़ी गंडक नदी में अचानक तेज बहाव की वजह से एक नाव पलटने की सूचना दी। इस हादसे में चार लोग पुनियावन पुल के पास तेज बहाव के बीच फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने रात में रेस्क्यू ऑपरेशन की परमीशन मांगी। इस पर तत्काल परमीशन देते हुए एसडीआरएफ के कमांडेंट को रेस्क्यू का आदेश दिया। एडीएम एफआर वैभव मिश्रा ने बताया कि ऑपरेशन की परमीशन मिलते ही एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। एडीएम एफआर ने बताया कि घुप अंधेरा होने की वजह से एसडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाने में असमर्थता जतायी। इसपर तत्काल प्रकाश की व्यवस्था कराई गई। इसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया। एडीएम एफआर वैभव मिश्रा, एसडीएम खड्डा ऋषभ पुंडीर और एसडीआरएफ की टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते में हुए कड़ी मशक्कत के बाद महज 40 मिनट में पानी के तेज बहाव में फंसे चारो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद सभी का मेडिकल चेकअप कराया गया। वहीं डॉक्टर्स के क्लीयरेंस के बाद सभी को गाड़ी से उनके घर पहुंचाया गया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि बड़ी गंडक नदी के तेज बहाव में फंसे चारो लोग बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि चारो लोग देर रात नदी में मछली पकड़ने गये थे। इस दौरान अचानक नदी का बहाव तेज हो गया और नाव पलट गयी। वहीं नदी में तेज बहाव होने की वजह से वह बहते हुए पुनियाहवा पुल के पास फंस गये। ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिलने पर एसडीएम खड्डा ऋषभ ने एडीएम एफआर वैभव मिश्रा को रात 8 बजे जानकारी दी। इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और 40 मिनट में सफलतापूर्वक सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। एडीएम एफआर ने बताया कि नदी के तेज बहाव में राजकुमार सहानी, भुवाली सहानी, सुभाष साहनी और शैलेश कुमार फंस गये थे। उन्होंने बताया कि चारो बिहार के बगाह नारायणपुर घाट के रहने वाले हैं। ऑपरेशन के बाद सभी का मेडिकल चेकअप कराया गया। इसके बाद गाड़ी से सभी को उनके घर पहुंचाया गया।

राज्यमंत्री ने की महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा दिये निर्देश

● सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध हो मूलभूत सुविधायें: राज्यमंत्री

● सैम-मैम बच्चों का चिन्हीकरण कर करायें कार्यवाही: राज्यमंत्री

● बच्चों व गर्भवती महिलाओं को समय से उपलब्ध हो पोषण आहार

राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला अपने विभाग की सॅचालित योजनाओं की सर्किट हाउस में समीक्षा करती हुयी

कानपुर देहात। महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सर्किट हाउस सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं, परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। राज्यमंत्री द्वारा सभी सीडीपीओ से कुपोषित बच्चों की संख्या, आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थितिए नये आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की प्रगति व अन्य भौतिक संसाधनों के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। उन्होंने सभी सीडीपीओ को अपने ब्लाक अन्तर्गत संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं/लाभों को उपलब्ध कराया जाये, उनको बेहतर शिक्षा दी जाये। सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समय से शत प्रतिशत पोषण आहार वितरण करने, सैम.मैम बच्चों के चिन्हीकरण करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पीएमकेयर, वन स्टॉप सेन्टर, निराश्रित महिला पेंशन योजना, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं, योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित को दिये। उन्होंने बेटी बचाओंए बेटी पढ़ाओं योजना के अधिक से अधिक प्रचार करने के भी निर्देश दिये। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीडीपीओ, सुपरवाईजर, ब्लाक क्वाडिनेटर, बाल संरक्षण अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

कारगिल विजय दिवस पर भाजयुमो ने निकाला मशाल जुलूस

फतेहपुर। सन् 1999 मे भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ जो कि 60 दिनो तक चलने के उपरान्त 26 जुलाई को भारत विजय के साथ समाप्त हुआ। कारगिल विजय की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व मे आम जन मानस द्वारा मसाल जुलूस का आयोजन किया गया। भारतीय जवानो के सम्मान मे वर्मा चौराहे से पटेल नगर चौराहे तक भारत माता कि जय के नारो के साथ विजय ज्योति के रुप मे मसाल जुलूस परणित किया गया। जिला अध्यक्ष मधुराज विश्वकर्मा ने बताया कि कश्मीर मुद्दे पर द्विपक्षीय वार्ता भारत शांति पुर्ण ढंग से हल करने का घोषणा पत्र का उलंघन करते हुए पाकिस्तान ने अपने सैनिको और अर्ध सैनिक बलो को छिपा कर नियन्त्रण रेखा के पार भेजनें लगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने के बाद प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेई ने आपरेशन विजय के नाम से 02 लाख सैनिको को कारगिल क्षेत्र मे भेजा।

कार्यकर्ता विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें: असीम अरुण

● भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ की बैठक में राज्यमंत्री का हुआ जोरदार स्वागत

राज्य मंत्री का स्वागत करते सागर अग्रवाल लकी।

कन्नौज। भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ की बैठक में व्यापारी बंधुओं से कल प्रस्तुत हुए बजट पर सार्थक चर्चा हुई। जिसमें पहुंचे राज्य मंत्री असीम अरुण का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। गुरुवार को जिला कार्यालय पर व्यवसायिक प्रकोष्ठ भाजपा की आयोजित बैठक में राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि भाजपा सरकार के बजट से विकसित भारत का सपना साकार होगा। हर वर्ग एवं हर क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार चौमुखी विकास कार्य करवा रही है। आम आदमी से लेकर किसानों, नौजवानों एवं बेरोजगारों के सपने को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी सरकार के सपनों को आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन प्रदेश मंत्री/सह संयोजक व्यवसायिक प्रकोष्ठ भाजपा सागर अग्रवाल लकी, जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया, संतोष चतुर्वेदी एवं व्यापारी नेताओं ने राज्य मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए सरकार ने जो विभिन्न योजनाएं दी हैं उनको कैसे जन-जन तक पहुंचाएं, इसपर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होनें कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने वाली भाजपा की नीतियों में सभी व्यापारी बंधुओं ने विश्वास जताया। इस दौरान जिला महामन्त्री संजय गुप्ता, जिला उपाध्याय आनंद गुप्ता व ऋषि यादव, नगर अध्यक्ष गौरव गोयल, अखिलेश पांडेय, धीरेंद्र गुप्ता, अंकित गुप्ता, नरेश भदौरिया सहित सैकड़ो व्यापारी गण मौजूद रहे।

सड़क के बीचोबीच खड़े विद्युत पोल से चौपहिया वाहनों का आवागमन ठप

संडीला (हरदोई)। ट्रांस्फॉर्मर रखने के लिए खड़े किए गए दो खंभे ट्रांस्फॉर्मर हटने के बाद भी सड़क के बीचोबीच यथावत खड़े हैए जिसके कारण इस महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग पर चौपहिया वाहनों का आवागमन बंद है और लोग परेशान हैं। नगर के मोहल्ला मलकाना दमादपुरवा में मोहल्ला माकूम कुआं से दादा मियां की मज़ार होते हुए सेंट थेरेसा बाईपास से जुड़ता है। इस संपर्क मार्ग पर डॉ0 फैसल के घर के निकट लगभग 50 वर्ष पूर्व विद्युत आपूर्ति के लिए दो खंभे बीच सड़क पर गाड़ कर चबूत्रा बनाया गया था। लगभग दस वर्ष पहले इस स्थान से ट्रांस्फार्मर विद्युत विभाग द्वारा हटा लिया गया और चबूत्रा तोड़ दिया गया लेकिन खंभे ज्यों के त्यों खड़े रहे। इस दौरान इस संपर्क मार्ग पर वाहनों का आवागमन इसलिए होता रहा क्योंकि इस क्षेत्र में स्व0 आबाद मियां के तालाब और खेतों के कारण वाहन किनारे होकर निकल जाते थे लेकिन

विगत 5 वर्षों में इस जगह पर भी अंधाधुंध मकान बन गए और यह संपर्क मार्ग काफ़ी सकरा हो गया। चूंकि बीचोबीच में दोनों खंभे खड़े हैं इसलिए एम्ब्यूलेंसए कारए ट्रैक्टर ट्रॉली आदि का आवामन बंद हो गया। अब स्थिति यह है कि सेंट थेरेसा बाईपास तक जाने के लिए क्षेत्र का पूरा चक्कर लगाना पड़ता हैए जिसके कारण धन और समय दोनों की बर्बादी होती है। सड़क के बीचोबीच खड़े इन दोनों खंभों को लेकर नगर पालिका और विद्युत विभाग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। विद्युत विभाग के जिम्मेदारों का कहना है कि इन खंभों को हटाने के लिए पूरी लाइन हटानी होगी।

चेकडैम धांधली की जांच करायी जायेगी उच्चाधिकारियों से: सिचाई राज्य मंत्री

● सीडीओ ने कहा जांच टीमे पहले ही हो चुकी है गठित रिपोर्ट का हो रहा है इंतजार ● अट्ठाइस चेकडैमों की प्रक्रिया हो रही है पूरी आज आवेदनों की टेक्नीकल जांच हुई झांसी में

हमीरपुर। लघु सिचाई विभाग के चेकडैम असमय ध्वस्त होने के मामले में प्रदेश सरकार के सिचाई राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने साफ कहा है कि इस मामले की वह उच्चाधिकारियों से जांच करायेगे। वही सीडीओ ने कहा कि चेकडैम की जांच के लिये पहले ही करीब छह टीमों का गठन कर दिया गया था उनकी शीघ्र ही रिपोर्ट मांगी गयी है।

जानकारी के मुताबिक लघु सिचाई विभाग के अभियंताओ द्वारा चेकडैम के नाम पर किसानो के साथ धोखाधड़ी करने व लाखो रुपये ठिकाने लगाने का मामला अब शासन तक पहुच गया है। वही सरीला क्षेत्र के बंधौली व चंडौत गांव के मजदूरों ने बताया कि दबंग ठेकेदारों ने चेकडैम तो उनसे बनवा लिया था मगर उनकी मजदूरी आज तक नही दी है इसके लिये वह उच्चाधिकारियों से शिकायते की है मगर उसका कोई असर नही हुआ है। बंधैली के शैलेंद्र ने बताया कि वह चेकडैम में मेट था उसके साथ के कई मजदूर काम किया मगर ठेकेदार हजारो रुपये हड़प कर गया। इसी प्रकार व्रजमोहन का कहना है कि वह भी मजदूरी के लिये दर दर भटक रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि चेकडैम वनाकर क्षेत्रीय किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है क्योकि किसी भी चेकडैम से आज तक सिचाई के नाम पर एक बूद पानी नही निकला है सिर्फ कागजो में ही सिचाई चलती रही है। वही सिचाई राज्य मंत्री रामकेश निषाद का कहना है कि मामला गंभीर है वह इस मामले की जाच करायेगे। और दोषियों को कतई बख्शा नही जायेगा ।सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ला का कहना है कि चेकडैम् की जांच के लिये पहले की टीमों का गठन किया जा चुका है मगर उनकी रिपोर्ट नही आयी है। शीघ्र ही उनकी रिपोर्ट मांगी जायेगी। इसके बाद कार्यवाही की जायेगी। बही अपना दल के नेता महेंद्र राजपूत ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। कहा है कि यदि जांच करा ली जाये तो करोडो रुपये की धाधली सामने आ जायेगी। इधर विभाग मे 28 टेंडरों की प्रक्रिया चल रही है ठेकेदारो ने ई टेंडर डाल दिये है। टेक्नीकल जांच के लिये अधिशासी अभियंता गुरुवार को झांसी गये थे वहा से खानापूरी करने के बाद बाद मे वित्तीय जांच होगी इसके बाद ये सभी चेकडैम बनने शुरु हो जायेगे। जो पुराने ध्वस्त हो गये उनकी चिंता किसी को नही है। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

तीन दिन से गायब किसान का शव उतराता मिला

राठ (हमीरपुर)। तीन दिन से गायब किसान का शव धसान नदी में उतराता मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मझगवां थाने के लिधौरा गांव निवासी दसइयां ने बताया कि हम उसके पिता 61 वर्षीय गोरेलाल अहिरवार 23 जुलाई को भैंस चराने के लिए गए थे। शाम को भैंस वापस आ गई। लेकिन वह घर नहीं लौटे। तलाश करने पर कोई जानकारी नहीं हो सकी। बुधवार को सारा दिन ढूंढा न मिलने पर थाने में गुमशुदगी की दर्ज कराई। गुरुवार सुबह गांव से 3 किलोमीटर दूर धसान नदी के किनारे उनका शव उतराते मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसने बताया कि भैंस को पानी पिलाते समय उनका पर फिसल मझगवां थानाध्यक्ष नंदलाल प्रजापति ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना की जानकारी हो सकेगी।

क्विक न्यूज

तेज़ रफ़्तार कार की चपेट में आकर युवक की मौत, वृद्ध घायल

संडीला (हरदोई)। अनियंत्रित गति से आ रही एक कार ने बाइक से गिरे युवक को रौंद दिया जिससे उसकी मौत हो गयी। एक वृद्ध व्यक्ति इस हादसे में घायल भी हुआ है। मल्लावां संडीला मार्ग पर सुबह यह दुर्घटना हुई। ग्राम चंदौली थाना माधवगंज निवासी 25 वर्षीय मनोज कुमार अपनी बाइक से आ रहे थे। जब वह गौसगंज के पास पहुंचे तो साइकिल से आ रहे गौसगंज निवासी अली हुसैन से उनकी बाइक टकराकर अनियंत्रित हो गयी और सड़क पर जा गिरे जबकि अली हुसैन सड़क के किनारे कच्ची मिट्टी में गिरे। इसी बीच अत्यंत तेज़ गति से आ रही कार ने सड़क पर गिरे मनोज कुमार को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे वे मरणासन्न हो गए। उन्हें उठाकर लोग अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गयी। मृतक मनोज कुमार किसी विद्यालय में बतौर शिक्षक कार्यरत थे। साइकिल सवार अली हुसैन को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की एफ़आईआर दर्ज की गयी है। अभी तक कार का कोई पता नहीं मिला है।

वृद्ध को साड़ ने हमला कर मार डाला

राठ (हमीरपुर)। नहर बाईपास पर टहलने के लिए निकले वृद्ध को सांड ने हमला कर मार डाला। कस्बे के दीवानपुरा मोहल्ला प्रभु दयाल (80) मंगलवार की शाम करीब पांच बजे वह नहर बाईपास पर टहलने गए थे। लौटते समय अन्ना सांड ने हमला बोल दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्राइवेट अस्पताल में ले गए। जहां से मेडिकल कालेज झांसी रेफर कर दिया गया। जहां उनकी मौत हो गई। स्वजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। वहीं कस्बे के पठानपुरा मोहल्ला निवासी 18 वर्षीय निधि पुत्री वीरेंद्र सिंह का बुधवार को जन्मदिन था। वह शाम को केक खरीदने जा रही थी। तभी सांड ने हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

कन्टेनर में पीछे से घुसी डीसीएम, चालक की मौत

फतेहपुर। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के बड़ौरी टोल प्लाजा के समीप एनएच-2 में आगे जा रहे कन्टेनर के अचानक रूकने पर पीछे से आ रही डीसीएम घुस गई। जिसमें 50 वर्षीय चालक की मौके पर मौत हो गई। बाराबंकी जनपद के थाना फतेहपुर भड़ने हवा मजरे संदूहपुर निवासी सियाराम का पुत्र दिनेश डीसीएम चालक था। बताते हैं कि बुधवार की रात आगे जा रहे कन्टेनर ने बड़ौरी टोल प्लाजा के समीप अचानक ब्रेक लगा देने पर पीछे से आ रही डीसीएम घुस गई। जिसमें दिनेश की घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विच्छेदन गृह भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया।

सड़क पार कर रहे चालक को वाहन ने रौंदा, मौत

फतेहपुर। राजस्थान प्रांत के जिला जयपुर थाना बेवार गांव आदर्श विद्या मंदिर अजमेर रोड बाईपास निवासी रमजान अली का पुत्र अब्दुल हमीद ट्रक चालक था। थरियांव थाना क्षेत्र के उसरैना के पास ट्रक खड़ा कर उतरकर सड़क पार रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उसे रौंद दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस घायल को उपचार के लिए सदर अस्पताल ला रही थी तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया।

अधेड़ ने जहर खाकर दी जान

फतेहपुर। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव निवासी स्व. रामशंकर का पुत्र रमेश काफी दिनों से मानसिक तनाव में था। बीती शाम उसने जान देने के इरादे से जहर खा लिया। कुछ देर बाद जब उसकी हाल बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उसे तत्काल उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सकीय उपचार के बाद हालत ठीक न होने पर उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को विच्छेदन गृह भेज दिया।

कूलर में उतरे करंट से युवक की मौत

फतेहपुर। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छीछा में बुधवार की शाम कूलर में उतर रहे करंट की चपेट में आ जाने से 35 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छीछा गांव निवासी चंद्रभान का पुत्र महेश सिंह बुधवार की शाम खाना खाकर कमरे में सोने चला गया। तभी कूलर चालू करते समय करंट की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

चौकीदार का पुत्र युवती को भगाकर ले जाने में गिरफ्तार

फर्रुखाबाद। युवती को ले जानें के मामले में आरोपी चौकीदार के पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस नें आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के लिए चालान कर दिया। राजेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम निवासी 17 वर्षीय युवती को ले जानें में ग्राम गांधी के पुत्र सकटे के पुत्र नागेश के खिलाफ मुकदमा धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस नें युवती को फरीदाबाद से दबिश के दौरान बरामद किया था।

16.36 करोड़ की संपत्ति सपा नेता जग्गू यादव की कुर्क

फर्रुखाबाद। डीएम के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत सपा नेता जग्गू यादव की 16 करोड़ 36 लाख 9 हजार 497 रूपये इकसठ पैसे की अबैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। तहसीलदार सदर श्रद्धा पाण्डेय, थानाध्यक्ष मऊदरवाजा अमित गंगवार व थाना कादरी गेट के पुलिस बल के साथ गैंगेस्टर के आरोपी देवेन्द्र उर्फजग्गू यादव की सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही की गई, जिसमे बाग लकूला में लगभग 28 आवासीय प्लाट व कृषि योग्य भूमि को मुनादी कराकर कुर्क किया गया । जग्गू वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्ध है। जग्गू व उसके भाई सपा नेता योगेंद्र यादव उर्फचन्नू को पूर्व में जिला प्रशासन ने वर्ष 2017 व 2021 में जिला बदर किया था। भूमाफिया भी घोषित किया जा चुका है। कोतवाली फतेहगढ़ में 12 जून 2024 को गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। जग्गू यादव को बीते 13 जून 2024 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

जरदोजी कारीगर की पत्नी की संदिग्ध मौत

संवाददाता। फर्रुखाबाद

जरदोजी कारीगर की पत्नी को संदिग्ध हालत में निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के स्वजनों ने जहर देकर हत्या का आरोप लगाया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पंहुची लेकिन सीमा विवाद में पुलिस उलझी रही। शहर कोतवाली के मोहल्ला बाग रुस्तम निवासी कासिम जरदोजी कारीगर है। उसकी पत्नी रानी की दोपहर अचानक हालत खराब हो गयी स उसका पति कासिम रानी को निजी चिकित्सक के यहाँ लेकर गया जहाँ मृत घोषित कर दिया। रानी की मौत की सूचना पर उसके भाई आमिर पुत्र यामिन निवासी बंगशपुरा कोहना ने आरोप लगाया की कासिम की किसी अन्य महिला के साथ नजदीकी हैं, लिहाजा कासिम पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया ।

मृतका के दो पुत्र हैं ससूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मऊदरवाजा अमित गंगवार, शहर कोतवाल जेपी शर्मा आदि पुलिस बल के साथ पंहुचे। शहर कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डेढ़ घंटे उलझा रहा सीमा विवाद थाना मऊदरवाजा व शहर कोतवाली पुलिस के बीच सीमा विवाद फंस गया। दोनों थानों की पुलिस अपने-अपने सीमा में घटना न होने की बात करती रही। बाद में सभासद नौशाद मंसूरी के लिखित देने के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

एआरटीओ कार्यालय पहुंची जिलाधिकारी कर्मचारियों को लगाई फटकार

● बिचौलियों से दूर रहने की दी हिदायत, दुकानें बंद कर दलाल हुए फरार

संवाददाता। फतेहपुर

एआरटीओ ऑफिस में दलाल और बाहरी व्यक्तियों से काम कराए जाने की आ रही शिकायतों की हकीकत जानने के लिए गुरुवार को डीएम सी. इंदुमती अचानक एआरटीओ कार्यालय जा पहुंची जहां उन्होंने विधिवत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एआरटीओ को कड़ी चेतावनी देते कहा कि किसी भी हालत में बिचौलियों के माध्यम से कार्य न किए जाएं। साथ ही पटल में कोई भी बाहरी व्यक्ति काम करते नहीं मिलना चाहिए। डीएम के निरीक्षण की खबर मिलते ही दलालों ने दुकानों के शटर गिराकर फरार हो गए।

जिलाधिकारी सी. इन्दुमती ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रिकार्ड रूम, कार्यालय के पटल सहायकों द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं कार्यालय परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया। कार्यालय परिसर के आसपास अवैध दुकानों एवं दलालों का मामला संज्ञान में आने पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए एआरटीओ को तत्काल निर्देशित किया कि बिचौलियों के माध्यम से कोई भी कार्य न हो, जिससे आम जन मानस का कार्य सुगमता से हो। किसी भी पटल पर प्राइवेट लोगों से कार्य न कराया जाए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अविनाश त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक धीरेन्द्र प्रताप, पुलिस क्षेत्राधिकारी, एआरटीओ प्रशासन पुष्पांजलि मित्रा गौतम, प्रवर्तन सहित संबंधित उपस्थित रहे।

दुकानों की जांच कर मांगी रिपोर्ट: निरीक्षण के दौरान डीएम ने एआरटीओ को निर्देश दिया किया कि कार्यालय परिसर के आसपास जितनी भी दुकाने संचालित है, उनकी गम्भीरता के साथ जांच कराएं। स्पष्ट किया कि जांच कराते हुए तीन दिन के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वहीं यह भी निर्देश दिए कि कार्यालय में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए जो भी प्रार्थना पत्र आते हैं, उनका सूचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से निस्तारण हो।

नये रिकार्ड रूम के लिए निर्देश: निरीक्षण के दौरान डीएम को रिकॉर्ड रूम में पर्याप्त जगह न पाए पर उन्होंने नया रिकॉर्ड रूम बनाने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर पत्राचार करते हुए संबंधित रिपोर्ट से अवगत कराने के निर्देश दिए। कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का परमिट, रजिस्ट्रेशन, वाहनों का फिटनेस, बीमा आदि का कार्य समय से किया जाए।

अगस्त से कानपुर सेण्ट्रल-अलीगढ़ फास्ट मेमू चलेगी

● रूरा व झींझक में होगा ठहराव

● यात्रियों में नई मेमू के सॅचालन पर हर्ष की लहर

संवाददाता। कानपुर देहात

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सौगात प्रदान करते हुये 1 अगस्त से कानपुर सेण्ट्रल-अलीगढ मेमू फास्ट ट्रेन के सॅचालन की घोषणा की है। जनपद के रूरा व झींझक स्टेशन पर ही ठहराव होने पर यात्रियों में इस नई ट्रेन के सॅचालन पर हर्ष की लहर दौड गयी है। जनसम्पर्क कार्यालय उ0म0रे0 प्रयागराज द्वारा वुधवार को जारी विज्ञप्ति में 04189/04190 कानपुर-अलीगढ फास्ट मेमू विशेष गाडी(अनारक्षित) के सॅचालन का निर्णय लिया गया है, यह विशेष फास्ट मेमू 1 अगस्त को कानपुर सेण्ट्रल से सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर अलीगढ के लिये रवाना होगी, जनपद के रूरा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन 7 बजकर 54 मिनट पर आयेगी, झींझक में यह विशेष ट्रेन 8 बजकर 14 मिनट पर आकर रूकेगी, कानपुर से चलने के बाद यह ट्रेन पनकी धाम, रूरा, झींझक,फफूँद, भरथना, इटावा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टूँडला, हाथरस के बाद अलीगढ 12 बजकर 40 मिनट पर पहुँचेगी, वापसी में यह विशेष मेमू अलीगढ से दोपहर एक बजकर चालीस मिनट पर कानपुर के लिये

रेलवे प्रशासन द्वारा नई गाडी के सॅचालन की समय सारिणी

रवाना होगी, झींझक स्टेशन पर 5 बजकर 50 मिनट पर, रूरा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन 6 बजकर 11 मिनट पर आयेगी, कानपुर सेण्ट्रल पर यह ट्रेन शाम को 7 बजकर 45 मिनट पर पहुँचेगी। इस विशेष ट्रेन के सॅचालन से भारी सॅख्या में यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा की उम्मीद जतायी जा रही है। 8 डिब्बों की यह ट्रेन 31 जनवरी तक 158 फेरे लगायेगी। इस यात्रीगाडी के सॅचालन की घोषणा पर रूरा चैयरमैन रामजी गुप्ता, व्यापारी नेता श्याम मोहन दुबे, आशीष गुप्ता मोनू, सरदार गुरमीत सिंह, शैलेन्द्र तिवारी, झींझक चैयरमैन सोनू तिवारी, रवीन्द्र शुक्ला भोले, अजय शुक्ला, राघवेन्द्र शुक्ला सहित अन्य लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है।

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष के अस्वस्थ होने से छाई मायूसी

गुरसहायगंज (कन्नौज)। नगर के मोहल्ला रामगंज निवासी पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राजीव ठाकुर का विगत दिन पूर्व अचानक स्वास्थ्य बिगडनें से उनके समर्थकों व शुभचिंतकों में मायूसी दिखाई दे रही है। वहीं विद्यायिका पुत्र एवं समर्थकों ने लखनऊ स्थित हास्पिटल पहुंचकर हाल जाना। बताते चलें कि बीते मंगलवार की सुवह पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राजीव ठाकुर की अचानक तबीयत बिगड गयी।

परिजनों नें आनन फानन में नगर के एक निजी चिकित्सक के यहां दिखाया जहां स्वास्थ्य लाभ न होनें पर लखनऊ स्थित मेदांता हास्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उनके स्वास्थ्य लाभ में निरंतर सुधार हो रहा है। ज्ञात हो कि पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राजीव ठाकुर नें अपनी मृदुभाषिता व लोकप्रियता के सहयोग से जनपद में समाज के लोगों को भाजपा के पक्ष में लामबन्द करनें में सफलता हासिल

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राजीव ठाकुर का फाईल फोटो।

करनें का कार्य किया है। उनकी तबीयत बिगडनें की खबर पर विद्यायिका पुत्र एवं राहुल राठौर, शशांक वर्मा, रानू ठाकुर, अशोक चौरसिया, मोनू वर्मा सहित नागरिकों नें लखनऊ स्थित मेदांता हास्पिटल पहुंचकर उनके हाल लिये। साथ ही उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

शिक्षामित्रों ने श्रद्धांजलि सभा कर निकाला कैंडल मार्च

● मांगों पर विचार न हुआ तो 05 सितंबर को लखनऊ में होगा धरना प्रदर्शन

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने दिवंगत शिक्षामित्र साथियों को जहां भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की वहीं सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल तक कैंडिल मार्च निकाला। बैठक करके शिक्षामित्रों ने समस्याओं पर चर्चा करते हुए अपने हक व अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सभी का हौसला बढ़ाया। जिलाध्यक्ष सुशील तिवारी के नेतृत्व में नहर कालोनी के सामने स्थित एक गेस्ट हाउस में में शिक्षामित्र एकत्र हुए। सर्वप्रथम शिक्षामित्रों ने दिवंगत साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सुशील तिवारी ने बताया कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, जिस पर तमाम शिक्षामित्रों ने मौत को गले लगाया। तब से लेकर अब तक लगभग 12000 शिक्षामित्रों की असामयिक मृत्यु हो चुकी है, तब से अब तक हजारों शिक्षामित्र आर्थिक तंगी का सामना करते हुए मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं। फिर भी 2017 से अब तक सरकार ने शिक्षामित्र की कोई सुधि नहीं ली। जिला महामंत्री रवीन्द्र प्रकाश पटेल ने बताया कि शिक्षामित्र संघ ने तमाम आंदोलन किए, कई बार शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा को भी रखा। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी अपनी पीड़ा से अवगत कराया लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा एवं जिला संयुक्त मंत्री ओम पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अगर मांगों पर विचार नहीं किया तो आगामी पांच सितंबर को लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए हम सब बाध्य होंगे। इस मौके पर अदीप सिंह, अजय सिंह, अनूप तिवारी, आशुतोष द्विवेदी, माया, रेनू, सुचिता पांडेय, राजेश सिंह, शैलेन्द्र वर्मा, मीनू सिंह, सुनील मिश्रा, ओम पटेल, आशुतोष द्विवेदी, अखिलेश गुप्ता, सर्वेश चन्द्र मिश्र, भानु प्रताप सिंह, अनिल श्रीवास्तव, कैलाश, आशीष पटेल, विशाल शुक्ला, शैलेन्द्र सिंह, विष्णु दुबे, संतोष यादव उपस्थित रहे।

नीट परीक्षा की शुचिता में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर दोबारा परीक्षा कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नीट-यूजी, 2024 के पूरे परिणाम में गड़बड़ी हुई थी और परीक्षा की शुचिता में प्रणालीगत उल्लंघन हुआ। शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई को विवादों में घिरी परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा दोबारा कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था और आदेश बुधवार रात को अपलोड किया गया। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए 14 पृष्ठ के अंतरिम आदेश में कहा गया है, वर्तमान चरण में, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा के पूरे परिणाम में गड़बड़ी हुई है या परीक्षा की शुचिता में कोई प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है। करीब 40 याचिकाओं पर विस्तृत और तर्कपूर्ण फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। न्यायालय ने कहा, शहर-वार और केंद्र-वार जो डेटा पेश किया गया है और वर्ष 2022, 2023 और 2024 के डेटा की तुलना से यह संकेत नहीं मिलता है कि प्रश्नपत्र प्रणालीगत रूप से लीक हुआ है और इससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। पीठ ने कहा कि इस वर्ष दोबारा परीक्षा कराने का आदेश परीक्षा में शामिल हुए 20 लाख से अधिक छात्रों के लिए गंभीर परिणामों से भरा होगा। आदेश में कहा गया कि इस तरह की कार्वाई से प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान आएगा, पूरी प्रक्रिया कई महीनों के लिए पीछे चली जाएगी तथा इसका मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पीठ ने कहा कि दोबारा परीक्षा का आदेश भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता को भी प्रभावित करेगा और हाशिए पर पड़े समुदायों तथा कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को भौतिक विज्ञान के एक विवादास्पद प्रश्न के लिए आईआईटी दिल्ली के तीन विशेषज्ञों के पैनल द्वारा सुझाए गए उत्तर को सही मानते हुए अपनी मेरिट सूची को संशोधित करने के लिए भी कहा। इसने इस बात की पड़ताल की कि क्या कथित उल्लंघन प्रणालीगत स्तर पर हुआ था और क्या उल्लंघन ऐसी प्रकृति का था जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता प्रभावित हुई। इसने यह भी पड़ताल की कि क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है। पहले के निर्णयों के अनुसार, यदि धोखाधड़ी के लाभार्थियों को वास्तविक सफल अभ्यर्थियों से अलग करना संभव नहीं है, तो पुन: परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि उस विवाद को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए एक अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी, जिसने 20 लाख से अधिक छात्रों के करियर को प्रभावित किया। आदेश में कहा गया, यह तथ्य कि नीट (यूजी) 2024 का पेपर झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में लीक हुआ, विवाद का विषय नहीं है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए आदेश में कहा गया है कि जांच जारी है और अब तक की जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के अनुसार, हजारीबाग तथा पटना के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले लगभग 155 छात्र प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी के लाभार्थी हैं। पीठ ने दोबारा परीक्षा का आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस बात के सुस्थापित परीक्षण से निर्देशित है कि क्या दागी छात्रों को उन छात्रों से अलग करना संभव है जो बेदाग हैं। इसने कहा, यदि जांच में वर्तमान चरण में संदिग्धों के अलावा लाभार्थियों की बढ़ी हुई संख्या की संलिप्तता का पता चलता है, तो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी चरण में गलत काम में संलिप्त पाए जाने वाले प्रत्एक छात्र के खिलाफ कार्वाई की जाएगी।

न्यायालय ने कहा कि कोई भी छात्र, जिसके बारे में यह पता चलता है कि उसने धोखाधड़ी की है, इस निर्णय के आधार पर भविष्य में प्रवेश जारी रखने के लिए निहित अधिकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा। न्यायालय ने केन्द्र के इस कथन पर गौर किया कि उसने निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्ईय विशेषज्ञ समिति गठित की है। पीठ ने कहा, समिति इस न्यायालय द्वारा अपने अंतिम निर्णय और आदेश में जारी किए जाने वाले ऐसे अन्य निर्देशों का पालन करेगी, जो उन क्षेत्रों के संबंध में हों, जिनकी उसके द्वारा जांच की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि (1)नीट (यूजी) और एनटीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अन्य परीक्षाओं के आयोजन की प्रक्रिया को उचित रूप से मजबूत किया जाए और (2) वर्तमान वर्ष के दौरान सामने आए मामलों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। परीक्षा की शुचिता पर संदेह तब पैदा हुआ जब कुल 67 छात्रों ने एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व 720 अंक प्राप्त किए, जिसमें हरियाणा के एक केंद्र से छह छात्र शामिल थे। एनटीए द्वारा एक जुलाई को संशोधित परिणामों की घोषणा के बाद शीर्ष रैंक साझा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2024 में 23 लाख से अधिक छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) दी थी।

सीयूईटी-यूजी परीक्षा की अंतिम कुंजी जारी नतीजे जल्द घोषित किए जाएंगे : एनटीए

भाषा। नई दिल्ली

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने बृहस्पतिवार को संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा-स्नातक (सीयूईटी-यूजी) की अंतिम कुंजी जारी कर दी। इसी के साथ स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ हो गया। एनटीए ने सात जुलाई को सीईयूटी-यूजी 2024 की वैकल्पिक कुंजी जारी की थी जबकि करीब एक हजार विद्यार्थियों की शिकायत वाजिब होने पर उनकी दोबारा परीक्षा 19 जुलाई को ली गई।

एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अंतिम कुंजी जारी कर दी गई है और परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) सहित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर जारी हंगामे की वजह से सीईयूटी-यूजी 2024 के परिणाम घोषित करने मे देरी हुई है।

सीयूईटी के परिणाम पहले 30 जून को घोषित किए जाने थे लेकिन एनटीए ने नीट-यूजी, यूजीसी-नेट और सीआईएसआर-यूजीसी-नेट में कथित अनिमियतता एवं प्रश्नपत्र लीक के आरोपों की वजह से एनटीए ने नतीजे घोषित करने में देरी की। सीयूईटी-यूजी के तहत 15 विषयों की परीक्षा कलम-कागज के माध्यम से हुई जबकि अन्य 48 विषयों के लिए परीक्षा कंप्यूटर माध्यम से हुई। इस साल 261 केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा के लिए 13.4 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है।

नीट पर न्यायालय का फैसला कांग्रेस की ओछी राजनीति की हार : धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला छात्रों की हार नहीं बल्कि कांग्रेस के गैरजिम्मेदाराना रवैए और ओछी राजनीति की हार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पर्चा लीक और भ्रष्टाचार की जनक है। प्रधान ने एक्स पर लिखा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि परीक्षा की शुचिता में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं पाया गया है। कांग्रेस को भारत सरकार पर तो नहीं पर क्या माननीय उच्च न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है? नीट मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला विद्यार्थियों की नहीं कांग्रेस के गैरजिम्मेदाराना रवैए, कुतर्क और ओछी राजनीति की हार है।

शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से राजस्थान में जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तब हुए पेपर लीक को लेकर सवाल किया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, राजस्थान में भाजपा सरकार आने से पूर्व खटा-खट हुए पेपर लीक क्या खरगे जी के संज्ञान में नहीं हैं? अपनी सरकार में हुए पेपर लीक पर खरगे जी ने मुंह में दही क्यों जमा रखी थी। कांग्रेस पेपर लीक और भ्रष्टाचार की जनक है।

प्रधान ने कहा, देश की जनता ने कांग्रेस को लगातार तीसरी बार नकारा है। लगातार तीसरी बार हार कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। राजनीतिक रोटियां सेकने और तेजी से फिसलती हुई अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए कांग्रेस के पास झूठ, आधा सच और अराजकता एकमात्र सहारा है। नीट-यूजी 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को विवादों से भरी इस परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसकी शुचिता के व्यवस्थागत उल्लंघन के कारण यह दूषित हुई है।

यह फैसला राजग सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के लिए राहत की बात है, जो पांच मई को आयोजित प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक, धोखाधड़ी और प्रतिरूपण जैसे बड़े पैमाने पर कदाचार के आरोप में सड़कों और संसद में कड़ी आलोचना और विरोध का सामना कर रहे थे। प्रधान ने आरोप लगाया, खरगे जी, ना तो आपको, ना आपके नेता राहुल गांधी, ना आपकी पार्टी को विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता है। आपको केवल अपने और एक परिवार के भविष्य की चिंता है।

कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, रासुका के तहत सांसद को जेल में रखना आपातकाल

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि एक निर्वाचित सांसद को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में रखा जाना अघोषित आपातकाल है जिस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने कहा कि चन्नी जेल में बंद चरमपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह का जिक्र कर रहे थे और इससे साबित होता है कि कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग 1975 के आपातकाल की बात करते हैं लेकिन इस समय देश में आर्थिक आपातकाल और अघोषित आपातकाल लगा है। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा, यह आपातकाल ही है कि पंजाब में 20 लाख मतदाताओं द्वारा निर्वाचित एक संसद सदस्य को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निरुद्ध रखा गया है। वह यहां अपने क्षेत्र के लोगों की बात नहीं रख सकते। यह भी आपातकाल है।

चन्नी ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भाजपा नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस सांसद खडूर साहिब लोकसभा से निर्वाचित हुए अमृतपाल सिंह का जिक्र कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद के अंदर दिए गए कांग्रेस सांसद चन्नी के बयान दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने पीटीआई वीडियो से कहा, इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले खालिस्तानियों को आज चन्नी से खुला समर्थन मिला। इसका मतलब है कि कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ है। यह भारत की अखंडता पर हमला है। मेरा कहना है कि कार्वाई होनी चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस को जवाब देना होगा कि क्या पार्टी खालिस्तान के विचार का समर्थन करती है जिस विचार की वजह से 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। कांग्रेस हमेशा अलगाववादियों और आतंकवादियों का समर्थन क्यों करती है? याकूब, अफजल, 26।11 के जिहादी और अब के आतंकवादी? भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने चन्नी को कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग की। उन्होंने पीटीआई वीडियो से कहा, आज चन्नी, जिनकी चवन्नी की हैसियत नहीं है, आतंकवादियों के समर्थन में बोल रहे हैं और उन्हें महिमामंडित कर रहे हैं। वह कनाडा से राष्ट्र-विरोधी तत्वों के इशारे पर काम कर रहे हैं।

बिहार विधानसभा में विपक्ष ने किया जबरदस्त हंगामा

विपक्षी सदस्यों ने नीतीश कुमार सरकार में अविश्वास जताया

पटना। बिहार विधानसभा में बृहस्पतिवार को उस समय जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जब विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ सरकार में अविश्वास व्यक्त करते हुए सदन के बीचों-बीच समानांतर कार्यवाही संचालित करने का प्रयास किया। एक दिन पहले सदन के भीतर महिला विधायकों के प्रति मुख्यमंत्री के अपमानजनक व्यवहार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने के लिए विधानसभा तक मार्च निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में बृहस्पतिवार को विपक्षी महिला विधायक काली पट्टी बांधे हुई थीं। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने प्रश्नकाल चलाने का फैसला किया और कर्मचारियों के लिए रखे गए फर्नीचर को पलटने की कोशिश कर रहे विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा, ए विधानसभा के कर्मचारी हैं। यदि आपके कृत्यों के कारण कोई घायल होता है, तो मैं कड़ी कार्वाई करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। सदन के बीचों-बीच बैठे विपक्षी सदस्यों ने भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम को कुर्सी पर बैठाया गया और उन्हें सदन का अध्यक्ष कहकर संबोधित करते हुए समानांतर कार्यवाही संचालित करने का असफल प्रयास किया।

प्रश्नकाल समाप्त होने तक विपक्षी विधायक सदन के बीचों-बीच डटे रहे लेकिन बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है और वे सदन से बहिर्गमन कर गए। विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए कई स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा, यह अजीब बात है कि जिन लोगों ने ए प्रस्ताव प्रस्तुत किए, उन्होंने सदन में उपस्थित रहने की भी जहमत नहीं उठाई। विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति के बीच शून्यकाल का संचालन किए जाने के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दी।

इस बीच, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन में भी महिला विधायकों के प्रति मुख्यमंत्री के व्यवहार का मुद्दा विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाया गया, जिसके कारण आज की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद सभापति अवधेश कुमार सिंह को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बिहार विधान परिषद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री और उनके करीबी सहयोगी एवं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार का आरोप है कि विपक्ष की महिला विधायकों को कुछ भी पता नहीं है या वे कुछ भी नहीं समझती हैं। ललन मुझ पर बजट को समझने में असमर्थ होने का आरोप लगाते हैं और दावा करते हैं कि मैं किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, इन दोनों नेताओं को ऐसी महिला विरोधी टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। भोजनावकाश के बाद भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही शाम चार बजकर 50 मिनट तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। पूर्व मंत्री और राजद नेता कुमार सर्वजीत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरोप लगाया, ‟22 जुलाई को सत्र के शुरू होने के बाद से विपक्ष के विधायकों को एक मिनट भी बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। वह विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर धरना दे रहे विपक्षी सदस्यों में शामिल थे। बिहार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्षी सदस्यों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए पलटवार किया, ‟अध्यक्ष कुछ सदस्यों को उनकी बारी से इतर बोलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। जब उनकी बारी आई तो वे (विपक्षी सदस्य) हंगामा करते हुए सदन से बाहर चले गए।

झारखंड के दो विधायक दलबदल रोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए

रांची। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने बृहस्पतिवार को दलबदल रोधी कानून के तहत दो विधायकों को अयोग्य ठहराया। यह आदेश 26 जुलाई से प्रभावी होगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के लोबिन हेम्ब्रोम और कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य ठहराने का आदेश शुक्रवार से शुरू हो रहे विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर आया। झामुमो और भाजपा ने क्रमश: हेम्ब्रोम और पटेल के खिलाफ दलबदल रोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग उठाई थी। हेम्ब्रोम ने राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और झामुमो के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हांसदा को चुनौती दी थी। पटेल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे और वह हजारीबाग सीट से चुनाव लड़े थे। दोनों ही हालांकि चुनाव हार गए थे।

संथाल परगना, अररिया, किशनगंज, कटिहार सहित कुछ जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए: सांसद

भाषा। नई दिल्ली

भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना और बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ने तथा हिंदुओं के गांव खाली होने का दावा करते हुए सरकार से इन क्षेत्रों को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की। लोकसभा में शून्यकाल इस मुद्दे को उठाते हुए झारखंड के गोड्डा से सांसद दुबे ने कहा कि साल 2000 में बिहार से झारखंड के अलग होने के समय संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी 36 प्रतिशत थी जो आज 26 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, 10 प्रतिशत आदिवासी कहां खो गए, कहां गायब हो गए। सदन कभी इसकी चिंता नहीं करता। झारखंड की सरकार भी कोई कार्वाई नहीं करती।

दुबे ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए उनके क्षेत्र में आकर आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं। उन्होंने कहा, हिंदू, मुसलमान का सवाल नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा में 267 बूथ पर मुसलमानों की आबादी 117 प्रतिशत बढ़ गई। पूरे झारखंड में 25 विधानसभाओं मे मुस्लिम आबादी 110 से 123 प्रतिशत तक बढ़ी है।

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि झारखंड के पांकुर में पिछले दिनों दंगा हुआ क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और माल्दा से आए लोगों ने तथा बंगाल पुलिस ने स्थानीय हिंदुओं को भगाया। उन्होंने कहा, हिंदुओं के गांव के गांव खाली हो रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड यह बात कह रहा हूं। एक भी बात गलत है तो इस्तीफा देने को तैयार हूं। दुबे ने कहा कि बंगाल से आए लोगों ने जुल्म किया और झारखंड पुलिस ने कोई कार्वाई नहीं की।

उन्होंने कहा कि इन सब घटनाक्रम को देखते हुए झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के माल्दा और मुर्शिदाबाद तथा बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार को मिलाकर केंद्रशासित प्रदेश बना देना चाहिए और यहां राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू की जानी चाहिए, अन्यथा यहां से हिंदू खाली हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इससे भी पहले सदन की एक समिति क्षेत्र में भेजी जाए जिसमें तृणमूल कांग्रेस के सर्वाधिक सदस्यों को रखा जाए। दुबे ने यह दावा भी किया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल में एक आदेश में कहा है कि उक्त क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि विधि आयोग की 2010 की 235वीं रिपोर्ट को लागू किया जाए जिसमें सिफारिश की गई है कि धर्मांतरण और दूसरे धर्म के लोगों से शादी के लिए अनुमति जरूरी है।

एनएचएआई के सामने कोई वित्तीय संकट नहीं: नितिन गडकरी

नई दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) किसी वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा और उसने टोल राजस्व आदि के माध्यम से अपने ऋण को चुकाने की योजना बनाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में माला राय के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी जिन्होंने पूछा था कि क्या एनएचएआई भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। गडकरी ने कहा, एनएचएआई किसी वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि एनएचएआई ने 15,700 करोड़ रुपए के बैंक ऋण का पूर्व भुगतान इनविट मुद्रीकरण प्राप्ति के माध्यम से कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई का ऋण 3.35 लाख करोड़ रुपए है।

गडकरी ने कहा कि सरकार ने एनएचएआई को वित्त वर्ष 2023-24 से धन जुटाने के लिए अधिकृत नहीं किया है। उन्होंने कहा, इस प्रकार ऋण में कमी शुरू हो गई है। गडकरी ने कहा कि एनएचएआई ने टोल राजस्व और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बेहतर प्रवाह के माध्यम से अपने ऋण को चुकाने के लिए एक योजना तैयार की है। उन्होंने कहा, इनविट मोड के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग केवल ऋण चुकाने के लिए किया जाता है। इनविट (अवसंरचना निवेश न्यास) म्यूचुअल फंड के स्वरूप वाली सामूहिक निवेश योजना है, जिसमें निवेशक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश कर पाते हैं।

पेज 1 का शेष

पीएम का दौरा...

15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। शिंकुन ला सुरंग न केवल हमारे सशस्त्र बलों और उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करेगी बल्कि लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देगी। इस अवसर पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक के साथ सेना के दिग्गज, वीर नारियों और शहीद सैनिकों के परिजन कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। इस बीच पंजाब पुलिस ने एक महिला के विवरण के आधार पर एक संदिग्ध का स्केच भी जारी किया है, जिसने फांगटोली में सात संदिग्ध लोगों को देखा था। सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने भूमिगत और सीमा पार सुरंगों का पता लगाने के लिए सांबा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर भी एक अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने कहा, किसी भी सीमा पार सुरंग की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक व्यापक एंटी-टनल अभ्यास शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान में ड्रोन की तैनाती भी शामिल है और संभावित आतंकवादी घुसपैठ से उत्पन्न सुरक्षा खतरों के जवाब में इसे रोजाना चलाया जा रहा है।

ममता...

एक सवाल का जवाब देते हुए जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि हमें बांग्लादेश की ओर से ऐसा संदेश प्राप्त हुआ है। यह अनिवार्य रूप से रिपोर्टों में वर्णित तर्ज पर है। उन्होंने कहा, मैं यह रेखांकित करना चाहूंगा कि हमारे संविधान की सातवीं अनुसूची - सूची एक - संघ सूची - आइटम 10 के तहत, विदेशी मामलों का संचालन और सभी मामले जो संघ को किसी भी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं, एकमात्र विशेषाधिकार हैं केंद्र सरकार। एक्स पर व्यापक रूप से साझा किए गए एक वीडियो में महमूद को यह कहते हुए सुना गया, ममता बनर्जी के प्रति पूरा सम्मान, जिनके साथ हम आपसी हितों का रिश्ता साझा करते हैं... हालांकि, उनके बयान ने भ्रम पैदा कर दिया है और इसमें भ्रम पैदा करने की क्षमता है। इसलिए, हमने उनके बयान पर भारत सरकार को एक नोट भेजा है। महमूद ने राजनयिक माध्यमों से भारत सरकार से संपर्क किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने भी बनर्जी से पड़ोसी बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर कोई भी राजनीति से प्रेरित लोकलुभावन टिप्पणी नहीं करने का आग्रह किया है जो देश के बाहरी मामलों को प्रभावित कर सकती है।

बजट पर...

जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। विपक्षी सदस्यों के विरोध पर बिड़ला ने कहा कि सदन और संसदीय परंपरा का बहुत सम्मान है। रिजिजू ने कहा कि बुधवार को बजट पर शुरू हुई चर्चा के दौरान विपक्षी नेताओं ने बजट पर कुछ नहीं कहा, वे सिर्फ राजनीति में लगे रहे। रिजिजू ने कहा, उन्होंने लोगों के जनादेश का अपमान किया है। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को गाली दी है।

राज्यों के पास...

रॉयल्टी वह भुगतान है जो उपयोगकर्ता पक्ष बौद्धिक संपदा या अचल संपत्ति परिसंपत्ति के मालिक को देता है। प्रविष्टि 49 के अंतर्गत, राज्यों को भूमि और भवनों पर कर लगाने का अधिकार है, जबकि प्रविष्टि 50 राज्यों को खनिज विकास पर कर लगाने की अनुमति देता है, लेकिन यह खनिज विकास से संबंधित संसद द्वारा कानून के तहत लगाई गई किसी भी सीमा के अधीन है प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर), 1957 राज्य को खदानों एवं खनिजों पर कर लगाने से प्रतिबंधित नहीं करता है। पीठ ने कहा, एमएमडीआर अधिनियम में राज्य की कर लगाने की शक्तियों पर सीमाएं लगाने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। एमएमडीआरए के तहत रॉयल्टी कर की प्रकृति में नहीं है। इसने कहा, राज्यों के पास खदानों, खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधाई अधिकार है। शुरू में प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पीठ ने दो अलग-अलग फैसले दिए हैं और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने असहमतिपूर्ण फैसला दिया है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि राज्यों के पास खदानों तथा खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधाई अधिकार नहीं है। प्रधान न्यायाधीश और न्यायमूर्ति नागरत्ना के अलावा पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति उज्ज्ल भुइयां, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं। पीठ ने इन विवादास्पद मुद्दे पर फैसला सुनाया कि क्या खनिजों पर देय रॉयल्टी खान तथा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत कर है। क्या केवल केंद्र को ही ऐसा कर लेने का अधिकार है या राज्यों को भी अपने क्षेत्र में खनिज युक्त भूमि पर कर लेने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने इस जटिल मामले की सुनवाई 27 फरवरी को शुरू की थी, क्योंकि इस मुद्दे पर संविधान पीठ के दो विरोधाभासी फैसले थे।

तकनीक...

और साक्षात्कारों के साथ-साथ प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) सहित सालाना 14 परीक्षाएं आयोजित करता है। 2023 में, 1.01 मिलियन से अधिक लोगों ने सीएसई के लिए आवेदन किया था, जिसमें लगभग 590,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। सीएसई भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने का कार्य करता है।

उप्र में...

सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की निशुल्क बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इसका लाभ ले सकते है, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियां डाउनलोड करनी होगी तथा उसकी एक प्रति परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा के बाद अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 एक जुलाई, 2024 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।

रील बनाने...

यह एक सतत प्रक्रिया है और जितना अधिक आप इसे करते रहेंगे, उतना ही लोग हतोत्साहित होंगे। कुमार ने कहा, लेकिन समस्या यह है कि हमारे पास हर एक कोने की जांच करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। अगर मेट्रो में प्रतिदिन 67 लाख यात्री सफर करते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की निगरानी करना आसान नहीं है। हमारे पास सीसीटीवी है, जिसके माध्यम से हम परिसर में कुछ भी होने पर पता लगा सकते हैं। डीएमआरसी ने कई मेट्रो स्टेशनों पर पोस्टर भी लगाए हैं, जिनमें यात्रियों से रील न बनाने और दूसरों के लिए असुविधा उत्पन्न न करने को कहा गया है।

राष्ट्रपति भवन...

बयान के अनुसार, अशोक शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो सभी कष्टों से मुक्त या किसी भी दुख से रहित है तथा इसके अलावा, अशोक का तात्पर्य एकता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रतीक सम्राट अशोक से है। बयान में कहा गया, भारत गणराज्य का एक राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। इसके अनुसार, अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है। मंडप भाषा में एकरूपता लाता है और अशोक शब्द से जुड़े प्रमुख मूल्यों को बरकरार रखते हुए अंग्रेजीकरण की संस्कृति के निशान को मिटाता है। हॉल का उपयोग विदेशी देशों के मिशन के प्रमुखों द्वारा परिचय पत्र प्रस्तुत करने और राष्ट्रपति द्वारा आयोजित राजकीय भोज की शुरूआत से पहले आने वाले प्रतिनिधिमंडलों के लिए परिचय के औपचारिक स्थान के रूप में किया जाता है।

कठुआ हमले में आतंकियों के दो मददगार गिरफ्तार

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सेना के गश्ती दल पर हुए आतंकी हमले में संलिप्तता के लिए आतंकवादियों के दो कथित मददगारों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकी गतिविधियों से निपटने को लेकर जारी प्रयासों के तहत आतंकियों के दो मददगारों को गिरफ्तार किया है। जिले के दूरस्थ मछेड़ी इलाके में हथियार बंद आतंकवादियों द्वारा आठ जुलाई को घात लगाकर किए गए हमले में एक जूनियर कमीशन अधिकारी सहित सेना के पांच जवान शहीद हुए थे और पांच अन्य लोग घायल हुए थे। प्रवक्ता ने बताया, इन व्यक्तियों ने पुलिस से महत्वपूर्ण जानकारी जानबूझकर छिपाई थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बिलावर के कलना धानू परोल के रहने वाले लायाकत अली उर्फ पावू और मल्हार के बौली मोहल्ला के रहने वाले मूल राज उर्फ जेनजू के रूप में हुई है। प्रवक्ता के अनुसार, दोनों ने पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिससे आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई।उन्होंने बताया कि मल्हार थाने में अली और राज के खिलाफ और इग्रेस एंड इंटरनल मूवमेंट कंट्रोल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

राष्ट्रपति मुर्मू शिक्षिका की भूमिका में आईं नजर

बच्चों से ग्लोबल वार्मिंग रोकने पर किया संवाद

भाषा। नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कार्य करते हुए दो साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस अवसर वह शिक्षिका की भूमिका में नजर आईं और विद्यार्थियों से ग्लोबल वार्मिंग और इसे रोकने के तरीकों पर संवाद किया। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने जल संरक्षण पर जोर दिया और उन्हें अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि जलवायु परिवर्तन के असर को कम किया जा सके। कक्षा के 53 विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, मैं पिछले कई दिनों से सोच रही थी कि आपसे बात करूं क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।

संवाद की शुरुआत में राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से उनकी अभिलाषा और पसंदीदा विषयों के बारे में पूछा तथा यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि विद्यार्थी वैज्ञानिक और डॉक्टर बनने को इच्छुक हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, पूरी दुनिया में वैज्ञानिक, जनता, प्रशासक और शासक बहुत बड़ी समस्या पर संगोष्ठी, सम्मेलन और सभा कर रहे हैंअ क्या आप जानते हैं वह समस्या क्या है? इस पर तुरंत विद्यार्थियों ने जवाब दिया, जलवायु परिवर्तन , ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने स्कूल में पढ़ा था कि छह ऋतुएं होती हैं लेकिन हम केवल चार महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, इन चारों में से सबसे ज्यादा गर्मी का एहसास हमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। दिन-ब-दिन तापमान बढ़ता जा रहा है और इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों, पक्षियों और पेड़ों पर भी पड़ रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देश के कई हिस्से सूखे की मार झेल रहे हैं, इसलिए जल संरक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा, बच्चे यह भी जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और हमें और पेड़ लगाने चाहिए। हमें पानी की बर्बादी को रोकने और उसके संरक्षण के लिए कदम उठाना चाहिए। हमें वर्षाजल को जमा करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि जरूरत से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि और अधिक पेड़ लगाने, जंगलों को बचाने और वायु प्रदूषण कम करने की जरूरत है तभी हम भविष्य मे इसे (ग्लोबल वार्मिंग) रोकने में सक्षम होंगे। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू एक पेड़ मां के नाम पहल का जिक्र करते हुए विद्यार्थियों से अपने जन्मदिन पर भी पेड़ लगाने को कहा। उन्होंने कहा, मुझे वास्तव में आपके साथ संवाद कर खुशी हो रही है।मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आप नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आप नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। आप ग्लोबल वार्मिंग के असर के बारे में सचेत हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप बड़े होंगे तब ग्लोबल वार्मिंग निश्चित तौर पर कम होगी। ओडिशा के मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन होने से पहले मुर्मू 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल पद पर भी आसीन थीं।

उत्तराखंड में बनेगा चारधाम डैशबोर्ड

देहरादून। उतराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बृहस्पतिवार को कहा कि चारधाम यात्रा के प्रभावी प्रबंधन के लिए उत्तराखंड में जल्द ही डैशबोर्ड बनाया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) द्वारा तैयार किए जा रहे चारधाम डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए रतूड़ी ने कहा कि डैशबोर्ड चारधाम से संबंधित सभी विभागों के मध्य सूचनाओं के प्रभावी आदान प्रदान व डेटा साझा करने का माध्यम बनेगा जिससे विभागों में प्रभावी समन्वय स्थापित होगा। उन्होंने इसके लिए सभी विभागों में एक-एक नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने चारधाम डैशबोर्ड में यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित क्षेत्र), स्लिपिंग जोन (फिसलन वाले क्षेत्र), मुख्य मार्गों के अलावा वैकल्पिक मार्गों की जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें मलबे, भूस्खलन या यातायात जाम से बाधित सड़कों, सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े अनिवार्य रूप से अपडेट किए जाएं तथा धामों में खराब मौसम या अन्य कारणों से हैली सेवा रद्द होने की पूर्व जानकारी अनिवार्य रूप से अपडेट की जाए। इसके अलावा, उन्होंने पशुपालन विभाग को चारधाम डैशबोर्ड में यात्रा मार्ग पर खच्चरों के लिए चारे, पीने के गर्म पानी, पशुचिकित्सकों की उपलब्धता की जानकारी भी नियमित रूप से अपडेट करने की हिदायत दी।

केंद्र का प्रस्ताव : इलाहाबाद उच्च न्यायालय आगरा, मेरठ से वीडियो कांफ्रेंस से करे सुनवाई

भाषा। नई दिल्ली

केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कुछ मामलों की मेरठ और आगरा से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई करने का प्रस्ताव भेजा है तथा उसे उम्मीद है कि इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। कानून एवं विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी पीठ मेरठ और आगरा में स्थापित हो, यह विषय लंबे समय से चल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ई-कोर्ट प्रोजेक्ट-तृतीय के माध्यम से ऐसा प्रयास कर रही है।

मेघवाल ने कहा, हमने (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के) मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि कुछ सुनवाई मेरठ से की जा सकती है, आगरा से की जा सकती है। उसका (पत्र का) जवाब अभी आया नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सकारात्मक उत्तर आने की संभावना है। मेघवाल ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने के प्रश्न पर कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने सरकार से जानना चाहा कि सरकार जब सर्किट बेंच या क्षेत्रीय पीठ बनाने पर विचार करेगी तो क्या वह देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ बनाने पर विचार करेगी? उन्होंने यह भी पूरक प्रश्न किया था कि क्या सरकार उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 62 से बढ़ा कर 65 वर्ष और 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने पर विचार करेगी, वेतन एवं भत्तों के साथ? एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में मेघवाल ने कहा कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के तहत की जाती है, जिसमें किसी भी जाति या वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से संबंधित श्रेणीवार आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। उन्होंने कहा कि 2018 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के लिए अनुशंसित व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार निर्धारित प्रारूप में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में विवरण प्रदान करना आवश्यक है। मेघवाल ने बताया कि 2018 से नियुक्त उच्च न्यायालय के 661 न्यायाधीशों में से 21 अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं, 12 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं, 78 अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और 499 सामान्य श्रेणी के हैं।

संविधान सम्मत संघीय गणराज्य के ढांचे की अवहेलना करता है केंद्रीय बजट: सांसद

नई दिल्ली (भाषा)। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का वित्त वर्ष 2024-25 का बजट बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के बनाए संविधान का अपमान है और इसमें संघीय गणराज्य के ढांचे की अवहेलना की गई है।

भदौरिया ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, बजट में संविधान सम्मत संघीय गणराज्य के ढांचे को पूरी तरह दरकिनार करते हुए सरकार को बचाने का समर्थन मूल्य चुकाया गया है। उन्होंने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए किए गए सहायता प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि इस बजट को अंग्रेजी की वर्णमाला के केवल दो शुरुआती अक्षरों ए (आंध्र प्रदेश) और बी (बिहार) तक सीमित रखा गया है और अन्य अक्षरों यानी देश के अन्य प्रदेशों की अनदेखी की गई है। भदौरिया ने आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए भी विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सांसदों की सिफारिश पर पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए जाने चाहिए। भाकपा (माले) के राजाराम सिंह ने बजट को किसानों, गरीबों और युवाओं का विरोधी बताया और कहा कि इसमें लोकसभा चुनाव में मिले जनादेश का उल्लंघन किया गया है उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से थी, लेकिन इस सरकार ने इसे पूरा नहीं किया। सिंह ने कहा कि बजट में बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान निकालने और गरीबी को मिटाने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल द्रमुक के सी एन अन्नादुरई ने बजट को लोकतंत्र-विरोधी बताया। कांग्रेस के शशिकांत सेंथिल ने कहा कि यह बजट केवल दो राज्यों के लिए प्रेमपत्र की तरह है, लेकिन यह वास्तविक प्यार नहीं है। उन्होंने बजट में तमिलनाडु की पूरी तरह अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बजट में मनरेगा का आवंटन कम कर दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह ने कहा कि वह बजट से निराश हैं, क्योंकि इसमें गरीबों और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है।

चूक का अहसास करने में सरकार को लगभग पांच दशक लग गए

संघ से जुड़े मामले में मप्र उच्च न्यायालय

इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार को अपनी इस चूक का अहसास करने में करीब पांच दशक लग गए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरीखे विश्वप्रसिद्ध संगठन को सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित संगठनों की सूची में गलत तरह से शामिल किया गया था। अदालत ने संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी रोक हटाने के सरकार के हालिया फैसले के हवाले से यह तल्ख टिप्पणी की। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी पुरुषोत्तम गुप्ता की रिट याचिका का निपटारा करते यह टिप्पणी की। गुप्ता ने 19 सितंबर 2023 को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के साथ ही केंद्र सरकार के उन कार्यालय ज्ञापनों को चुनौती दी थी जो संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने में बाधा बन रहे थे। पीठ ने केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय को निर्देश भी दिया कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर नौ जुलाई के उस कार्यालय ज्ञापन को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करे जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटाई गई है। अदालत ने इस ज्ञापन को देश भर में केंद्र सरकार के सभी विभागों और उपक्रमों को 15 दिन के भीतर भेजने का निर्देश भी दिया। इंदौर में रहने वाले याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम गुप्ता ने पीटीआई-भाषा से कहा, मैं संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी रोक हटाने के केंद्र सरकार के फैसले से जाहिर तौर पर खुश हूं। मेरे पिता संघ की शाखा में जाते थे और सेवानिवृत्ति के बाद मैं भी संघ की गतिविधियों से जुड़ना चाह रहा था।गुप्ता ने बताया कि वह केंद्रीय भण्डारण निगम के अधिकारी के पद से 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कहा,"अब मेरे जैसे हजारों लोगों के लिए संघ से जुड़ने की राह आसान हो गई है।

राष्ट्रीय संग्रहालय की इमारत के बारे में अभी फैसला नहीं किया गया

नई दिल्ली (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद को बताया कि प्रस्तावित नए युगे युगीन भारत संग्रहालय में न केवल राष्ट्रीय संग्रहालय बल्कि भारत के अन्य संग्रहालयों की कलाकृतियों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।जनपथ पर स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की वर्तमान इमारत के भविष्य के बारे में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मौजूदा इमारत पर निर्णय लिया जाना बाकी है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य जवाहर सरकार ने यह लिखित सवाल पूछा था। उन्होंने सरकार से पूछा कि राष्ट्रीय संग्रहालय को गिराकर केंद्रीय सचिवालय की साझा इमारतें बनाने के फैसले पर सरकार का वर्तमान नजरिया क्या है। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई सभी प्राचीन वस्तुओं को नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में प्रस्तावित युगे युगीन भारत संग्रहालय में स्थानांतरित किया जा रहा है या उनका सिर्फ एक हिस्सा स्थानांतरित करने की योजना है।केंद्रीय मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय संग्रहालय की मौजूदा इमारत के बारे में अभी फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, प्रस्तावित संग्रहालय में न केवल राष्ट्रीय संग्रहालय बल्कि भारत के अन्य संग्रहालयों की कलाकृतियां भी शामिल किए जाने की संभावना है। तृणमूल सदस्य ने यह भी पूछा कि क्या सरकार या राष्ट्रीय संग्रहालय ने प्रस्तावित नए संग्रहालय या राष्ट्रीय संग्रहालय की खातिर परामर्श परियोजना के लिए पेरिस के लौवर संग्रहालय के साथ हस्ताक्षर किए हैं या ऐसी कोई बातचीत की है।

शेखावत ने कहा कि यह मंत्रालय दोनों देशों के बीच 2020 में हस्ताक्षरित आशय पत्र के आधार पर फ्रांस के संग्रहालयों के साथ एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा, इस संबंध में मसौदा मंत्रिमंडल नोट पर अंतर-मंत्रालई परामर्श किया जा रहा है। एक बार पूरा होने के बाद, इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। प्रस्तावित युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में आठ विषयगत खंड होंगे जो 5,000 वर्षों की भारत की कहानी प्रदर्शित करेगा। माना जा रहा है कि बन जाने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा।एक अन्य सवाल में उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार को हाल में खोजी गई औपनिवेशिक काल की उस फाइल की जानकारी है जिसमें ब्रिटेन के शाही खजाने में मौजूद भारतीय आभूषणों का ब्योरा है, जिनमें महाराजा रणजीत सिंह से जुड़ी वस्तुएं भी शामिल हैं।

वामपंथी उग्रवाद के कारण छत्तीसगढ़ से विस्थापित आदिवासी लौटने को तैयार नहीं

नई दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि वामपंथी उग्रवाद के कारण छत्तीसगढ़ से विस्थापित आदिवासी परिवार पुनर्वास योजनाओं और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद वापस लौटने को तैयार नहीं हैं। जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उइके ने कांग्रेस सदस्य फूलो देवी नेताम के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के कारण छत्तीसगढ़ से विस्थापित आदिवासी परिवारों की पहचान के लिए पड़ोसी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती जिलों में सर्वेक्षण के वास्ते दलों का गठन किया था। उन्होंने बताया कि वामपंथी उग्रवाद के कारण सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों से 2,389 परिवारों के कुल 10,489 आदिवासी लोग विस्थापित हुए हैं। सुकमा से 9,702अ बीजापुर से 579 और दंतेवाड़ा से 208 लोग विस्थापित हुए हैं। मंत्री ने कहा,"प्रभावित परिवार राज्य सरकार की पुनर्वास योजनाओं की जानकारी देने और सुरक्षा शिविरों के माध्यम से उपलब्ध सुरक्षा के बावजूद अपने मूल गांवोंस्थान पर लौटने को तैयार नहीं हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने जुलाई 2019 में छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र को 13 दिसंबर, 2005 से पहले वामपंथी उग्रवाद के कारण विस्थापित आदिवासी लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने को कहा था, ताकि उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

सरकार ने अनचाहे कॉल, संदेशों पर अंकुश के मसौदे पर टिप्पणियां देने की समय-सीमा आठ अगस्त तक बढ़ाई

नई दिल्ली(भाषा)। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने प्रचार-प्रसार संबंधी फोन कॉल और एसएमएस जैसे अनचाहे एवं अवांछित कारोबारी संचार पर लगाम लगाने से संबंधित दिशानिर्देशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर बृहस्पतिवार को आठ अगस्त कर दी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विभिन्न महासंघों, संघों और अन्य हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर तारीख बढ़ाई गई है। इस पहले टिप्पणियां प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई थी।

मंत्रालय ने कहा कि उसे विभिन्न सुझाव तथा टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिन पर फिलहाल गौर किया जा रहा है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और नियामकों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए इन दिशानिर्देशों में व्यक्तिगत संचार को नहीं रखा गया है। इसमें कारोबारी संचार को प्रचार तथा सेवा संदेशों जैसी वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित किसी भी संचार के रूप में परिभाषित किया गया है। ए दिशानिर्देश कारोबारी संचार से जुड़े सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होंगे। दिशानिर्देशों के मसौदे के मुताबिक, व्यक्ति की रजामंदी या पंजीकृत प्राथमिकताओं का ध्यान न रखने वाला कोई भी कारोबारी संचार अनचाहे और अवांछित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा अपंजीकृत नंबर या एसएमएस हेडर का उपयोग करना, कॉल न आने का विकल्प चुनने के बावजूद कॉल करना, डिजिटल सहमति न लेना, कॉल करने वाले और उद्देश्य की पहचान न करना और सहमति बंद करने का विकल्प न देने जैसी स्थितियां भी अनचाही और अवांछित कारोबारी संचार की श्रेणी में रखी जाएंगी। इनमें ऐसे संचार पर भी रोक लगाने का प्रावधान है जो ग्राहक वरीयताओं के आधार पर वाणिज्यिक संदेशों पर दूरसंचार नियामक ट्राई के नियमों का उल्लंघन करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के 2018 के नियम पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों के लिए डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) पर पंजीकरण असरदार रहा है।

विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर शीर्ष अदालत ने उप्र सरकार से जवाब मांगा

नई दिल्ली। (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार से विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर जवाब मांगा। अंसारी ने उस मामले में जमानत का अनुरोध किया है जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न लोगों को जबरन वसूली के लिए धमकाया। अंसारी की पत्नी चित्रकूट जिला जेल में बंद अपने पति अंसारी से मुलाकात के लिए जाती थी। मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक अंसारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के एक मई के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसमें मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। फरवरी 2023 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंसारी की पत्नी औपचारिकताओं और निर्धारित पाबंदियों का पालन किए बिना अक्सर जेल में उनसे मिलने जाती थी।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि यह आरोप लगाया गया था कि अंसारी ने अपनी पत्नी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और जबरन वसूली के लिए विभिन्न लोगों को धमकाया। यह भी आरोप लगाया गया कि अंसारी की पत्नी का चालक जेल अधिकारियों की मदद से जेल से अंसारी के भागने की साजिश रच रहा था। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अंसारी की याचिका बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। शीर्ष अदालत ने अंसारी की याचिका पर राज्य से जवाब मांगा और इस पर सुनवाई दो सप्ताह बाद करना निर्धारित किया। अब्बास अंसारी गैंगस्टर-नेता और कई बार विधायक रह चुके मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार अंसारी की कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अंसारी, विधानसभा के सदस्य होने के नाते एक जिम्मेदार पद पर हैं और उनका आचरण उच्च स्तर का होना चाहिए।

कॉन्वेंट स्कूल में छात्रों को संस्कृत का श्लोक पढ़ने से रोकने के आरोप में प्रधानाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज

गुना (मध्य प्रदेश)। मध्य प्रदेश के गुना शहर में एक निजी स्कूल की प्रधानाचार्य के खिलाफ विद्यार्थियों को संस्कृत का श्लोक पढ़ने से रोकने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानाचार्य ने इस मामले में माफी मांग ली है। उन्होंने बताया कि कथित घटना 15 जुलाई को वंदना कॉन्वेंट स्कूल में सुबह की सभा के दौरान हुई, जब तीन विद्यार्थियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखमया का पाठ किया। आरोप है कि प्रधानाचार्य सिस्टर कैथरीन ने उनसे माइक छीन लिया और कहा कि स्कूल में ऐसे श्लोक बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में घटना का विवरण दिया गया है। दो दिन बाद कथित घटना के बारे में पता चलने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों ने स्कूल में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। एबीवीपी से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। सूत्रों ने बताया कि उनके आग्रह पर सिस्टर कैथरीन वहां पहुंचीं और इस मुद्दे पर माफी मांगी। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानाचार्य ने कहा कि वह दिन केवल अंग्रेजी में बातचीत के लिए आरक्षित था और इसीलिए विद्यार्थियों को रोका गया। सूत्रों के अनुसार, प्रधानाचार्य ने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और अगर उन्होंने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो उन्हें खेद है। अधिकारी ने बताया कि माफी मांगने के बावजूद प्रदर्शनकारी प्रधानाचार्य के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और उन्हें हटाने की मांग करते रहे तथा वे दो घंटे से अधिक समय तक परिसर में रहे और मांग की कि स्कूल में रोजाना श्लोक का पाठ किया जाए। अधिकारी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) चंद्र शेखर सिसोदिया भी स्कूल पहुंचे और आश्वासन दिया कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग से मुलाकात की

एलएसी का पूर्ण सम्मान करने की जरूरत बताई

भाषा। वियनतियान (लाओस)

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बृहस्पतिवार को यहां अपने चीनी समकक्ष वांग ई से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) तथा पिछले समझौतों का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस महीने दूसरी बार मिले दोनों नेताओं ने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए जाने की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की।

लाओस में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर

जयशंकर ने यहां आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान वांग से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, सीपीसी (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना) पोलित ब्यूरो सदस्य और (चीन के) विदेश मंत्री वांग ई से आज वियनतियान में मुलाकात की। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा जारी रही। सीमा की स्थिति निश्चित रूप से हमारे संबंधों की स्थिति पर प्रतिबिंबित होगी। दोनों के बीच वार्ता पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद जारी रहने के बीच हुई जो मई में अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश कर गया।

जयशंकर ने कहा, वापसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता पर सहमति बनी। एलएसी और पिछले समझौतों का पूरा सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हमारे संबंधों को स्थिर करना हमारे आपसी हित में है। हमें वर्तमान मुद्दों पर उद्देश्य और तत्परता की भावना का रुख रखना चाहिए।

दोनों नेताओं ने इस महीने की शुरुआत में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। भारत का कहना है कि जब तक सीमा क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। मई 2020 से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध है तथा सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, हालांकि दोनों पक्ष टकराव वाले कई बिंदुओं से पीछे हटे हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई थी, जो दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था।

अलास्का के नजदीक रूस और चीन के बमवर्षक विमान देखे गएः उत्तर अमेरिकी एरोस्पेस कमान

बीजिंग। चीन और रूस के लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम चार बमवर्षक विमानों को अलास्का के नजदीक अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के ऊपर उड़ते देखा गया, जिसके जवाब में अमेरिका तथा कनाडा ने अपने लड़ाकू विमान भेजे। अमेरिका एवं कनाडा की संयुक्त एरोस्पेस कमान ने एक बयान में यह जानकारी दी। रूस और चीन दोनों के दो-दो विमान थे। नार्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमान (एनओआरएडी) ने कहा कि चीन और रूस की सैन्य गतिविधि को खतरे के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। चीन और रूस ने बृहस्पतिवार को पुष्टि की कि उसने रूस को अलास्का से अलग करने वाले बेरिंग सागर के ऊपर संयुक्त रूप से हवाई गश्त की। कमान ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, एनओआरएडी उत्तरी अमेरिका के नजदीक प्रतिद्वंद्वी गतिविधियों की लगातार निगरानी करेगा।

जयशंकर ने आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक की

वियनतियाने (लाओस)। विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने बृहस्पतिवार को आसियान बैठक से इतर फिलीपीन के अपने समकक्ष एनरिक एम मनालो और नार्वे के एस्पेन बार्थ इडे से मुलाकात की और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। जयशंकर ने तिमोर लेस्ते के विदेश मंत्री बेंडिटो फ्रेटास और कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री सोक चेंदा सोफिया के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। जयशंकर और अन्य सभी नेता इस समय लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओस) की राजधानी वियनतियान में आसियान ढांचे के तहत आसियान-भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं।

जयशंकर की दक्षिणी पूर्वी एशियाई समकक्षों के साथ बातचीत मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीति पर केंद्रित रही जबकि उन्होंने नार्वे के नेता के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चर्चा की।

नार्वे के विदेशमंत्री के साथ बैठक के बाद जयशंकर ने कहा, आज एस्पेन बार्थ इडे से मुलाकात अच्छी रही। भारत और नार्वे की स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार में साझेदारी जारी रहेगी। दोनों देशों की बेहतरी के लिए यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते (ईएफटीए) को क्रियान्वित करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। भू राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि वह अपने मित्र फिलीपीन के एनरिक एम मनालो से मिलकर खुश हैं। दोनों लोकतंत्रों के बीच मजबूत होते हमारे सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी, विशेष रूप से कानून के शासन और आसियान की प्रमुखता बनाए रखने पर चर्चा की।

कमला हैरिस शासन करने के योग्य नहीं : डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस देश में शासन करने के योग्य नहीं हैं। हैरिस के संभावित उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी पर यह तीखा हमला किया। राष्ट्रपति जो बाइडन (81) ने बीते सप्ताहांत में राष्ट्रपति पद की चुनावी दौड़ से अपना नाम वापस लिए जाने के बाद कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन किया था। हैरिस (59) अब संभावित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं और अगस्त में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में उन्हें आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। ट्रंप ने कहा, कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की सबसे उदार निर्वाचित राजनीतिज्ञ हैं। वह एक अति-उदारवादी राजनीतिज्ञ हैं। वह बर्नी सैंडर्स से भी ज्यादा उदार हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने आरोप लगाया, अगर वह कभी सत्ता में आईं तो वह इस देश को बहुत तेज़ी से नष्ट कर देंगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हैरिस सीमा की सरदार थीं, लेकिन वह कभी सीमा पर नहीं गईं। ट्रंप ने कहा, अगर कमला आपसे जो बाइडन की मानसिक अक्षमता के बारे में इतनी बेशर्मी से झूठ बोलेंगी, तो वह आपसे किसी भी चीज़ के बारे में झूठ बोल सकती है।

मोदी की रूस यात्रा के समय को लेकर निराश अमेरिकाः अमेरिकी अधिकारी

वाशिंगटन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऐसे समय रूस की यात्रा करने को लेकर अमेरिका निराश है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन यहां नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे। यह बात अमेरिकी विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन सांसदों से कही, जिन्होंने भारत-रूस के बढ़ते संबंधों को लेकर चिंता जाहिर की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8-9 जुलाई को रूस की आधिकारिक यात्रा की थी। यह यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से मोदी की पहली रूस यात्रा थी। भारत ने 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की अभी तक निंदा नहीं की है और लगातार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के समाधान की वकालत की है।

दक्षिण एवं मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने मंगलवार को यहां संसदीय बैठक में अमेरिकी सांसदों से कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा के प्रतीकवाद और समय को लेकर हमारी निराशा के बारे में आपसे पूरी तरह सहमत हूं। हम अपने भारतीय मित्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि मैं उस यात्रा के संदर्भ पर कुछ प्रकाश डालूं तो संभव है कि आप कुछ आश्वस्त हों। मॉस्को जाने से दो सप्ताह पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के इतर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात की थी। लू ने कहा कि मॉस्को में रहने के दौरान मोदी ने क्या किया, इस पर अमेरिका सावधानीपूर्वक गौर कर रहा है। उन्होंने कहा, हमने कोई नया बड़ा रक्षा सौदा नहीं देखा। हमने प्रौद्योगिकी सहयोग पर कोई बड़ी चर्चा नहीं देखी। इसके अलावा, आपने देखा होगा कि मोदी ने पुतिन के सामने टेलीविजन पर सीधे प्रसारण में कहा था कि यूक्रेन में युद्ध को युद्ध के मैदान में नहीं जीता जा सकता और युद्ध में बच्चों की मौत को देखकर उन्हें कितना दर्द हुआ था।

लू ने कहा, यह परोक्ष तौर पर कीव में बच्चों के अस्पताल पर बमबारी का संदर्भ है, जो उनके वहां रहने के दौरान हुआ था। महोदय, मैं इस यात्रा के बारे में आपकी चिंता को समझता हूं और हम उन चिंताओं को सीधे भारतीयों तक पहुंचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। भारतीयों ने पिछले ढाई सालों में अरबों डॉलर की रक्षा खरीद को रद्द कर दिया है क्योंकि रूस अब आपूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। लू आठ जुलाई को कीव के ओहमाटडाइट चिल्ड्रेन हॉस्पिटल पर हुए हमले का जिक्र कर रहे थे, जब रूस ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल दागी थीं। इस हमले में अस्पताल में भर्ती दो लोगों सहित कम से कम 42 लोग मारे गए थे।

चीन हिंद महासागर में घुसपैठ कर रहा हैः अमेरिकी सांसद

वाशिंगटन। अमेरिका की एक प्रभावशाली सांसद ने दावा किया है कि चीन हिंद महासागर के प्रमुख क्षेत्रों में अपनी पैठ बना रहा है और इस जल क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार में बाधा डाल रहा है, जिससे अमेरिका और दक्षिण एशिया में उसके मित्र देशों और सहयोगियों की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों पर खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी संसद में मंगलवार को सत्र के दौरान महिला सांसद यंग किम ने कहा कि वैश्विक व्यापार के लिए हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण मार्ग है जहां 80 प्रतिशत समुद्री तेल व्यापार और 40 प्रतिशत विश्व व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरता है। विदेश मामलों की समिति में हिंद-प्रशांत के मुद्दों से संबंधित उपसमिति की अध्यक्ष यंग ने मंगलवार को कहा, हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के महत्व को नहीं भूल सकते। अमेरिकी सांसद यंग किम ने कहा कि दक्षिण एशिया अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किम ने कहा कि इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आ रहा है, जिससे अमेरिका के समक्ष कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) हिंद महासागर में महत्वपूर्ण मार्गों पर कब्जा कर रही है और इस जल क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार में बाधा डाल रही है। हाल के वर्षों में हमने पाकिस्तान और श्रीलंका में चीन के बंदरगाहों, जिबूती में सैन्य प्रतिष्ठानों और मालदीव के बुनियादी ढांचे में चीन के निवेश को देखा है, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितों तथा क्षेत्र में हमारे मित्रों और सहयोगियों के लिए खतरा बन रहा है। किम ने कहा, पिछले महीने मेरी उपसमिति ने हिंद-प्रशांत बजट, दक्षिण चीन सागर तथा ताइवान जलडमरूमध्य पर चीन के आक्रमक रुख पर चर्चा की थी। सीसीपी भारत की नियंत्रण रेखा पर सीमा संघर्ष को भी बढ़ा रहा है और इसकी पनडुब्बियां और युद्धपोत नियमित रूप से हिंद महासागर में आवागमन कर रहे हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संसाधन-समृद्ध दक्षिण चीन सागर को व्यापक रूप से वैश्विक संघर्ष के लिए संभावित केंद्र बिंदु के रूप में देखा जाता है। चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इस समुद्री क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं।

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank | **शाखा कार्यालयः** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नं. 23, शाल टॉवर, तीसरी मंजिल न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ने आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा(ओं) के लिए मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है। ऋण(ओं) को गैर-निष्पादित आस्ति(यों) (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, इसे तामील नहीं किया गया है और इसलिए इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर का नाम और पता (ऋण खाता सं.)	सुरक्षित आस्तियों का विवरण	नोटिस भेजने की तिथि / नोटिस की तिथि तक बकाया	एनपीए की तिथि
1.	ऋषि सिंह/आदित्य सिंह/संतोष देवी, खाता नं. LBROH00005173146, निवासीः 659/1, विशाल नगर हरियाणा रोहतक 124001	फ्लैट नं. एल-02, भूतल, द रोसेलिया 2, टॉवर - एल, जोकि सैक्टर-95ए, गुड़गांव, हरियाणा- 122001 में स्थित	29/06/2024 रु. 17,41,286/-	04/04/2024

ये कदम नोटिस की प्रतिस्थापित तामील के लिए उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ता/ओं और/या गारंटरों/ओं (जैसा लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने की सलाह दी जाती है। अन्यथा, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

दिनांक : जुलाई 26, 2024
स्थानः दिल्ली

भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी
कृते आई सी आई सी आई बैंक लि.

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank | **शाखा कार्यालयः** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नं. 23, शाल टॉवर, तीसरी मंजिल न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ने आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा(ओं) के लिए मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है। ऋण(ओं) को गैर-निष्पादित आस्ति(यों) (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, इसे तामील नहीं किया गया है और इसलिए इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर का नाम और पता (ऋण खाता सं.)	सुरक्षित आस्तियों का विवरण	नोटिस भेजने की तिथि / नोटिस की तिथि तक बकाया	एनपीए की तिथि
1.	निधि/अमृता नंद बडोला (LBDEH00002870577) और 15/215, मालवीय नगर, नई दिल्ली- 110017	फ्लैट नं. 53 डी, एमआईजी आईएसबीटी आवासीय योजना देहरादून उत्तरांचल- 248002	18/06/2024 रु. 4,43,600/-	04/04/2024
2.	दीपक तोमर/ जी पी सिंह (LBBAR00003213793) और पुत्र ज्ञानेंद्र पाल सिंह, मकान नं. 170, सेक्टर 2, ग्रेटर ग्रीन पार्क, बरेली बिशॉप स्कूल के पास, आरके यूनिवर्सिटी रोड, नवबांज यू.पी., उत्तर प्रदेश, बरेली - 243006	प्लॉट नं. 170, खसरा नं. 62 मिंजुमला, ग्रेटर ग्रीन पार्क, ग्राम हरुनगला, तहसील और जिला बरेली, उत्तर प्रदेश-243001 में स्थित	03/07/2024 रु. 3,03,885/-	07/04/2024

ये कदम नोटिस की प्रतिस्थापित तामील के लिए उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ता/ओं और/या गारंटरों/ओं (जैसा लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करने की सलाह दी जाती है। अन्यथा, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

दिनांक : जुलाई 26, 2024
स्थानः दिल्ली/एनसीआर

भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी
कृते आई सी आई सी आई बैंक लि.

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank | **शाखा कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर 23, शॉल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।

कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	रितु जैन/राहुल जैन/ LBDEL00002402048	एल.आई.जी. फ्लैट नं. 14, तीसरी मंजिल, ब्लॉक-ए1, पॉकेट-5, सेक्टर-35, रोहिणी, दिल्ली- 110085/ जुलाई 22, 2024	अप्रैल 17, 2024 रु. 9,28,256/-	दिल्ली/ एनसीआर
2.	चिराग सिंघल/मिंटू सिंघल/लीला रानी/ LBDEL00005472662	संपत्ति बेयरिंग संख्या 301, दूसरी मंजिल, बिना छत/टेरेस अधिकार के, ब्लॉक-डी, प्रशांत विहार आवासीय योजना के लेआउट प्लान में स्थित (उक्त संपत्ति के अंतर्गत भूमि के आनुपातिक 1/4 फ्री-होल्ड अधिकारों के साथ) दिल्ली- 110085/ जुलाई 22, 2024	मार्च 21, 2024 रु. 55,09,282/-	दिल्ली/ एनसीआर
3.	ओम प्रकाश बत्रा/ममता बत्रा/चंचल कांता बत्रा/ LBDEL00005383999/ LBDEL00003957237/ LBDEL00003957157	फ्री होल्ड डी.डी.ए. निर्मित फ्लैट नं. 371, दूसरी मंजिल, एमआईजी श्रेणी के अंतर्गत, पॉकेट-ए, सेक्टर-डी, शालीमार बाग में स्थित, दिल्ली- 110088 / जुलाई 22, 2024	मार्च 20, 2024 रु. 53,97,833/-	दिल्ली/ एनसीआर
4.	संतोष कुमार/अर्चना/ LBDEL00005650784	डी.डी.ए. बिल्ट-अप फ्री-होल्ड एल.आई.जी. फ्लैट बियरिंग नंबर 902, ग्राउंड फ्लोर पर, पॉकेट-डी में स्थित, लोक नायकपुरम (बक्करवाला), नई दिल्ली, दिल्ली- 110041/ जुलाई 23, 2024	मार्च 08, 2024 रु. 11,10,170/-	दिल्ली/ एनसीआर
5.	राजेश कुमार/ दीपा उपाध्याय/ LBDEL00005118029	फ्लैट नंबर 351, दूसरी मंजिल, डीडीए जनता श्रेणी के अंतर्गत, पॉकेट 6, सेक्टर 1ए फेज-1, सनराइज अपार्टमेंट, नसीरपुर, द्वारका, दिल्ली- 110045/ जुलाई 23, 2024	जनवरी 19, 2024 रु. 10,39,178/-	दिल्ली/ एनसीआर
6.	नारायण सिंह मेहरा/ सुरेंद्र सिंह/शांति देवी/ LBDEL00004554010/ LBDEL00004557200	डीडीए जनता फ्लैट नंबर 527, तीसरी मंजिल, पॉकेट-7, चरण- I, नसीरपुर, द्वारका, दिल्ली- 110045/ जुलाई 23, 2024	मार्च 23, 2024 रु. 5,96,388/-	दिल्ली/ एनसीआर

उपरोक्त कर्ज़दार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(याँ) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।

दिनांक : जुलाई 26, 2024
स्थान : दिल्ली/ एनसीआर

भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

INDAG

इंडैग रबर लिमिटेड

(सीआईएनः एल74899डीएल1978पीएलसी009038)
पंजी. कार्यालयः खेमका हाउस, 11, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली -110017
फोन : 011-26963172/73, ई-मेल आईडीः info@indagrubber.com, वेबसाइटः www.indagrubber.com

45वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं रिमोट ई-वोटिंग सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इंडैग रबर लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की पैंतालीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 16 अगस्त 2024 को दोपहर के 3.00 बजे आईएसटी, एजीएम नोटिस में सूचीबद्ध व्यवसाय निष्पादित करने हेतु, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें 26 जून, 2024 की एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए सदस्यों की एक सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना केवल ई-वोटिंग / रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा शामिल होगी जो कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुपालन में, उसके बाद परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और समय-समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्र ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 ("सेबी सर्कुलर्स") (सामूहिक रूप से "प्रासंगिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में कि जाएगी। 45वीं वार्षिक आम बैठक के लिए माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

संबंधित परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए व्याख्यात्मक विवरण और वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 25 जुलाई, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी है, जिनका नाम 19 जुलाई, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है और जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.indagrubber.com पर 'निवेशक संबंध' शीर्षक के तहत और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं और ऐसे सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

रिकॉर्ड तिथि और लाभांश

कंपनी के निदेशक मंडल ने 14 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पहले से भुगतान किए गए 0.90 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त, 2 रुपये प्रति अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2.1 रुपये का अंतिम लाभांश स्वीकृत और अनुशंसित किया है, जो वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

बोर्ड द्वारा अनुशंसित लाभांश, यदि इस वार्षिक आम बैठक में स्वीकृत हो जाता है, तो स्रोत पर कर की कटौती के अधीन, जैसा भी लागू हो, घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर, उन व्यक्तियों या उनके अधिदेशों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 16 अगस्त, 2024 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं (यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं) और उन लाभकारी स्वामियों को, जिनके नाम 9 अगस्त, 2024 को कारोबारी समय की समाप्ति पर एनएसडीएल और सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं (यदि शेयर डीमैट रूप में रखे गए हैं)।

सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 10 अगस्त, 2024 से शुक्रवार, 16 अगस्त, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

रिमोट ई-वोटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाओं का लाभ उठाया है। सदस्य कृपया कंपनी द्वारा प्राप्त दूरस्थ ई-वोटिंग सेवाओं के संबंध में नीचे नोट करें -

(i) एजीएम के नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय को रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है जो 13 अगस्त 2024 को प्रातः 9:00 बजे से प्रारंभ होकर 15 अगस्त 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।

(ii) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि 9 अगस्त 2024 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह कंपनी का ईवीएन नंबर का चयन करके रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

(iii) कोई भी व्यक्ति जिसने इलेक्ट्रॉनिक रूप में एजीएम नोटिस भेजने के बाद लेकिन 9 अगस्त 2024 की कट-ऑफ तारीख से पहले शेयर हासिल कर लिया है और कंपनी का सदस्य बन गया है, वह कंपनी के आरटीए से admin@skylinerta.com पर ई-मेल करके और एनएसडीएल से evoting.nsdl.co.in पर ई-मेल करके रिमोट ई-वोटिंग के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

(iv) जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 9 अगस्त 2024 तक कंपनी का सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

(v) 15 अगस्त 2024 को शाम 5:00 बजे के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग अक्षम कर दी जाएगी और उक्त तिथि और समय के बाद किसी भी वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) 45वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम के नोटिस में एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

(vii) वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।

(vii) एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग करने के बाद एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम में दोबारा वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ix) सदस्यों के निरीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेज एजीएम के दौरान बिना किसी शुल्क के निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे।

(x) किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं। या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013,, निर्दिष्ट ईमेल आईडी - evoting@nsdl.co.in पर जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान करेगा। सदस्य कंपनी सचिव को info@indagrubber.com पर भी लिख सकते हैं।

(xi) निदेशक मंडल ने मेसर्स कनिष्क अरोड़ा एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (सीपी संख्या 13253) के श्री कनिष्क अरोड़ा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-वोटिंग के संचालन के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है।

उक्त बैठक का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.indagrubber.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड की आज्ञानुसार
वास्ते इंडैग रबर लिमिटेड
हस्ता./-
कम्पनी सेक्रेटरी

तिथि : 25 जूलाई, 2024
स्थान : नई दिल्ली

Karnataka Bank Ltd. 100
Your Family Bank. Across India.

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा
8-बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क,
पूसा रोड
नई दिल्ली - 110060

फोनः 011-40591567 (एक्स. 240)
ईमेलः delhiarm@kbank.com
वेबसाइटः www.karnatakabank.com
सीआईएनः L85110KA1924PLC001128

अचल सम्पत्ति की बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका सांकेतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 31.07.2023 को लिया गया है, उसके उधारकर्ता/गारंटर/सह-ऑब्लिगेंट

(1) श्री भगवान गौतम पुत्र श्री किशन चंद, (2) श्रीमती किरण गौतम पत्नी श्री भगवान गौतम, दोनों (1) और (2) निवासीः 745/3, हरि नगर, जनता स्कूल के सामने, गनौर, सोनीपत, हरियाणा 131101 (3) श्री बृशन दत्त पुत्र श्री किशन चंद, मकान नं. 294-सी/14, एमसी रोड अशोक नगर, गन्नौर सोनीपत-131101, हरियाणा से सुरक्षित लेनदार कर्नाटक बैंक लिमिटेड, कुंडली शाखा, दुकान नं. 6, भूतल, बी एम कॉम्प्लेक्स, ड्रेन नं. 8 के पास, जीटी रोड, कुंडली हरियाणा 131028 की बकाया राशि रु. 56,10,233.92 (रु. छप्पन लाख दस हजार दो सौ तैंतीस और पैसे बानवे मात्र) अर्थात (i) सावधि ऋण खाता सं. 3907001600000801 के अंतर्गत रु. 17,07,844.56 दिनांक 03.07.2024 से भविष्य के ब्याज सहित, (ii) सावधि ऋण खाता सं. 3907001600003501 के अंतर्गत रु. 39,02,389.00 दिनांक 09.07.2024 से भविष्य के ब्याज तथा लागत, इत्यादि सहित की वसूली हेतु "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक **22.08.2024** को बेचा जाएगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1. संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका प्लॉट क्षेत्रफल 440 वर्ग गज अर्थात 14.5 मारला कुल 9 कनाल-14 मरला भूमि में से 29/388 हिस्सा, खेवट सं. 455//416, खाता सं. 597, रेक्ट और किला सं. 109//3(4-14) 4/1(5-0) वर्ष 2015-16 की जमाबंदी के अनुसार वर्तमान में खेवट सं. 491//455, खाता सं. 633 वर्ष 2020-21 की जमाबंदी के अनुसार जिसका आकार पूर्व से पश्चिम-75 वर्ग फीट, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम-50 फीट और पूर्व दिशा 56 फीट, हस्तांतरण विलेख सं. 607 दिनांकित 17.07.2020 और म्यूटेशन नं. 25128, मौजा गनौर, तहसील गनौर, जिला सोनीपत में स्थित, यह सम्पत्ति श्री श्री भगवान गौतम के नाम पर है।

चौहद्दीः पूरब में - योगी का प्लॉट, पश्चिम में - अन्य का प्लॉट, उत्तर में - सोनू और संजय का मकान, दक्षिण में - गली/रास्ता

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे अचल संपत्ति नहीं बेची जा सकतीः रु. 52,80,000.00 (रु. बावन लाख अस्सी हजार मात्र)

जमा/निविदा की जाने वाली बयाना राशिः रु. 5,28,000.00 (रु. पाँच लाख अट्ठाईस हजार मात्र)

2. संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका प्लॉट क्षेत्रफल 497.77 वर्ग गज अर्थात 16 मारला 4 सरसाई, कुल 9 कनाल-14 मरला भूमि में से 33/388 हिस्सा, खेवट सं. 416, खाता सं. 568, रेक्ट और किला सं. 109//3(4-14) 4/1(5-0) वर्ष 2015-16 की जमाबंदी के अनुसार वर्तमान में खेवट सं. 491//455, खाता सं. 633 वर्ष 2020-21 की जमाबंदी के अनुसार, गनौर के रेवेन्यू ईस्टेट में, तहसील गनौर, जिला सोनीपत में स्थित, यह सम्पत्ति श्री श्री भगवान गौतम के नाम पर है। यह संपत्ति मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स के खाते में सामान्य संपार्श्विक है।

चौहद्दीः पूरब में - श्री योगेश्वर त्यागी की संपत्ति, पश्चिम में - श्रीमती किरण का बचा हुआ हिस्सा उत्तर में - 17-1/2 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण में - श्रीमती कमलेश की संपत्ति

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे अचल संपत्ति नहीं बेची जा सकतीः रु. 57,24,000.00 (रु. सत्तावन लाख चौबीस हजार मात्र)

जमा/निविदा की जाने वाली बयाना राशिः रु. 5,72,400.00 (रु. पाँच लाख बहत्तर हजार चार सौ मात्र)

(उधारकर्ता/बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।)

(यह नोटिस उधारकर्ता/गारंटर को सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम-2002 के नियम (9) के उपनियम(1) के तहत नोटिस के रूप में भी कार्य करेगा)

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया कर्नाटक बैंक की वेबसाइट अर्थात **www.karnatakabank.com** में दिए गए लिंक देखें। दिनांक 22.08.2024 को मेगा ई-नीलामी के अंतर्गत

ई-नीलामी 22.08.2024 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल **https://bankauctions.in/** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को https://bankauctions.in/ पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा और ई-नीलामी (संभवतः 21.08.2024 को) मैसर्स 4क्लोजर, 605 ए, 6वीं मंजिल, मैत्रिवनम, अमीरपेट, हैदराबाद- 500038, संपर्क नं. 040-23836405, मोबाइल 8142000062, ई-मेलः info@bankauctions.in से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

दिनांकः 25.07.2024
स्थान : गनौर

कृते कर्नाटका बैंक लि.
मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी

Karnataka Bank Ltd. 100
Your Family Bank. Across India.

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा
8-बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क,
पूसा रोड
नई दिल्ली - 110060

फोनः 011-40591567 (एक्स. 240)
ईमेलः delhiarm@kbank.com
वेबसाइटः www.karnatakabank.com
सीआईएनः L85110KA1924PLC001128

अचल सम्पत्ति की बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका सांकेतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा 12.03.2023 को लिया गया है, उसके उधारकर्ता/गारंटर/सह-ऑब्लिगेंट

(1) श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री सत्येन्द्र सिंह (2) श्री सत्येन्द्र सिंह पुत्र श्री पीतम सिंह, दोनों नं. (1) और (2) का पता (क) जरुन कटरा, जरुआ, आगरा- 283102, उत्तर प्रदेश (ख) आवासीय भवन, प्लॉट नं. 03, दीक्षा एस्टेट मौजा नैनाना जाट, तहसील सदर और जिला आगरा- 282009, उत्तर प्रदेश (ग) आवासीय फ्लैट नं. 18बी, प्रथम तल, प्लॉट नं. 18, खसरा नं. 52 और 53 के भाग पर निर्मित भवन में गौरी कुंज, मौजा-रोहता, ग्वालियर रोड, तहसील सदर, जिला आगरा-282009, उत्तर प्रदेश (3) श्री लोकेश सिंह पुत्र श्री सत्येन्द्र सिंह, जरुन कटरा, जरुआ, आगरा-283102 से सुरक्षित लेनदार कर्नाटक बैंक लिमिटेड, आगरा शाखा, नं.76, हेरिटेज टावर्स, महात्मा गांधी रोड, नेहरू नगर, आगरा-282002, उत्तर प्रदेश की बकाया राशि (1) रु. 75,64,211.53 (रु. पचहत्तर लाख चौंसठ हजार दो सौ ग्यारह और पैसे तिरेपन मात्र) अर्थात (i) टर्म लोन खाता सं. 0307001800025101 के अंतर्गत रु. 58,30,492.00 दिनांक 23.07.2023 से भविष्य के ब्याज सहित (ii) पीएस टर्म लोन खाता सं. 0307001800006601 के अंतर्गत रु. 17,33,719.53 दिनांक 21.07.2023 से भविष्य के ब्याज, लागत इत्यादि सहित की वसूली हेतु (2) उधारकर्ता/गारंटर/सह-ऑब्लिगेंट मैसर्स फौजदार एंटरप्राइजेज, जिसका प्रतिनिधित्व इसकी प्रोप्राइटर श्रीमती कमलेश देवी द्वारा, पताः गांव और पोस्ट जरुआ कटरा आगरा -283102, उत्तर प्रदेश (2) श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री सत्येंद्र सिंह (3) श्री सत्येंद्र सिंह पुत्र श्री पीतम सिंह, दोनों नं. (2) और (3) का पता जरुआ कटरा, आगरा-283102, उत्तर प्रदेश से सुरक्षित लेनदार कर्नाटक बैंक लिमिटेड, आगरा शाखा, नं.76, हेरिटेज टावर्स, महात्मा गांधी रोड, नेहरू नगर, आगरा-282002, उत्तर प्रदेश की बकाया राशि (1) रु. 43,06,152.70 (रु. तैंतालीस लाख छह हजार एक सौ बावन और पैसे सत्तर मात्र) अर्थात (i) पीएस ओवरड्राफ्ट ऋण खाता सं. 0307000600014201 के अंतर्गत रु. 23,65,059.00 दिनांक 01.07.2024 से भविष्य का ब्याज सहित, (ii) पीएस सावधि ऋण खाता सं. 0307001800007201 के अंतर्गत रु. 9,82,224.64 दिनांक 15.07.2024 से भविष्य का ब्याज सहित (iii) पीएस सावधि ऋण खाता सं. 0307001800007901 के अंतर्गत रु. 6,02,367.06 दिनांक 11.07.2024 से भविष्य का ब्याज सहित (iv) पीएस टर्म लोन खाता सं. 0307001800008401 के अंतर्गत रु. 3,56,502.00 दिनांक 17.07.2024 से भविष्य का ब्याज, लागत इत्यादि सहित की वसूली हेतु "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक **28.08.2024** को बेचा जाएगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति नं. 1 : संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी प्लॉट नं. 03, दीक्षा एस्टेट, क्षेत्रफल 133.45 वर्ग मी., खसरा नं. 74 का हिस्सा, उस पर बनी इमारत सहित मौजा नैनाना जाट, तहसील सदर और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित, श्रीमती कमलेश देवी से संबंधित,

चौहद्दीः पूरब में - प्लॉट नं. 4, पश्चिम में - प्लॉट नं. 2, उत्तर में - 9.0 मी. चौड़ी रोड, दक्षिण में - अन्य की संपत्ति

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे अचल संपत्ति नहीं बेची जा सकतीः रु. 73,56,335/- (रु. तिहत्तर लाख छप्पन हजार तीन सौ पैंतीस मात्र)

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे अचल संपत्ति नहीं बेची जा सकतीः रु. 52,80,000.00 (रु. बावन लाख अस्सी हजार मात्र)

जमा/निविदा की जाने वाली बयाना राशिः रु. 7,35,633.50 (रु. सात लाख पैंतीस हजार छः सौ तैंतीस और पैसे पचास मात्र)

सम्पत्ति नं. 2 : संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट नं. 18बी, प्रथम तल, क्षेत्रफल 50.14 वर्ग मी., निर्मित भवन में प्लॉट सं. 18, खसरा सं. 52 और 53 का भाग, गौरी कुंज, मौजा-रोहता, ग्वालियर रोड, तहसील सदर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, श्रीमती कमलेश देवी से संबंधित चौहद्दीः पूरब में - अन्य की संपत्ति, पश्चिम में - 9.00 चौड़ी सड़क, उत्तर में - सम्पत्ति सं. बी-17 एफ.एफ दक्षिण में - **सम्पत्ति सं. बी-19 एफ.एफ**

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे अचल संपत्ति नहीं बेची जा सकतीः रु. 20,71,000.00 (रु. बीस लाख इकत्तर हजार मात्र)

जमा/निविदा की जाने वाली बयाना राशिः रु. 2,07,100.00 (रु. दो लाख सात हजार एक सौ मात्र)

(उधारकर्ता/बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।)

(यह नोटिस उधारकर्ता/गारंटर को सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम-2002 के नियम (8) के उपनियम(6) के तहत नोटिस के रूप में भी कार्य करेगा)

बिक्री की विस्तृत शर्तों व नियमों के लिए कृपया कर्नाटक बैंक की वेबसाइट **www.karnatakabank.com** पर "बिक्री हेतु बंधक परिसंपत्तियां" के अंतर्गत दिए गए लिंक को देखें।

ई-नीलामी 28.08.2024 को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल **https://bankauctions.in/** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को https://bankauctions.in/ पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा और ई-नीलामी (संभवतः 27.08.2024 को) मैसर्स 4क्लोजर, 605 ए, 6वीं मंजिल, मैत्रिवनम, अमीरपेट, हैदराबाद- 500038, संपर्क नं. 040-23836405, मोबाइल 8142000809, ई-मेलः info@bankauctions.in से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

दिनांकः 25.07.2024
स्थान : आगरा

कृते कर्नाटका बैंक लि.
मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी

अंकिता व्यक्तिगत स्पर्धा में 11वें स्थान पर, महिला टीम क्वार्टरफाइनल में

पेरिस। (भाषा)

पदार्पण कर रही तीरंदाज अंकिता भकत ने बृहस्पतिवार को यहां अनुभवी दीपिका कुमारी को पीछे छोड़ते हुए पेरिस ओलंपिक महिला व्यक्तिगत रिकर्व क्वालीफिकेशन में भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ 11वां स्थान हासिल किया, इससे देश ने चौथे स्थान पर रहकर टीम स्पर्धा में क्वार्टरफाइनल स्थान हासिल किया। अंकिता (26 साल) 666 अंक से भारतीय महिला तीरंदाजों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर रहीं, उनके बाद भजन कौर 559 अंक से 22वें और दीपिका कुमारी 658 अंक से 23वें स्थान पर रहीं। टीम स्पर्धा में भारत ने 1983 अंक से चौथा स्थान हासिल किया जिसमें दक्षिण कोरिया 2046 अंक से शीर्ष पर रहा। चीन उप विजेता जबकि मेक्सिको तीसरे स्थान पर रहा। टीम तालिका में शीर्ष चार टीम सीधे क्वार्टरफाइनल के लिए क्वालीफाई करती हैं जबकि पांचवें से 12वें स्थान पर रहने वाली टीम राउंड 16 मुकाबले खेलेंगी।भारत का सामना क्वार्टरफाइनल में फ्रांस और नीदरलैंड के बीच मुकाबले के विजेता से होगा। अगर भारतीय महिला टीम क्वार्टरफाइनल की बाधा पार कर लेती है तो उसे सेमीफाइनल में मजबूत कोरियाई टीम से भिड़ना पड़ सकता है।कोरियाई टीम ओलंपिक में अपराजेय रही है, उसने तीन साल पहले तोक्यो में लगातार नौवां पदक जीता था। व्यक्तिगत वर्ग में कोरिया की लिम सिहयिओन ने 694 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर से तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया जबकि उनकी हमवतन सुहियोन नाम 688 अंक से दूसरे स्थन पर रहीं। चीन की यांग जियाओलेई 673 अंक से तीसरे स्थान पर रहीं। दीपिका पहली बार मिश्रित टीम स्पर्धा में नहीं खेलेंगी क्योंकि अंकिता भारतीयों में शीर्ष पर रहीं। अंकिता पुरुष क्वालीफिकेशन में शीर्ष पर रहने वाले तीरंदाज के साथ मिश्रित टीम फाइनल्स में जोड़ी बनाएंगी। पुरुष क्वालीफायर दोपहर के सत्र में शुरू होंगे।

स्पेन की जीत से शुरुआत, अर्जेंटीना पहला मैच हारा

पेरिस।एपी यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने उज्बेकिस्तान को 2-। से हराकर ओलंपिक खेलों की फुटबॉल प्रतियोगिता में अपने अभियान की सकारात्मक शुरुआत की लेकिन लियोनेल मेस्सी के बिना खेल रहे विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा।

उज्बेकिस्तान ने स्पेन को कड़ी चुनौती दी और इसलिए दर्शकों का उन्हें भरपूर समर्थन भी मिला। पेरिस ओलंपिक खेलों का पहला गोल स्पेन के राइट बैक मार्क पबिल ने 29वें मिनट में किया। एल्डोर शोमुरोदोव ने पहले हाफ के आखिर में पेनल्टी के ज़रिए अपना 41वां अंतरराष्ट्रीय गोल करके बराबरी की, जिसका उज्बेकिस्तान के प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया। स्पेन की तरफ से सर्जियो गोमेज ने 62वें मिनट में निर्णायक गोल किया।इन खेलों में मेस्सी के बिना खेल रहे कोपा अमेरिका चैंपियन अर्जेंटीना को अपने पहले मैच में मोरक्को से 2-। से हार झेलनी पड़ी। मोरक्को की तरफ से दोनों गोल स्ट्राइकर सौफ़्याने रहीमी ने किए। मोरक्को की जीत जब सुनिश्चित लग रही थी तब अर्जेंटीना की तरफ से दूसरे हाथ के इंजरी टाइम मे क्रिस्टियन मदीना ने बराबरी का गोल कर दिया। मोरक्को के प्रशंसक मैदान पर उतर आए जिससे खेल खत्म होने से कुछ समय पहले मैच स्थगित कर दिया गया। इसके बाद 2 घंटे तक खेल रुका रहा और जब खेल शुरू हुआ तो उससे कुछ देर पहले वीडियो प्रणाली से अर्जेंटीना का गोल ऑफ साइड होने के कारण अमान्य करार दे दिया गया। अन्य मैचों में इजरायल ने कड़ी सुरक्षा के बीच खेले गए मैच में माली को।-। से बराबरी पर रोका जबकि मेजबान फ्रांस ने अमेरिका को 3-। से हराया।

दूसरे दौर में भिड़ सकते हैं जोकोविच और नडाल

पेरिस।(एपी) शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच पेरिस ओलंपिक खेलो की टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल के दूसरे दौर मे अपने चिर प्रतिद्वंद्वी राफेल नडाल से भिड़ सकते है। गुरुवार को जारी किए गए ड्रॉ के अनुसार जोकोविच अपने अभियान की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के खिलाफ करेंगे जबकि नडाल का सामना हंगरी के मार्टन फुक्सोविक्स से होगा। इन मैच मे जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी दूसरे दौर मे एक दूसरे का सामना करेंगे।ओलंपिक की टेनिस प्रतियोगिता उसी स्थल पर खेली जाएगी जहां फ्रेंच ओपन होता है। नडाल ने अपने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब मे से 14 खिताब फ्रेंच ओपन केरूप मे जीते है। उन्होने 2008 मे बीजिंग मे एकल जबकि 2016 मे रियो मे मार्क लोपेज के साथ मिलकर युगल वर्ग मे स्वर्ण पदक जीता था।फ्रेंच ओपन चैंपियन कार्लोस अल्कराज़ का सामना पहले दौर मे लेबनान के खिलाड़ी हैदी हबीब से होगा।महिलाओ के वर्ग मे पोलैड की शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा स्वियातेक पहले दौर मे रोमानिया की इरिना कैमेलिा बेगू से भिड़ेगी जबकि अमेरिका की दूसरी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ का सामना ऑस्ट्रेलिया की अजला टॉमलजानोविच से होगा।

एंडी मरे ओलंपिक टेनिस एकल से हटे, पेरिस में सिर्फ युगल में खेलेंगे

पेरिस। (एपी) दो बार के ओलंपिक टेनिस स्वर्ण पदक विजेता एंडी मरे ने गुरुवार को पेरिस खेलो की एकल स्पर्धा से हटने का फैसला किया और वह डैन इवांस के साथ केवल युगल स्पर्धा मे हिस्सा लेगे। ब्रिटेन के 37 साल के मरे ने कहा कि ओलंपिक उनके करियर का अंतिम टूर्नामेंट होगे। उन्होने इस महीने विम्बलडन की एकल स्पर्धा से भी हटने का फैसला किया था और युगल स्पर्धा मे भी अपने बड़े भाई जैमी के साथ एक ही मैच खेला था।मरे ने गुरुवार को कहा, मैंने डैन के साथ युगल स्पर्धा पर ध्यान लगाने के लिए एकल से हटने का फैसला किया।

पहले मैच में ब्रिटेन की हर्से से और शरत कमल स्लोवेनिया के कोजुल से भिड़ेंगे

पेरिस। भारत की शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता मनिका बत्रा महिला एकल के शुरूआती दौर में ब्रिटेन की अन्ना हर्से से भिड़ेंगी जबकि अनुभवी पुरुष खिलाड़ी अचंता शरत कमल स्लोवेनिया के डेनी कोजुल के सामने होंगे। बुधवार को ड्रा की घोषणा हुई। मनिका को 18वीं वरीयता मिली है और यह उनका लगातार तीसरा ओलंपिक है। वह 2021 तोक्यो ओलंपिक में एकल में राउंड 32 में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी थीं। पुरुष एकल में हरमीत देसाई का सामना पहले दौर में जोर्डन के अबो यमन से होगा जबकि 25 साल की श्रीजा अकुला (16वीं वरीय) महिला वर्ग में स्वीडन की खिलाड़ी क्रिस्टिना कालबर्ग के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। राष्ट्रमंडल खेलों के चैम्पियन शरत कमल भारत के टेबल टेनिस दल की अगुआई कर रहे हैं जिसमें 41 साल का यह खिलाड़ी ओलंपिक में पांचवीं दफा खेलने उतरेगा।

भारत तैयार, इस बार दहाई के पार

भाषा। पेरिस

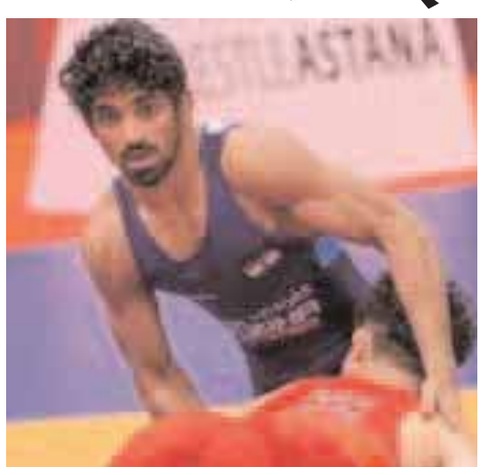

मंच सज चुका है और दुनिया भर के खिलाड़ियों की तरह भारत के 117 खिलाड़ी भी शुक्रवार से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं जहां उनका लक्ष्य पदकों की संख्या को दोहरे अंक में पहुंचाना होगा। भारत ने तोक्यो ओलंपिक में सात पदक जीते थे जो उसका ओलंपिक खेलों में अभी तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और भारतीय खिलाड़ी इसमें सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भले ही उन पर इसके लिए अपेक्षाओं का बोझ भी है लेकिन कुश्ती को छोड़कर किसी भी अन्य खेल के खिलाड़ी अपनी तैयारी को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं कर सकते हैं।

खिलाड़ियों को चाहे विदेश में अभ्यास करवाना हो या उन्हें सर्वश्रेष्ठ सुविधा उपलब्ध करानी हो, किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और अब परिणाम देना खिलाड़ियों का काम है। लेकिन इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि तोक्यो ओलंपिक के सात पदकों की संख्या की बराबरी करना भी आसान नहीं होगा क्योंकि भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को छोड़कर कोई भी अन्य खिलाड़ी पदक का प्रबल दावेदार नहीं है। भारत के 117 सदस्यों के दल में तीन खेलों एथलेटिक्स (29), निशानेबाजी (21) और हॉकी (19) के आधे खिलाड़ी शामिल हैं। इन 69 खिलाड़ियों में से 40 खिलाड़ी पहली बार ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। अन्य खेलों में भी कमोबेश यही स्थिति है और इस तरह से देखा जाए तो भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पदार्पण करने वाले खिलाड़ियों पर होगी। भारतीय दल में हालांकि कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्हें अपना खेल का स्तर बढ़ाना होगा। इन खिलाड़ियों में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, टेबल टेनिस के दिग्गज शरत कमल और हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश भी शामिल हैं जो निश्चित तौर पर अपना अंतिम ओलंपिक खेल रहे हैं। हॉकी टीम की ओलंपिक खेलों से पहले फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही जबकि मुक्केबाजों और पहलवानों को प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करने का कम मौका मिला। निशानेबाजों ने भी ओलंपिक से पहले मिश्रित परिणाम हासिल किए। ट्रैक और फील्ड एथलीटों, विशेषकर अविनाश साबले ने हाल में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अपने वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में उनका प्रदर्शन उन्हें पदक के दावेदारों में शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं लगता है। स्टीपलचेज़र साबले लगातार अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को बेहतर कर रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 8:09.94 है, लेकिन सात अंतरराष्ट्रीय धावक हैं जिन्होंने उनसे बेहतर समय निकाला है। ऐसे में उनका फाइनल में पहुंचना भी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। भारत की पदक की उम्मीदें नीरज तथा चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी की फॉर्म में चल रही बैडमिंटन जोड़ी पर टिकी हैं। नीरज भले ही अभी तक 90 मीटर की दूरी तक भाला नहीं फेक पाए हैं लेकिन उन्होंने निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया है। बड़ी प्रतियोगिताओं में वह अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं और उनके पास लगातार दो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाला तीसरा भारतीय खिलाड़ी बनने का शानदार मौका है। इससे पहले पहलवान सुशील कुमार (2008 और 2012) तथा सिंधु (2016 और 2021) ही यह उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। सात्विक और चिराग की जोड़ी जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन कर रही है उसे देखते हुए वह निश्चित तौर पर पदक की प्रबल दावेदार है। सिंधु भी लगातार तीसरा पदक जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी हाल की फॉर्म अच्छी नहीं रही और उन्हें मुश्किल ड्रॉ भी मिला है। हॉकी में भारत में पिछले ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीत कर 41 वर्ष के लंबे इंतजार को खत्म किया था लेकिन हाल में टीम के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव रहा है। पेनल्टी कार्नर को गोल में बदलना और लय बनाए रखना टीम की सबसे बड़ी चिंता है।यही नहीं भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और आयरलैंड के साथ मुश्किल ग्रुप में रखा गया है। ऐसे में टीम को छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है।। निशानेबाजी में भारत के 21 खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे जिनमें मनु भाकर और सौरभ चौधरी भी शामिल हैं जिन्हें पदक का दावेदार माना जा रहा है। इनके अलावा सिफत कौर समारा (50 मीटर थ्री पोजिशन), संदीप सिंह (10 मीटर एयर राइफल) और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (पुरुषों की 50 मीटर राइफल) ने भी निशानेबाजी में पदक का 12 साल का इंतजार खत्म करने का माद्दा दिखाया है। वर्तमान में भारतीय दल के प्रमुख गगन नारंग 2012 लंदन खेलों में 10 मीटर एयर राइफल कांस्य पदक जीतकर पोडियम पर पहुंचने वाले आखिरी भारतीय निशानेबाज थे। कुश्ती में भारत ने पिछले चार ओलंपिक खेलों में पदक जीता है लेकिन इस बार भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण खिलाड़ियों की तैयारी अनुकूल नहीं रही हैं। इसके बावजूद अंशु मलिक, अंतिम पंघाल और अमन सहरावत को भारत का सबसे अच्छा दावेदार माना जा रहा है। अंडर-23 विश्व चैंपियन रीतिका हुड्डा भी छुपी रुस्तम साबित हो सकती है। अन्य खेलों में तीरंदाजी और टेबल टेनिस के खिलाड़ियों ने अपनी रैंकिंग के आधार पर खेलों में जगह बनाई है। तीरंदाजी में भारत लगातार ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा है लेकिन उसे अभी अपने पहले पदक का इंतजार है। पिछले ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू पिछले कुछ समय से चोट और खराब फॉर्म से जूझ रही हैं। मुक्केबाजी में निकहत जरीन और निशांत देव से उम्मीद की जा सकती है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अभी तक कुल 35 पदक जीते हैं। इनमें निशानेबाज अभिनव बिंद्रा (2008) और नीरज चोपड़ा (2021) ही व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीत पाए हैं।

पदकों की हैट्रिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं पीवी सिंधु

पेरिस। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु लगातार तीसरे ओलंपिक खेलो मे पदक जीतकर इतिहास रचने के लिए किसी भी तरह की कसर नही छोड़ रही है और उन्होने अपना यह लक्ष्य हासिल करने के लिए पिछले कुछ महीनो मे अलग-अलग तरीको से कड़ा अभ्यास किया है। सिंधु ने रियो ओलंपिक मे रजत और तोक्यो ओलंपिक मे कांस्य पदक जीता था। अगर वह पेरिस ओलंपिक मे पोडियम पर पहुंचने मे सफल रहती है तो फिर वह पदको की हैट्रिक पूरी करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन जाएंगी। सिंधु पिछले कुछ समय से अच्छी फॉर्म मे नही चल रही है लेकिन उन्होने कहा कि पिछले आठ महीने प्रकाश पादुकोण के साथ बिताने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वह लगातार तीसरा पदक जीतने के लिए तैयार है। सिंधु ने पोर्ट डे ला चैपल एरिना मे अभ्यास सत्र के बाद कहा, निश्चित रूप से पदक जीतना मेरा लक्ष्य है। यह पहला हो या दूसरा या फिर तीसरा यह मायने नही रखता। मैंने दो पदक जीते है और मै तीसरे पदक के बारे मे सोच कर खुद पर दबाव नही बनना चाहती हूं। उन्होने कहा, जब भी मै ओलंपिक मे भाग लेती हूं तो वह मेरे लिए नया ओलंपिक होता है। इसलिए मै जब भी ओलंपिक मे खेलने के लिए उतरती हूं तो मेरा लक्ष्य पदक जीतना होता है।

आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने गोलों की क्लिप देखता हूं : सुखजीत

नई दिल्ली। दो साल पहले भारतीय हॉकी टीम में पदार्पण करने वाले फॉरवर्ड सुखजीत सिंह पेरिस में ओलंपिक में पदार्पण को लेकर कतई नर्वस नहीं है और आत्मविश्वास बढाने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय गोलों की क्लिप देखते रहते हैं। सुखजीत भारतीय टीम में शामिल उन पांच खिलाड़ियों (अभिषेक, राजकुमार पाल, जरमनप्रीत सिंह, संजय) में से हैं जिनके लिए पेरिस उनका पहला ओलंपिक होगा। तोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। पंजाब के तरण तारण में जन्मे सुखजीत ने खानगी से पहले भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा , मैंने 2022 में भारतीय टीम में पदार्पण किया और एफआईएच प्रो लीग में स्पेन के खिलाफ पदार्पण मैच में ही गोल किया था। अब तक का सफर अच्छा रहा है और हर मैच में सर्वश्रेष्ठ करने की ही कोशिश रहती है। अब तक 70 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 22 गोल कर चुके सुखजीत ने कहा कि वह ओलंपिक के दबाव का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं।उन्होंने कहा , मुझे दबाव बिल्कुल नहीं लग रहा। हमने बड़े टूर्नामेंट खेले हैं तो दबाव का सामना करना बखूबी आता है। अपनी तैयारियों के दम पर बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा खेलने का यकीन है।

एआईसीएफ के पूर्व प्रमुख संजय कपूर फिडे भारत क्षेत्र के अध्यक्ष चुने गए

नई दिल्ली। (भाषा) अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के पूर्व प्रमुख संजय कपूर को सर्वसम्मति से बृहस्पतिवार को फिडे भारत क्षेत्र का अध्यक्ष चुना गया। देश में खेल की शीर्ष संस्था ने यह जानकारी दी। अहमदाबाद में एआईसीएफ की आम सालाना बैठक (एजीएम) के दौरान यह घोषणा की गई। कपूर को चार साल के लिए क्षेत्र का अध्यक्ष चुना गया और फिडे अध्यक्ष अरकाडी दवोरकोविच ने उन्हें बधाई दी। कपूर की नई भूमिका भारत में शतरंज प्रशासन के लिए अहम पल है जिसमें उन्हें वैश्विक स्तर पर खेल के विकास और प्रगति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति पर कपूर ने कहा, फिडे भारत क्षेत्र का अध्यक्ष चुना जाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है।

तुषारा चोट के कारण भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला से बाहर

पालेकल। (भाषा) श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषारा अभ्यास के दौरान हाथ में चोट लगने के कारण भारत के खिलाफ तीन मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। इस 29 वर्षीय खिलाड़ी के बुधवार को अभ्यास सत्र के दौरान बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। श्रीलंका ने तुषारा की जगह एक अन्य तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को टीम में शामिल किया है।

सीन नदी पर ओलंपिक उद्घाटन के दौरान हो सकती है बारिश

पेरिस। (एपी) सीन नदी पर पेरिस ओलपिक के अनूठे उद्घाटन समारोह के दौरान मौसम की गाज गिर सकती है क्योंकि मौसम विभाग ने शुक्रवार को बारिश का अनुमान जताया है। फ्रांस के मौसम विभाग मेटियो फ्रांस ने शुक्रवार की सुबह बारिश की भविष्यवाणी की है। दोपहर को मौसम साफ रहेगा लेकिन शाम को बारिश हो सकती है जिस समय उद्घाटन समारोह होना है। बारिश होने पर भी उद्घाटन समारोह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा।

बांग्लादेश के खिलाफ भारत प्रबल दावेदार

महिला एशिया कप सेमीफाइनल

दाम्बुला। (भाषा) भारतीय महिला क्रिकेट टीम शुक्रवार को यहां एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ जीत की प्रबल दावेदार के तौर पर मैदान में उतरेगी जिसमें शेफाली वर्मा की निगाहें आक्रामक प्रदर्शन करने पर लगी होंगी जबकि स्मृति मंधाना भी बड़ा स्कोर बनाने के लिए बेताब होंगी। शेफाली ने अभी तक 158 रन बनाए हैं जिससे वह टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। निगार सुल्ताना की टीम के खिलाफ शेफाली को अच्छी शुरूआत करानी होगी क्योंकि विपक्षी टीम के पास धीमी गति के गेंदबाजों की भरमार है।

भारतीय महिला टीम ने सभी तीनों मुकाबलों में प्रतिद्वंद्वी टीम को मात दी है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ सात विकेट से, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ 78 रन से और नेपाल के खिलाफ 82 रन के अंतर से जीत हासिल की। हालांकि कप्तान हरमनप्रीत कौर जानती हैं कि एशिया कप में सेमीफाइनल और फाइनल ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए बांग्लादेश की टीम टूर्नामेंट के इस चरण में खतरनाक टीम हो सकती है। भारत के लिए शुरुआत काफी अहम होगी इसलिए शेफाली चाहेंगी कि उनकी सीनियर सलामी जोड़ीदार मंधाना भी अच्छा प्रदर्शन करें। बाएं हाथ की यह खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ 45 रन की पारी के दौरान शानदार फॉर्म में थी। ग्रुप लीग चरण में भारतीय टीम यूएई और नेपाल से भिड़ी थी।

टी20 श्रृंखला:पंत और सैमसन में से एक का चयन बड़ी चुनौती

कोलंबो। (भाषा) भारतीय क्रिकेट टीम के नवनियुक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर के लिए श्रीलंका के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू होने वाले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से किसी एक का चयन करना चुनौतीपूर्ण होगा। छोटे प्रारूप से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली को छोड़कर टी20 विश्व कप विजेता टीम के अधिकतर खिलाड़ी श्रीलंका दौरे पर आए हैं और ऐसे में पंत और सैमसन में से किसी एक का चयन करना आसान नहीं होगा क्योंकि यह दोनों ही आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में भले ही दो स्थान खाली हैं लेकिन फिर भी इन दोनों में से किसी एक को बल्लेबाज के रूप में उतारना भी आसान नहीं होगा। पंत ने टी20 विश्व कप में 171 रन बनाए जबकि सैमसन को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला जबकि वह टीम का हिस्सा थे। भारत और श्रीलंका के बीच यह श्रृंखला भारतीय टीम के लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन गई है क्योंकि गंभीर की मुख्य कोच के रूप में यह पहली श्रृंखला है जबकि टीम के नए कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। गंभीर के पिछले रिकार्ड को देखते हैं तो यह निश्चित है कि टीम संयोजन में उनकी बात को अधिक तवज्जो दी जाएगी। पंत जब दिसंबर 2022 में कार दुर्घटना में घायल होने के बाद टीम से बाहर थे तब विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन, सैमसन, जितेश शर्मा और ध्रुव जुरेल को आजमाया गया। अगर पंत और सैमसन के आंकड़ों पर गौर करें तो वह काफी हद तक समान नजर आते हैं। सैमसन ने अभी तक 28 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 133 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इनमें से 27 मैच उन्होंने 2020 के बाद खेले हैं जबकि उन्होंने 2015 में इस प्रारूप में पदार्पण कर लिया था।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ए, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा द इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड,ए-8, सेक्टर-7, जिला-गौतमबुद्ध नगर, नोएडा (उ.प्र.)-201301, दूरभाष-01202470700 से मुद्रित। प्रधान संपादक : शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। मुख्य व्यवसायिक कार्यालय- 201-205 द्वितीय मंज़िल, प्रताप भवन, 5 ,बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष:011-69342500।